



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]

No. 134]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 3, 2009/भाद्रपद 12, 1931

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 3, 2009/SRAVANA 12, 1931

गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

गुडगाँव, 30 जुलाई, 2009

सं. जेईआरसी-01/2009.—गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय 1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार

- (i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2009 है।
- (ii) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- (iii) ये विनियम संपूर्ण गोवा राज्य तथा अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा तथा नागर हवेली, दमन तथा दीव, लक्षद्वीप तथा पुद्दुचेरी पर विस्तारित होंगे।

2. परिभाषाएं

- (i) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है;
 - (ख) "अध्यक्ष" से आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "आयोग" से गोवा राज्य तथा अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा तथा नागर हवेली, दमन तथा दीव, लक्षद्वीप तथा पुडुच्चेरी के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "बैठक" से अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा समय-समय पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में हुई सुनवाई, बैठकें, विचार-विमर्श, वाद-विवाद, जाँच, अन्वेषण, परामर्श अभिप्रेत है ;

(ङ.) "अधिकारी" से आयोग का अधिकारी अभिप्रेत है ;

(च) "याचिका" से सभी याचिकाएं, आवेदन, परिवाद, अपीलें, उत्तर, प्रत्युत्तर, अनुपूरक अभिवचन, अन्य कागज-पत्र तथा दस्तावेज अभिप्रेत तथा सम्मिलित हैं ;

(छ) "प्राप्तकर्ता अधिकारी" से याचिका प्राप्त करने के लिए आयोग द्वारा पदाभिहित अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ज) "कार्यवाही" से वे सभी प्रकार की कार्यवाहियां अभिप्रेत तथा सम्मिलित हैं जिन्हें आयोग अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्य के निर्वहन में कर सकेगा ;

(झ) "विनियम" से ये विनियम अभिप्रेत हैं ;

(ञ) "सचिव" से आयोग का सचिव अभिप्रेत है; तथा

(ट) "यू टी" से संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है ।

(ii) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो यहां परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में है ।

3. आयोग का कार्यालय, कार्यालय समय तथा बैठकें

(i) आयोग का मुख्यालय ऐसे अन्य स्थान पर अवस्थित होगा जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चय किया जाए, इस समय आयोग का मुख्यालय गुड़गांव, हरियाणा में अवस्थित है ।

(ii) जब तक अन्यथा निदेश न दिया जाए, आयोग का मुख्यालय तथा अन्य कार्यालय शनिवार, रविवार तथा केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अवकाशों के सिवाय प्रतिदिन खुले रहेंगे ।

(iii) आयोग का मुख्यालय तथा अन्य कार्यालय ऐसे समय तक खुले रहेंगे जैसा आयोग द्वारा समय-समय पर निदेश दिया जाए । इस समय आयोग का कार्य समय प्रातः 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक होगा, जिसमें 1.30 अपराह्न से 2.00 बजे अपराह्न तक भोजनावकाश होगा ।

(iv) जहां कोई अंतिम कार्यदिवस ऐसे दिन पड़ता है जिसको आयोग का कार्यालय बंद रहता है तथा इस कारण उस दिन कोई कार्य नहीं किया जा सकता है तो वहां वह कार्य अगले कार्यदिवस को किया जाएगा जिस दिन कार्यालय खुलता है ।

(v) आयोग मामलों की सुनवाई के लिए बैठकें मुख्यालय तथा ऐसे अन्य स्थान, दिन तथा समय पर कर सकेगा जैसा अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया जाए ।

4. आयोग की भाषा

(i) जब तक आयोग के आदेश द्वारा अन्यथा अनुज्ञात न किया जाए, आयोग की कार्यवाहियां अंग्रेज़ी/हिंदी या क्रमिक संघ राज्यक्षेत्रों के लिए भारत सरकार तथा गोवा राज्य के लिए उनके शासकीय कारबार के संचालन हेतु गोवा सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य भाषा में संचालित की जाएंगी ।

(ii) उपरोक्त उप-विनियम (i) में विनिर्दिष्ट के सिवाय, आयोग द्वारा किसी अन्य भाषा में याचिका, दस्तावेज तथा अन्य सामग्री स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि उसके साथ उसका अनुवाद संलग्न न हो ।

(iii) कोई भी अनुवाद जिसके लिए कार्यवाही के पक्षकारों द्वारा सहमति दी जाती है या कोई भी पक्षकार उस व्यक्ति का, जिसके द्वारा मान्यताप्राप्त भाषा में अनुवाद किया गया था, अधिप्रमाणिकता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाता है तो आयोग द्वारा उसे सही अनुवाद के रूप में स्वीकार किया जाएगा ।

(iv) आयोग, समुचित मामलों में, याचिकाओं, अभिवचनों, दस्तावेजों तथा अन्य सामग्री के अंग्रेज़ी अनुवाद के प्रयोजन के लिए आयोग पदाभिहित किसी अधिकारी या व्यक्ति को इसके अनुवाद के लिए निदेश दे सकेगा ।

5. आयोग की मुद्रा

- (i) आयोग की एक पृथक् मुद्रा होगी जिसमें यह उपदर्शित होगा कि यह आयोग की मुद्रा है ।
- (ii) मुद्रा की डिजाइन निम्नानुसार होगी ।
- (iii) आयोग द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश या की गई संसूचना, जारी नोटिस या प्रमाणित प्रति को आयोग की मुद्रा से स्टांपित किया जाएगा तथा सचिव या उस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे ।

6. आयोग के अधिकारी**(i) नियुक्तियां**

- (क) आयोग को विभिन्न कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, सचिव, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने की शक्ति होगी, वह ऐसे अधिनियम में अधिकथित प्रक्रिया के अनुरूप अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए अर्हताएं, अनुभव तथा अन्य निबंधन तथा शर्तों को भी विहित कर सकेगा ।
- (ख) आयोग अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आयोग को सहयोग देने के लिए परामर्शियों की नियुक्ति कर सकेगा ।

(ii) सचिव

- (क) सचिव अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।
- (ख) आयोग अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने में सचिव से ऐसी सहायता ले सकेगा जो वह उचित समझें ।

(iii) उपरोक्त उपबंधों की व्यापकता पर विशिष्टतया तथा प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सचिव को निम्नलिखित शक्तियां होंगी तथा वह निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :-

- (क) वह आयोग के अभिलेख तथा मुद्रा की अभिरक्षा करेगा;
- (ख) वह आयोग से संबंधित सभी याचिकाओं, आवेदनों या संदर्भों को प्राप्त करेगा या करवाएगा;
- (ग) वह इस संबंध में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आयोग को उसके समक्ष के प्रत्येक मामले में विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी अभिवचनों का संक्षेप तथा सारांश तैयार करेगा या करवाएगा ।
- (घ) वह आयोग द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों से संबंधित कार्यवाहियों में आयोग को सहायता देगा ।
- (ङ) वह आयोग द्वारा पारित आदेशों को अधिप्रमाणित करेगा;
- (च) वह आयोग द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा ।
- (छ) उसे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार/गोवा प्रशासन/संघ राज्यक्षेत्रों या अन्य कार्यालयों, कंपनियों तथा फर्मों या किसी अन्य पक्षकार से, जैसा आयोग द्वारा निदेश दिया जाए, ऐसी जानकारी एकत्रित करने का अधिकार होगा जो अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए उपयोगी समझे जाएं तथा आयोग के समक्ष जानकारी को प्रस्तुत करेगा ।

7. शक्तियों का प्रत्यायोजन

- (i) आयोग, अपने अधिकारियों को, ऐसे कृत्य, जिसमें विनियमों द्वारा सचिव द्वारा प्रयोक्तव्य अपेक्षित कृत्य भी सम्मिलित हैं, ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर प्रत्यायोजित कर सकेगा जो आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किए जाएं ।
- (ii) सचिव की अनुपस्थिति में, आयोग का ऐसा कोई अन्य अधिकारी, जिसे आयोग द्वारा पदाभिहित किया जाए, सचिव के सभी कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा ।

(iii) आयोग को हर समय यह प्राधिकार होगा कि वह किसी भी समय या तो किसी हितबद्ध या प्रभावित पक्षकार से प्राप्त आवेदन पर या स्व-प्रेरणा से आयोग के सचिव या अधिकारियों द्वारा किए गए आदेश या की गई कार्रवाई का पुनर्विलोकन, प्रतिसंहरण, पुनरीक्षण, उपांतरण, संशोधन, परिवर्धन या अन्यथा परिवर्तन कर सकेगा यदि आयोग ऐसा करना समुचित समझे ।

8. उपभोक्ता संगमों तथा अन्यो की भागीदारी

(i) आयोग किसी भी संगम/फोरम या निगमित निकायों या उपभोक्ताओं के किसी समूह को आयोग के समक्ष ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर भाग लेने की अनुज्ञा देगा जिसके बारे में आयोग समुचित समझे ।

(ii) आयोग कार्यवाहियों को समय पर पूरा करने की दृष्टि से, ऊपर निर्दिष्ट संगमों/समूहों/फोरमों को सामूहिक रूप से अपनी-अपनी याचिकाओं/शपथ-पत्रों को प्रस्तुत करने हेतु एकत्रित होने के लिए निदेश देने हेतु स्वतंत्र होगा ।

(iii) आयोग जब कभी वह उचित समझे संगमों, समूहों, फोरमों या निगमित निकायों को आयोग के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता संगम के रूप में मान्यता देने हेतु प्रक्रिया अधिसूचित कर सकेगा ।

(iv) आयोग, यदि आवश्यक समझे, उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा ।

(v) आयोग उपभोक्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी या व्यक्ति को ऐसी फीस, लागत तथा खर्चों का संदाय ऐसे पक्षकारों द्वारा करने का निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

अध्याय 2

आयोग के समक्ष कार्यवाहियों से संबंधित साधारण नियम

9. आयोग के समक्ष कार्यवाहियां, आदि

(i) आयोग, अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए समय-समय पर ऐसी बैठकें करेगा जो वह समुचित समझे ।

(ii) आयोग के कारबार के संव्यवहार के लिए, उपरोक्त उप-विनियम (i) में यथा उल्लिखित बैठकें संचालित करने के लिए गणपूर्ति की संख्या दो होगी:

परंतु जब अध्यक्ष या सदस्य को ऐसी सुनवाई, बैठक में भाग लेने से निवारित किया गया है जिसकी उन्हें पर्याप्त कारण के लिए सम्यक् रूप से सूचना दी गई है तब यथास्थिति, बैठक में भाग लेने वाले सदस्य या अध्यक्ष विधिमान्यपूर्वक गणपूर्ति का गठन करेंगे:

परंतु यह और कि पिछले किसी भी विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के लिए आयोग की बैठक के लिए गणपूर्ति उपस्थित सभी सदस्यों की होगी ।

10. प्रतिनिधित्व का प्राधिकार

कोई भी व्यक्ति, आयोग के समक्ष अपना प्रतिनिधित्व करने तथा कार्य और अभिवचन करने हेतु किसी अधिवक्ता या किसी कानूनी वृत्तिक निकाय के ऐसे सदस्य को जिसके पास विधि व्यवसायी का प्रमाणपत्र हो, प्राधिकृत कर सकेगा जैसा आयोग समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें । कोई भी व्यक्ति आयोग के समक्ष स्वयं उपस्थित हो सकेगा और अपनी ओर से कार्य करने तथा अभिवचन करने हेतु अपने किसी भी कर्मचारी को प्राधिकृत कर सकेगा । आयोग समय-समय पर, ऐसे निबंधन तथा शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसके अध्यक्ष को कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से प्रतिनिधित्व करने और कार्य करने तथा अभिवचन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

11. कार्यवाहियों का आरंभ होना

(i) आयोग स्व-प्रेरणा से या किसी प्रमाणित या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा फाइल की गई याचिका पर कार्यवाही आरंभ कर सकेगा ।

(ii) कार्यवाहियों को आरंभ करने की सूचना आयोग द्वारा जारी की जाएगी तथा प्रभावित पक्षकारों को सूचना की तामील करने या ऐसे प्ररूप में, जैसा वह निदेश दे, याचिका के समर्थन में उत्तर और प्रतिपक्षी द्वारा प्रत्युत्तर फाइल करने के लिए ऐसे आदेश तथा निदेश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझें । आयोग, यदि उचित समझे, ऐसे प्ररूप में, जैसा आयोग निदेश दे, कार्यवाहियों में अंतर्बलित मुद्दों पर

टीका-टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए याचिका के प्रकाशन के लिए आदेश जारी कर सकेगा ।

(iii) जाँच की सूचना जारी करते समय, आयोग समुचित मामलों में, आयोग के किसी अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे आयोग मामलों में याचिकाकर्ता की हैसियत में मामले को प्रस्तुत करने हेतु समुचित समझे, पदाभिहित कर सकेगा ।

12. आयोग के समक्ष याचिकाएं तथा अभिवचन तथा संदेय फीस

(i) आयोग के समक्ष फाइल की जाने वाली सभी याचिकाएं टाइप, साइक्लोस्टाइल या सफेद कागज की एक ओर स्वच्छ रूप से मुद्रित तथा पठनीय होंगी तथा प्रत्येक पृष्ठ क्रम से संख्यांकित होगा । आयोग ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर, जो वह विनिर्दिष्ट करें, कंप्यूटर डिस्क या इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से याचिकाओं को स्वीकार करेगा । याचिका की अंतर्वस्तु पृथक् पैराओं में समुचित रूप से विभाजित होनी चाहिए जो कि क्रम से संख्यांकित होगी । याचिका के साथ संलग्न सभी ऐसे दस्तावेज, समर्थित आंकड़ें तथा विवरण ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे जिसने शपथ पत्र फाइल किया है ।

(ii) आयोग के समक्ष फाइल की गई प्रत्येक याचिका/आवेदन के साथ अध्याय-8 के उपबंधों के अनुसार फीस संलग्न की जाएगी ।

(iii) फीस डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर के रूप में संदेय होगी जो सचिव, गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के पक्ष में होगी ।

(iv) प्राप्त फीस को प्ररूप-जेईआरसी-1 (उपाबंध-1) में विहित रजिस्टर में प्रविष्ट किया जाएगा ।

13. साधारण शीर्षक

आयोग के समक्ष सभी याचिकाओं में साधारण शीर्षक तथा सभी प्रकाशन तथा सूचनाएं प्ररूप-जेईआरसी-2 (उपाबंध-2) के अनुसार होंगी ।

14. समर्थन में शपथपत्र

(i) सभी याचिकाएं हस्ताक्षरित, सत्यापित तथा शपथ-पत्र द्वारा समर्थित होंगी तथा ऐसा प्रत्येक शपथ-पत्र प्ररूप-जेईआरसी-3 (उपाबंध-3) के अनुसार होगा ।

(ii) सभी शपथ-पत्र एक वचन में लिखे जाने चाहिए तथा उसमें पूरा नाम, आयु, व्यवसाय तथा अभिसाक्षी का पता तथा वह हैसियत जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा है तथा ऐसे व्यक्ति के समक्ष हस्ताक्षरित तथा शपथित किया जाएगा जो शपथपत्र को विधिपूर्वक लेने तथा प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है।

(iii) प्रत्येक शपथपत्र में स्पष्टतः तथा पृथक् रूप से यह कथन दर्शित होगा कि उसमें
 क. अभिसाक्षी के ज्ञान के अनुसार;
 ख. अभिसाक्षी की प्राप्त जानकारी के अनुसार; तथा
 ग. अभिसाक्षी के विश्वास के अनुसार सत्य है।

15. जहां शपथपत्र में किसी कथन को अभिसाक्षी की प्राप्त सूचना के अनुसार सत्य कहा गया है, शपथपत्र में सूचना के स्रोत भी प्रकटित किया जाएगा तथा ऐसा कथन भी संलग्न करेगा कि अभिसाक्षी को विश्वास है कि जानकारी सत्य है।

16. याचिकाओं का प्रस्तुतीकरण तथा संवीक्षा

(i) सभी याचिकाओं की छह प्रतियां फाइल की जाएंगी तथा याचिका का प्रत्येक सेट सभी प्रकार से पूर्ण होगा। याचिका के साथ आयोग द्वारा विहित फीस संदेय होगी।

(ii) सभी याचिकाएं व्यक्तिगत रूप से या सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता या प्रतिनिधि द्वारा आयोग के मुख्यालय में या आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए ऐसे अन्य फाइलिंग केंद्र या केंद्रों पर तथा अधिसूचित समय पर प्रस्तुत की जाएंगी। याचिकाओं को आयोग का, ऊपर उल्लिखित स्थानों पर रजिस्ट्रीकृत डाक पावती द्वारा भी भेजा जा सकता है। अधिवक्ता के पक्ष में वकालतनामा तथा यदि याचिका प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत की जा रही है तो याचिका के साथ प्रतिनिधि को प्राधिकृत करने वाला दस्तावेज भी फाइल किया जाएगा, यदि मामले अभिलेख पर पहले से दर्ज न किए गए हों। आयोग के समक्ष पक्षकार का प्रतिनिधि करने वाले विधि व्यवसायी से भिन्न कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्ररूप जेईआरसी-4 (उपाबंध-4) में उपसंज्ञाति ज्ञापन फाइल करेगा।

(iii) याचिका की प्राप्ति पर, याचिका प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा पदाभिहित प्राप्त करने वाला अधिकारी मुहर लगाकर तथा जिस तारीख को याचिका प्रस्तुत की गई वह तारीख डालकर पावती देगा तथा याचिका फाइल करने वाले व्यक्ति को, मुहर तथा तारीख के साथ पावती देगा, प्राप्ति सूचना भी देगा। यदि याचिका

रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्राप्त होती है तो जिस तारीख को याचिका आयोग के कार्यालय में वास्तविक रूप से प्राप्त होती है वहीं तारीख याचिका के प्रस्तुतीकरण की तारीख जानी जाएगी ।

(iv) याचिका के प्रस्तुतीकरण तथा प्राप्ति की प्रविष्टि आयोग के कार्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए रखे गए रजिस्टर में सम्यक् रूप से की जाएगी । उक्त रजिस्टर प्ररूप जेईआरसी-5 (उपाबंध-5) में दिए गए प्ररूप के अनुसार होगा ।

(v) प्राप्तिकर्ता अधिकारी किसी ऐसी याचिका को स्वीकार करने से इंकार कर सकेगा जो अधिनियम या विनियमों के उपबंधों या आयोग द्वारा दिए गए निदेशों के अनुरूप नहीं है या कोई अन्य त्रुटि है जो विनियमों या आयोग के निदेशों के अनुसार से भिन्न किसी अन्य प्रकार से प्रस्तुत की गई हो :

परंतु, तथापि, किसी याचिका को, याचिका फाइल करने वाले व्यक्ति को इस प्रयोजन के लिए दिए गए समय में त्रुटि को दूर करने का अवसर दिए बिना, अभिवचनों या प्रस्तुतीकरण में त्रुटियों के लिए नामंजूर नहीं किया जाएगा । प्राप्तिकर्ता अधिकारी फाइल की गई याचिका में की गई त्रुटियों को प्ररूप जेईआरसी-6 (उपाबंध-6) में दिए गए प्ररूप के अनुसार लिखित में सलाह देगा ।

(vi) याचिका के प्रस्तुतीकरण के संबंध में प्राप्तिकर्ता अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति मामले को समुचित आदेश के लिए आयोग के सचिव के समक्ष रखने का अनुरोध कर सकेगा ।

(vii) अध्यक्ष किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत याचिका को मंगाने का हकदार होगा तथा याचिका के प्रस्तुतीकरण और मंजूरी से संबंधित ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह उचित समझे ।

(viii) यदि संवीक्षा करने पर, याचिका नामंजूर नहीं की जाती अथवा सचिव या अध्यक्ष द्वारा नामंजूरी के किसी आदेश को परिशोधित किया जाता है तो याचिका सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत की जाएगी तथा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति से नम्बर दिया जाएगा ।

(ix) जैसे ही याचिका तथा सभी आवश्यक दस्तावेज दाखिल किए जाते हैं तथा त्रुटियों और आपत्तियां, यदि कोई हों, दूर की जाती हैं तथा याचिका की जांच कर ली गई हो

तथा उसे संख्यांकित कर दिया गया हो, तो याचिका प्रारंभिक सुनवाई तथा स्वीकृति के लिए आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(x) आयोग, पक्षकार की उपस्थिति की आवश्यकता के बिना याचिका को स्वीकृत कर सकेगा। आयोग सम्बद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना स्वीकृति रद्द करने का आदेश पारित नहीं करेगा। आयोग यदि उचित समझे, तो ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जैसा वह ठीक समझे, याचिका की स्वीकृति की सुनवाई के लिए, नोटिस जारी कर सकेगा।

(xi) यदि आयोग, याचिका स्वीकार करता है तो यह प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) तथा अन्य प्रभावित या हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे प्ररूप में जैसा आयोग निदेश करे, याचिका के पक्ष या विपक्ष में उत्तर तथा प्रत्युत्तर फाइल करने के लिए, नोटिस तामील करने के लिए तथा याचिका को आयोग के समक्ष सुनवाई के लिए रखने के ऐसे आदेश तथा निदेश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

17. आयोग द्वारा जारी नोटिस तथा आदेशिका तामील करना

(i) आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले किसी नोटिस या आदेशिका या समन की तामील, आयोग द्वारा निर्देशित निम्न प्रकारों में से किसी एक या अधिक प्रकार से की जा सकेगी;

(क) कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा तामील इस प्रकार की जाएगी जैसा आयोग द्वारा निर्देशित हो;।

(ख) किसी संदेशवाहक द्वारा व्यक्तिगत रूप से पहुँचाना;

(ग) पावती सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा;

(घ) उन मामलों में, जहां आयोग का यह समाधान हो गया है कि किसी व्यक्ति को युक्तियुक्त रूप से नोटिस, आदेशिका आदि तामील करना व्यावहारिक नहीं है, समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा;

(ङ) किसी अन्य रीति से जिसे आयोग उचित समझे।

(ii) प्रत्येक मामले में आयोग यह निर्णय करने का हकदार होगा कि कौन व्यक्ति इस प्रकार की तामील/प्रकाशन की लागत का वहन करेगा ।

(iii) प्रत्येक ऐसी नोटिस या आदेशिका, जिसका तामील की जानी अपेक्षित है या किसी व्यक्ति को पहुँचाई जानी है, उस व्यक्ति या तामील स्वीकार करने के लिए उसके द्वारा दिए गए पते पर, या तामील स्वीकार करने के लिए सशक्त उसका अभिकर्ता या उस स्थान पर जहाँ वह व्यक्ति या उसका अभिकर्ता प्रायः रहता है या व्यापार करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कार्य करता है, भेजी जा सकेगी । नोटिस के साथ याचिका के साथ फाइल किए गए दस्तावेजों की प्रतियाँ सहित याचिका की प्रति भी संलग्न की जाएगी ।

(iv) उस दशा में जब आयोग के समक्ष कोई मामला लंबित हो तथा तामील किए जाने वाले व्यक्ति ने किसी अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि को प्रस्तुत होने या स्वयं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत कर दिया हो तो अभिकर्ता या प्रतिनिधि को सभी मामलों में संबंधित पक्षकार की ओर से नोटिस तथा आदेशिकाएं तामील होने के लिए सशक्त समझा जाएगा तथा ऐसे अभिकर्ता या प्रतिनिधि को की गई तामील को, तामील किए जाने वाला तामील माना जाएगा ।

(v) जहाँ नोटिस कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा दिया जाता है तो वह पक्षकार आयोग में, नोटिस तथा आदेशिकाओं के तामील की तारीख तथा रीति का विवरण देते हुए तामील का शपथ पत्र फाइल करेगा।

(vi) यदि किसी याचिका को प्रकाशित किया जाना अपेक्षित हो तो इसे विनिर्दिष्ट किए जाने वाले ऐसे प्ररूप में, समाचार-पत्र में ऐसी अवधि और ऐसे समय के भीतर प्रकाशित किया जाएगा, जैसा आयोग निदेश दे ।

(vii) नोटिस, सम्मन या आदेशिकाओं की तामील या उनके प्रकाशन के संबंध में विनियमों या आयोग के निदेशों के अनुपालन में त्रुटि होने पर आयोग या तो याचिका खारिज कर सकता है या ऐसे अन्य और निदेश दे सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(viii) व्यक्ति के नाम या विवरण में कोई त्रुटि होने के कारण किसी तामील या प्रकाशन को अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा परंतु यह तब जबकि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी तामील अन्य सभी प्रकार से पर्याप्त है तथा किसी त्रुटि या अनियमितता के कारण कोई कार्यवाही तब तक अविधिमान्य नहीं होगी जब तक कि आयोग की, किए

गए आक्षेप पर यह राय हो कि ऐसी त्रुटि या अनियमितता के कारण सारवान रूप से अन्याय हुआ है या ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण हो ।

18. उत्तर, विरोध, आक्षेपों आदि का फाइल किया जाना:

(i) प्रत्येक व्यक्ति जिसे जाँच का नोटिस या याचिका जारी की जाती है (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रत्यर्थी कहा गया है) जो याचिका का विरोध या समर्थन करना चाहता है, उत्तर और ऐसे दस्तावेजों को, जिन पर वह विश्वास करता है, (छह प्रतियों में) ऐसी अवधि के भीतर फाइल करेगा जो आयोग द्वारा नियत की जाए । फाइल किए गए उत्तर में प्रत्यर्थी जाँच के नोटिस या याचिका में दिए गए तथ्यों को विशिष्ट रूप से स्वीकार, इंकार या स्पष्ट करेगा तथा ऐसे अतिरिक्त तथ्यों का भी अधिकथन करेगा जिन्हें वह मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक समझे । उत्तर याचिका की ही शीति से हस्ताक्षरित तथा सत्यापित होगा और शपथपत्र द्वारा समर्थित किया जाएगा ।

(ii) प्रत्यर्थी उत्तर की एक प्रति दस्तावेजों की सही प्रति के रूप में सम्यक् रूप से सत्यापित प्रतियों के साथ याचिकाकर्ता को या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को तामील करेगा तथा आयोग के कार्यालय में ऐसी तामील का सबूत भी फाइल करेगा ।

(iii) जहाँ प्रत्यर्थी मामले के न्यायपूर्ण विनिश्चय के लिए आवश्यक अतिरिक्त तथ्यों का अधिकथन करता है, तो आयोग याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए उत्तर का प्रत्युत्तर फाइल करने की अनुज्ञा दे सकेगा । उत्तर फाइल करने के लिए उम्पर वर्णित प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तनों सहित प्रत्युत्तर फाइल करने के लिए लागू होगी ।

(iv) आक्षेप या टीका-टिप्पणियों का फाइल किया जाना -

(क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, (ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें उत्तर मांगने के लिए नोटिस, आदेशिकाएं आदि जारी की गई हैं) जो इस प्रयोजन के लिए किए गए प्रकाशन के अनुसरण में आक्षेप या टिप्पणियाँ फाइल करने का आशय रखता है, इस प्रयोजन के लिए नियत समय के भीतर आक्षेपों या टिप्पणियों का विवरण, उन्हें समर्थन करने वाले दस्तावेजों की छह प्रतियों और साक्ष्यों के साथ आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित अधिकारी को पहुँचाएगा ।

(ख) यदि आयोग अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट पर यह समझता है कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों की भागीदारी मामले की कार्यवाहियों तथा निर्णय में मदद करेगी तो आयोग ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जिसमें संगम, फोरम निगमित निकाय भी सम्मिलित हैं, जिन्हें वह

भाग लेने के लिए उपयुक्त समझें, आयोग के समक्ष कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(ग) जब तक कि आयोग द्वारा अनुज्ञा न दे दी हो, आक्षेप या टिप्पणियाँ फाइल करने वाला व्यक्ति आवश्यक रूप से कार्यवाहियों में मौखिक निवेदन करने हेतु भाग लेने का हकदार नहीं होगा । तथापि, आयोग आक्षेपों या टिप्पणियों के निपटान के लिए कार्यवाहियों के पक्षकारों को ऐसा अवसर, जैसा आयोग उचित समझें, देने के पश्चात् फाइल किए गए आक्षेपों और टिप्पणियों पर कार्यवाही करने का हकदार होगा ।

19. मामले की सुनवाई

(i) आयोग, मामले की सुनवाई के लिए जैसा वह उपयुक्त समझे प्रक्रम, रीति, स्थान, तारीख तथा समय को अवधारित कर सकेगा तथा निम्नलिखित किसी एक या अधिक रीति से और कार्यवाही कर सकेगा:

(क) आयोग, पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर मामले का विनिश्चय कर सकेगा या पक्षकारों को शपथ पत्र द्वारा या मामले में मौखिक निवेदन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कह सकेगा ।

(ख) यदि आयोग, मौखिक निवेदन द्वारा पक्षकार को साक्ष्य देने का निदेश देता है, आयोग, यदि आवश्यक या समीचीन समझे, तो दूसरे पक्षकार को साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों की प्रति-परीक्षा करने का अवसर दे सकेगा ।

(ग) आयोग, यदि आवश्यक या समीचीन समझे, किसी अधिकारी या आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित व्यक्ति को किसी भी पक्षकार के साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए निदेश दे सकेगा ।

(घ) आयोग, पक्षकार को मामले के तर्कों या निवेदनों का लिखित नोट फाइल करने का निदेश दे सकेगा ।

20. पक्षकार द्वारा उपसंजात न होने पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:

(i) जब कोई मामला सुनवाई के लिए नियत किया जाए या सुनवाई के लिए निश्चित तारीख को या सुनवाई की किसी ऐसी अन्य तारीख को जिस तक सुनवाई स्थगित हो, पक्षकारों

में से कोई या उनका प्राधिकृत अभिकर्ता या प्रतिनिधि उपसंजात न हो तो आयोग, अपने विवेकाधिकार से जब याचिकाकर्ता या उस व्यक्ति के, जो आयोग को सुनवाई के लिए प्रेरित करता है, अनुपस्थित रहने पर याचिका को व्यतिक्रम के लिए खारिज कर सकता है या एक पक्षीय कार्यवाही कर सकता है।

- (ii) जब कोई याचिका व्यतिक्रम के लिए खारिज कर दी जाए या उस पर एक पक्षीय विनिश्चय दे दिया जाए तो व्यथित व्यक्ति, यथास्थिति, याचिका खारिज होने या एक पक्षीय विनिश्चय होने के 30 दिन के भीतर पारित आदेश को वापस करने के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा तथा यदि आयोग की यह समाधान हो जाता है कि जब याचिका का सुनवाई हुई उस व्यक्ति के अनुपस्थित रहने के लिए पर्याप्त कारण था, तो आयोग उन शर्तों पर, जिन्हें वह उचित समझे, आदेश वापस ले सकेगा।

21. आयोग की अतिरिक्त जानकारी, साक्ष्य आदि मांगने की शक्तियाँ :

(i) आयोग किसी भी मामले पर आदेश पारित करने से पूर्व किसी भी समय पक्षकारों या उनमें से किसी एक या अधिक या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे आयोग उपयुक्त समझे, ऐसे दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निदेश दे सकेगा जिन्हें आयोग स्वयं को आदेशों को पारित करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन से आवश्यक समझे।

(ii) आयोग, साक्षी को सम्मन करने, साक्ष्य के रूप में पेश किए जा सकने वाले किसी दस्तावेज या अन्य तात्त्विक सामग्री की खोज या उसे पेश करने, किसी कार्यालय से लोक अभिलेख मांगने, आयोग के किसी अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के नियंत्रण या अभिरक्षा में रख ऐसे लेखों, बहियों या अन्य दस्तावेजों या जानकारी की, जिसे आयोग मामले में समुचित समझता है, जाँच करने का निदेश दे सकेगा।

22. विवाद्यको का अन्यों को निर्देश करना:

(i) कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, आयोग मामले के ऐसे विवाद्यक या विवाद्यकों को, जिन्हें वह उचित समझे, ऐसे व्यक्तियों को, जिनमें आयोग के अधिकारी और पसमर्शदाता भी सम्मिलित हैं, किंतु वे उन तक ही सीमित नहीं हैं और जिन्हें आयोग विशेषज्ञीय सलाह या राय देने के लिए अर्हित समझता है, निर्दिष्ट करने का हकदार होगा।

(ii) आयोग, समय-समय पर किसी स्थान या स्थानों के निरीक्षण के लिए तथा स्थान के अस्तित्व या स्तर या वहाँ की सुविधाओं पर रिपोर्ट देने के लिए ऐसे व्यक्तियों को

नाम-निर्दिष्ट कर सकेगा जिनमें अधिकारी और परामर्शदाता सम्मिलित हैं, किंतु उन तक ही सीमित नहीं है ।

(iii) आयोग, यदि यह ठीक समझे, संबंधित पक्षकारों को, जो विशेषज्ञ या सूचित सलाह या राय देने के लिए अर्हित हो, और/या किसी अन्य व्यक्ति को, ऊपर उपखण्ड (1) और (2) में पदाभिहित व्यक्तियों के समक्ष निर्दिष्ट विवादों या मामलों पर अपने-अपने विचार प्रकट करने के लिए पेश होने का निर्देश दे सकता है ।

(iv) ऐसे व्यक्ति से प्राप्त रिपोर्ट या राय मामले के अभिलेख का एक भाग होगी तथा आयोग, द्वारा पदाभिहित व्यक्ति द्वारा दी गई रिपोर्ट या राय की प्रतियाँ पक्षकारों को दी जाएगी । पक्षकार रिपोर्ट या राय के समर्थन या विरोध में अपने पक्ष का पाठ फाइल करने के हकदार होंगे ।

(v) आयोग, मामले का विनिश्चय करते समय ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई रिपोर्ट या राय, पक्षकारों द्वारा फाइल उत्तर को सम्यक् रूप से ध्यान में रखेगा और यदि आवश्यक समझे, रिपोर्ट या राय देने वाले व्यक्ति की जांच कर सकेगा ।

23. आयोग के आदेश:

(i) आयोग, याचिका पर आदेशों को पारित करेगा तथा आयोग के सदस्य, जो मामले की सुनवाई तथा विनिश्चय पर वोट करते हैं, आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे ।

(ii) आयोग द्वारा आदेशों के समर्थन में दिए गए कारण, आदेश का एक भाग होंगे तथा इन विनियमों के अनुसार प्रतियाँ निरीक्षण प्रतियाँ भेजे जाने के लिए उपलब्ध होंगी ।

(iii) आयोग द्वारा जारी या सूचित किए गए सभी आदेश और विनिश्चय सचिव के या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे तथा उन पर आयोग के कार्यालय की मुद्रा होगी ।

(iv) आयोग के सभी अंतिम आदेश कार्यवाही के सभी पक्षकारों को सचिव के अथवा अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से संसूचित किए जाएंगे ।

(v) किसी अन्य उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, व्यथित पक्षकार आयोग के आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 110 के अधीन स्थापित विद्युत अपील अधिकरण में अपील फाइल करेगा ।

24. अंतरिम आदेश

आयोग, कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में, ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे।

25. कार्यवाहियों के अभिलेखों का निरीक्षण

(i) सिवाय उस भाग के जिसके लिए आयोग द्वारा अभिलिखित कारण गोपनीय या विशेष हैं या किसी व्यक्ति को प्रकटित न किए जाने है, प्रत्येक कार्यवाही के अभिलेख कार्यवाही के दौरान या आदेश पारित करने के पश्चात् इस बात के अध्वधीन ऐसे निबंधनों का अनुपालन करने वाले व्यक्ति के लिए निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे जैसा आयोग समय, स्थान तथा निरीक्षण की रीति तथा फीस के संदाय सहित, आदेश दे।

(ii) दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए आवेदन जेईआरसी-7 (उपाबंध-7) के अनुसार होगा तथा उसके साथ प्रत्येक दिन के लिए प्रत्येक निरीक्षण हेतु डिमांड ड्राफ्ट/पे-आदेश के रूप में 100/-रुपए की फीस संलग्न की जाएगी जो सचिव, गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के पक्ष में देय होगी।

(iii) अभिलेखों का निरीक्षण इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में 2.30 बजे से 4.30 बजे के बीच किसी कार्यदिवस के दौरान अनुज्ञात किया जाएगा।

(iv) अभिलेखों का निरीक्षण करने वाला व्यक्ति, निरीक्षण करते समय, किसी भी रीति से अभिलेखों को अस्त-व्यस्त नहीं करेगा, उन्हें फाड़ेगा नहीं, छेड़छाड़ नहीं करेगा या उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

(v) निरीक्षण का पर्यवेक्षण करने वाला अधिकारी, यदि उसकी राय में निरीक्षण करने की प्रक्रिया में किन्हीं भी अभिलेखों को नुकसान होने की संभावना है तो वह किसी भी समय निरीक्षण करने के लिए मना कर सकेगा तथा इस संबंध में तत्काल सचिव को रिपोर्ट करेगा तथा मामले पर आदेश प्राप्त करेगा।

(vi) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए रजिस्टर प्ररूप जेईआरसी-8 (उपाबंध-8) के अनुसार बनाए रखा जाएगा।

25. दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों का दिया जाना

(i) कोई भी व्यक्ति आयोग के आदेशों, विनिश्चयों, निदेशों तथा उनके समर्थन में दिए गए कारणों की प्रमाणित प्रतियां तथा अभिवचन कागज-पत्र तथा अभिलेखों के अन्य भाग, जिसके लिए वह हकदार है, को अभिप्राप्त करने का हकदार होगा जिसके लिए उसके द्वारा फीस का संदाय तथा ऐसे अन्य निबंधनों का पालन किया जाएगा, जैसा आयोग निदेश दे।

(ii) अंतरिम राहत देने वाला, इंकार करने वाला या उपांतरित करने वाला प्रत्येक आदेश तथा अंतिम आदेश याचिका के पक्षकारों को निःशुल्क भेजा जाएगा:

परंतु यह कि जब तक आयोग द्वारा अन्यथा आदेश न दिया, अंतिम आदेश की प्रति किसी ऐसे पक्षकार को नहीं भेजी जाएगी जो उपस्थित नहीं हुआ हो।

(iii) आयोग के किसी आदेश की प्रमाणित प्रति या आयोग के समक्ष कार्यवाही के अभिलेख के कोई दस्तावेज के प्ररूपिक भाग को अभिप्राप्त करने वाला व्यक्ति विहित प्ररूप जेईआरसी-9 (उपाबंध-9) में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(iv) प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन के साथ इन विनियमों की अनुसूची में विहित फीस संलग्न की जाएगी जो डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर के रूप में, सचिव गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के पक्ष में संदेय होगी।

(v) प्रति आवेदनों के रजिस्टर को प्ररूप जेईआरसी-10 (उपाबंध-10) में यथा विहित रूप में बनाए रखा जाएगा।

(vi) यथासाध्य-शीघ्र उस क्रम में प्रमाणित प्रतियां तैयार की जाएगी जिसमें आवेदन प्रति आवेदनों के रजिस्टर में प्रविष्ट किए गए हों।

(vii) प्रमाणित प्रतियां फोटोकापी की प्रक्रिया या टाइपिंग द्वारा तैयार की जाएगी और जब इस प्रकार प्रतियां तैयार हो जाएं तो उनकी प्रति तैयार करने वाले व्यक्ति द्वारा अपना यह समाधान करने के लिए मिलान किया जाएगा कि प्रतियां सही ढंग से तैयार की गई हैं और मांगे गए दस्तावेज की प्रतियां स्वच्छ हैं।

(viii) दस्तावेज के अंतिम पृष्ठ के पीछे निम्नलिखित पृष्ठांकित किया जाएगा,

(क) आवेदन का क्रम सं०

(ख) आवेदक का नाम

(ग) आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख

- (घ) पृष्ठों की संख्या
- (ङ.) प्रभारित प्रति फीस
- (च) वह तारीख जिसको प्रति तैयार हुई
- (छ) परिदान की तारीख

(ix) पृष्ठांकन इस प्रयोजन के लिए तैयार की गई खड़ स्टॉप की सहायता से किया जाएगा। प्रविष्टियां स्याही से की जाएंगी।

(x) प्रमाणित प्रति अभिप्राप्त करने के लिए संदेय प्रति फीस प्रत्येक पृष्ठ में शब्दों/लाइनों की संख्या को ध्यान में लाए बिना 3 रुपए प्रति पृष्ठ होगी।

26. आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाहियां समझा जाना

(i) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 95 के अनुसार, आयोग के समक्ष की सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 तथा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी तथा आयोग दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 345 तथा 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

(ii) भारतीय दंड संहिता तथा दंड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत उपबंध निम्नानुसार हैं:-

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 193

मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड

जो कोई साक्ष्य किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से, मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

और जो कोई किसी अन्य मामले में, साक्ष्य मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1 - सेना न्यायालय (***) के समक्ष विचारण न्यायिक कार्यवाही है।

स्पष्टीकरण 2 - न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ होने से पूर्व जो विधि द्वारा निर्दिष्ट अन्वेषण होता है। वह न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो।

(ख) भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 228

न्यायिक कार्यवाही में बैठे हुए लोक-सेवक का साशय अपमान या उनके कार्य में विघ्न

जो कोई किसी लोक सेवक का उस समय, जब कि ऐसा लोक सेवक न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में बैठा हुआ हो, साशय कोई अपमान करेगा या उसके कार्य में विघ्न डालेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(ग) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345

अवमानना के कुछ मामलों में प्रक्रिया

(1) जब कोई ऐसा अपराध, जैसा भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित है, किसी सिविल, दंड या राजस्व न्यायालय की दृष्टिगोचरता या उपस्थिति में किया जाता है, तब न्यायालय अभियुक्त को अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकता है और उसी दिन न्यायालय के उठने के पूर्व किसी समय, अपराध का संज्ञान कर सकता है तथा अपराधी को ऐसा कारण दर्शित करने का, कि क्यों न उसे इस धारा के अधीन दंडित किया जाए, उचित अवसर देने के पश्चात् अपराध को दो सौ रुपए से अधिक जुर्माने का और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर एक मास तक की अवधि के लिए, जब तक कि ऐसा जुर्माना उससे पूर्वतर न दे दिया जाए, सादा कारावास का दंडादेश दे सकता है।

(2) ऐसे प्रत्येक मामले में न्यायालय वे तथ्य जिनसे अपराध बनता है, अपराधी द्वारा किए गए कथन के (यदि कोई हो) सहित तथा निष्कर्ष और दंडादेश भी अभिलिखित करेगा।

(3) यदि अपराध भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 228 के अधीन है तो अभिलेख में यह दर्शित होगा कि जिस न्यायालय के कार्य में विघ्न डाला गया था जिसका अपमान किया गया था उसकी बैठक किस प्रकार की न्यायिक कार्यवाही के संबंध में और उसके किसी प्रक्रम पर हो रही थी और किस प्रकार का विघ्न डाला गया था अपमान किया गया था।

(घ) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 38 के अन्तर्गत न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 345 के अधीन कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए वहां प्रक्रिया:

- (1) यदि किसी मामले में न्यायालय का यह विचार है कि धारा 345 में निर्दिष्ट और उसकी दृष्टिगोचरता या उपस्थिति में किए गए अपराधों में से किसी के लिए अभियुक्त व्यक्ति जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने से अन्यथा कारावासित किया जाना चाहिए या उस पर दो सौ रुपए से अधिक जुर्माना अधिविरोधित किया जाना चाहिए या किसी अन्य कारण से उस न्यायालय की यह राय है कि मामला धारा 345 के अधीन नहीं निपटाया जाना चाहिए तो वह न्यायालय उन तथ्यों को, जिससे अपराध बनता है और अभियुक्त के कथन को इसमें इसके पूर्व उपबंधित प्रकार से अभिलिखित करने के पश्चात्, मामला उसका विचारण करमे की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा और ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे व्यक्ति की हजिरी के लिए प्रतिभूति दी जाने की अपेक्षा कर सकेगा, अथवा यदि पर्याप्त प्रतिभूति न दी जाए तो ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।
- (2) वह मजिस्ट्रेट, जिसे कोई मामला इस धारा के अधीन भेजा जाता है, जहां तक हो सके इस प्रकार कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा मानो वह मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है।

अध्याय 3

अन्वेषण, जांच, जानकारी एकत्र करना

27. आयोग द्वारा आदेश/निर्देश

- (i) आयोग निम्नलिखित के बारे में अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जानकारी एकत्र करने, जांच, अन्वेषण, प्रवेश, तलाशी तथा अभिग्रहण के लिए अधिनियम के लागू उपबंधों के निबंधनों के अनुसार ऐसे आदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे:-
- (क) आयोग किसी ऐसे भवन या स्थान में प्रवेश के लिए आयोग की ओर से विशेष रूप से किसी भी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा जहां आयोग को यह विश्वास करने

के कारण हो कि अधिनियम के अधीन जांच या न्यायनिर्णयन की विषय-वस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज पाया जा सकेगा तथा ऐसे किसी दस्तावेज को जब्त कर सकेगा या उसका सारांश या प्रतियां ले सकेगा ।

(ख) अधिनियम की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग अपना यह समाधान हो जाने पर कि कोई अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की किंही शर्तों का या कोई उत्पादन कंपनी अधिनियम या तदधीन न बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों का किसी भी समय अनुपालन करने में असफल रहा है तो वह लिखित आदेश द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी के मामलों का अन्वेषण करने तथा आयोग को रिपोर्ट देने का निदेश देगा । इस प्रयोजन के लिए, आयोग अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादन कंपनियों द्वारा बनाए रखी जाने वाली न्यूनतम जानकारी का निदेश दे सकेगा और ऐसी रीति से भी निदेश दे सकेगा जिसमें ऐसी जानकारी को बनाए रखा जाएगा तथा स्वीकार किए जाने के लिए जांच तथा सत्यापन किया जाएगा ।

(ग) आयोग किसी भी समय, आयोग की अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी मामले के संबंध में सचिव या एक या उससे अधिक अधिकारी या परामर्शकों या किसी अन्य को, जिसे आयोग ठीक समझे, अध्ययन, अन्वेषण या जानकारी प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा ।

(घ) आयोग उक्त प्रयोजन के लिए, ऐसे अन्य आदेश, जिन्हें वह ठीक समझे, दे सकेगा तथा ऐसी समय-सीमा विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसके भीतर रिपोर्ट या जानकारी प्रस्तुत की जानी है ।

(ङ.) आयोग, जैसा अधिनियम में उपबंधित है, किसी व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने तथा उसकी जांच अनुज्ञात करने तथा इस निमित्त पदाभिहित आयोग के अधिकारी को बहियों, लेखाओं आदि को बनाए रखने या अधिकारी को जानकारी देने के निदेश जारी कर सकेगा या सचिव या अधिकारी को ऐसे निदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(च) आयोग, किसी ऐसी जानकारी, विशिष्टियों या ऐसे दस्तावेजों, जिन्हें आयोग आवश्यक समझे, के प्रयोजन के लिए अधिनियम में उपबंधित अपने कृत्यों के निर्वहन के संबंध में ऐसे निदेश जारी कर सकेगा तथा एक या उससे अधिक पद्धतियों का अनुसरण कर सकेगा ।

- (छ) यदि ऐसी प्राप्त रिपोर्ट या जानकारी आयोग को अपर्याप्त या अधूरी प्रतीत होती है तो आयोग या सचिव या इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी और जांच करने, रिपोर्ट तथा जानकारी देने का निदेश दे सकेगा।
- (ज) आयोग उपर्युक्त के संबंध में ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक और अनुपूरक मामलों पर, जिन्हें वह सुसंगत समझे, ध्यान देने का निदेश दे सकेगा।
- (ii) अधिनियम तथा विनियमों के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के संबंध में, आयोग, यदि ठीक समझे, इन विनियमों के अध्याय-2 के अधीन उपबंधित रीति से मामले पर जांच का नोटिस जारी करने और कार्यवाही करने का निदेश दे सकेगा।
- (iii) आयोग किसी भी समय किसी संस्था, परामर्शक, विशेषज्ञ, इंजीनियर, चार्टर्ड लेखाकार, अधिवक्ताओं, सर्वेक्षकों तथा ऐसे अन्य तकनीकी तथा वृत्तिक व्यक्तियों, जिन्हें वह आवश्यक समझे, की सहायता ले सकेगा तथा किसी मामले में, या मुद्दों पर अध्ययन, अन्वेषण, जांच करने के लिए उनको कह सकेगा और रिपोर्ट या कोई जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकेगा। आयोग ऐसे वृत्तिकों की नियुक्ति के लिए निबंधन तथा शर्तें अवधारित कर सकेगा।

अध्याय - 4

28. अनुज्ञप्तिधारियों और उत्पादन कंपनियों द्वारा फाइलिंग

- (i) आयोग, अधिनियम के लागू उपबंधों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारियों/उत्पादन कंपनियों के राजस्व और टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट करेगा।
- (ii) प्रभारों से आशयित राजस्व की संगणना के लिए, और टैरिफ अवधारित करने के लिए रीति और प्रक्रियाएं समय-समय पर आयोग द्वारा उपबंधित की जा सकेंगी।
- (iii) जब तक आयोग द्वारा अन्यथा निदेशित न किया जाए, अनुज्ञप्तिधारियों/उत्पादन कंपनियों के राजस्व/टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधनों और शर्तों के अंतर्गत यह सम्मिलित होगा कि अधिनियम की धारा 62 के निबंधनों में किसी वित्तीय वर्ष में अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादन कंपनी के अनुज्ञात टैरिफ और अनुमति प्राप्त राजस्व पश्चातवर्ती अवधि के लिए नियत किए जाने वाले किसी टैरिफ में समायोजन के अध्यधीन होगा। यदि आयोग का लिखित में ऐसे कारण अभिलिखित करने पर

यह समाधान हो जाता है कि ऐसा समायोजन वास्तव में वसूल की गई रकम के आधिक्य या कमी के लिए आवश्यक है और यदि आयोग का यह भी समाधान हो जाता है कि वह अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादन कंपनी से सम्बद्ध किसी कारण की वजह से नहीं है।

- (iv) अधिनियम के लागू उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक वर्ष अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी, प्रत्येक वर्ष 30 नवम्बर के पूर्व या जैसा कि आयोग द्वारा अन्यथा निदेशित किया जाए, एक प्रारूप में और इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुसार टैरिफ के अवधारण के लिए एक आवेदन-पत्र, इसके चालू अनुमोदित टैरिफ के अधीन प्रभारों से आगामी वित्तीय वर्ष के आशयित कुल राजस्व के लिए संगणनाओं वाले विवरण, सेवाएं प्रदान करने की आशयित लागत और टैरिफ प्रस्तावों सहित आयोग में फाइल करेगी।
- (v) उप विनियम (iv) में निर्दिष्ट विवरण, अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादन कंपनी के प्रत्येक पृथक् कारबार के लिए अलग से प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक पृथक् कारबार के लिए ऐसी रीति में प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि आयोग निदेश दे।
- (vi) उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादन कंपनी, आयोग में तुरंत ऐसी अतिरिक्त सूचना, विशिष्टियां और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जैसा आयोग ऐसे प्रारूप में, जो वह निदेश दे राजस्व संगणनाएं और टैरिफ प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के पूर्व, प्रस्तुत किए जाते समय या प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् अपेक्षित करे जैसा कि आयोग समय-समय पर निदेश करें।
- (vii) आयोग, राजस्व संगणनाओं के विवरण और टैरिफ प्रस्ताव फाइल करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा और जब तक आयोग द्वारा छूट न दी जाए, अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादन कंपनी आयोग द्वारा जारी ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करेंगे।

29. टैरिफ प्रस्तावों का प्रकाशन, आक्षेप पर सुनवाई

- (i) अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी, टैरिफ प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के 3 दिनों के भीतर, उत्पादक या प्रदाय के क्षेत्र में व्यापक रूप से परिचालित कम से कम दो समाचार पत्रों में एक सूचना, प्रस्तावित टैरिफ का सारांश बताते हुए तथा इच्छुक व्यक्तियों और राज्य सरकार/सम्बद्ध संघ राज्यक्षेत्र से आक्षेप आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित करेगी:

परंतु यह कि समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना समाचार पत्र की ही भाषा में होगी।

- (ii) जब तक आयोग द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए, आयोग अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादक कंपनी द्वारा दी गई राज्य संगणनाओं और टैरिफ प्रस्तावों पर कार्यवाही करेगा और ऐसी राजस्व संगणनाओं तथा टैरिफ प्रस्तावों पर विनिश्चय देने के लिए ऐसे व्यक्तियों को सुन सकेगा जैसा आयोग समुचित समझे।
- (iii) अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादन कंपनी की राजस्व संगणनाओं और टैरिफ प्रस्तावों पर सुनवाई, जहां तक संभव हो, उसी रीति में की जाएगी जैसा कि इन विनियमों के अध्याय-2 में उपबंधित है।

30. आयोग का आदेश

- (i) आयोग द्वारा अपेक्षित पूर्ण सूचना अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् और आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सुनने के बाद तथा एक ऐसी जांच करने के बाद जैसा कि आयोग समुचित समझे, आयोग एक आदेश करेगा और आवेदक को राजस्व संगणना तथा टैरिफ प्रस्तावों पर अपने विनिश्चय से सूचित करेगा।
- (ii) उपरोक्त अधिनियम (i) के अधीन आदेश करते समय, तत्पश्चात् किसी समय, आयोग ऐसा टैरिफ अधिसूचित कर सकेगा जो अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी प्रभावित करेंगे।
- (iii) आयोग, आदेश किए जाने के सात दिनों के भीतर आदेश की एक-एक प्रतिलिपि संबंधित सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और संबंधित अनुज्ञप्तिधारी/उत्पादन कंपनियों और संबंधित व्यक्ति को भेजेगी।

31. टैरिफ का प्रकाशन

अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ, यथास्थिति, गोवा राज्य या संबंधित संघ राज्यक्षेत्र में परिचालित समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगी और यदि आवश्यक हो तो आयोग सभी पणधारियों की सूचना के लिए उनका प्रचार करेगा। प्रकाशन में आयोग द्वारा अपेक्षित अन्य बातों के अलावा अनुमोदित टैरिफ का साधारण विवरण और इसके प्रभाव सम्मिलित होंगे।

32. टैरिफ का पुनरीक्षण

- (i) अवधारित टैरिफ साधारण तथा एक वित्तीय वर्ष में एक से अधिक बार संशोधित या उपांतर्गत नहीं किया जाएगा सिवाए किसी ईंधन अधिभार सूत्र के निबंधनों के अधीन प्रकटतः अनुज्ञेय किसी परिवर्तन के संबंध में, जैसा कि आयोग द्वारा उपबंधित किया जाए।

- (ii) अधिनियम की धारा 62 (4) के निबंधनों में टैरिफ में संशोधन के लिए सभी आवेदनपत्र ऐसे प्ररूप में किए जाएंगे जैसा कि आयोग, समय-समय पर निदेशित करें और अध्याय-2 के उपबंध, जहां तक वे लागू हो सकें, टैरिफ के अवधारण/संशोधन/उपांतरण के लिए कार्यवाहियों को लागू होंगे ।

33. विभेदी टैरिफ और प्रति सहायकीकरण

इन विनियमों के अधीन खुदरा टैरिफ अवधारित करते समय, आयोग उपभोक्ता के भार कारक, विद्युत कारक, वोल्टेज, किसी अवधि के दौरान उपभोक्ता द्वारा की गई ऊर्जा की कुल खपत या समय जिसके दौरान प्रदाय अपेक्षित हो या किसी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, प्रदाय की प्रकृति और प्रयोजन, जिसके लिए प्रदाय अपेक्षित हो, के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न टैरिफ नियत कर सकेगा ।

34. सरकार से सहायिकी

- (i) संबंधित सरकार, किसी भी समय जब वह समुचित समझे, आयोग द्वारा अवधारित टैरिफ में किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के किसी वर्ग को कोई सहायिकी प्रदान करने का प्रस्ताव कर सकेगी और ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने पर आयोग सहायिकी के रूप में संदत्त की जाने वाली रकम और संबंधित सरकार द्वारा सहायिकी के विनिश्चय से प्रभावित व्यक्ति को सहायिकी रकमों के संदाय की शीति सहित ऐसे संदाय के निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट करेगा ।
- (ii) टैरिफ का अवधारण करते समय, आयोग किसी ऐसी सहायिकी पर विचार करेगा जो संबंधित सरकार किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के किसी वर्ग को देने के लिए सहमत थी ।
- (iii) ऊपर उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, संबंधित सरकार का कोई भी निदेश क्रियाशील नहीं होगा यदि संबंधित सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 65 के उपबंधों के अनुसरण में सहायिकी रकम का अग्रिम संदाय नहीं किया जाता है और आयोग द्वारा नियत टैरिफ इस संबंध में आयोग द्वारा जारी आदेश की तारीख से लागू होगा ।
- (iv) वितरण अनुज्ञप्तिधारी से आयोग के समाधानप्रद रूप में ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा की जाती है कि संबंधित सरकार से वितरण अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त सहायिकी रकम को सम्भवतः हिसाब में लिया गया है और उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए सहायिकी दी जाती है ।

अध्याय - 5

अनुज्ञप्ति35. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन-पत्र

- (i) इसमें अंतर्विष्ट विनियम ऐसे सभी व्यक्तियों को लागू होंगे जो गोवा राज्य तथा अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षदीप और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्रों के भीतर विद्युत के पारेषण, वितरण या व्यापार के कारबार में लगने के इच्छुक हैं।
- (ii) अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन, अधिनियम के उपबंधों और इन विनियमों के अनुसार किया जाएगा।
- (iii) आयोग, यदि समुचित समझे, विद्युत के पारेषण, वितरण या व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन मांगने के लिए, समाचार पत्रों में विज्ञापन दे सकेगा या अन्यथा किसी ऐसी समुचित रीति में अधिसूचित कर सकेगा जैसा आयोग विनिश्चित करें।
- (iv) अनुज्ञप्ति के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर होंगे और उसे सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को भेजा जाएगा जिसे आयोग इस निमित्त पदाभिहित करें तथा इसमें निम्नलिखित होंगे:-

(क) प्रारूप के बाहर मुद्रित आवेदक और इसके अभिकर्ता (यदि कोई हो) के नाम और पते के साथ आवेदक द्वारा यथा प्रस्तावित प्रारूप अनुज्ञप्ति की छह मुद्रित प्रतियां और एक साफ्ट प्रति;

(ख) प्रस्तावित सेवा क्षेत्र के नक्शे की तीन प्रतियां, जिनमें प्रत्येक पर आवेदक के हस्ताक्षर हों, और ऐसी गलियों तथा सड़कों के मामले में जहां विद्युत का प्रदाय किया जाना है, उन्हें ऐसे चिह्नित या रंगदार किया जाएगा जिससे कि उस क्षेत्र के किसी भाग और गलियों या सड़कों की इस प्रकार पहचान हो सके कि वे किसी स्थानीय प्राधिकरण के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं और ये निम्नलिखित माप में होंगे:-

- (i) अधिकतम माप के प्रायः उपलब्ध नक्शों से कम माप के न हों; या
- (ii) ऐसे अन्य माप जो आयोग द्वारा अनुमोदित हो;

- (ग) किंही स्थानीय प्राधिकरणों की सूची जिनमें पारेषण या प्रदाय के क्षेत्र के किसी भाग का प्रशासन चिह्नित हो;
- (घ) किसी ऐसी भूमि को वर्णित करने वाला सन्निकट विवरण जिसे अनुज्ञप्ति के प्रयोजन के लिए अर्जित किए जाने का आवेदक का प्रस्ताव है और ऐसे अर्जन के लिए साधन;
- (ङ) उपयोगिता और ऐसी अन्य विशिष्टियों के संबंध में, जैसा कि आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए, व्यय किए जाने के लिए प्रस्तावित पूंजी का सन्निकट विवरण;
- (च) संगम-ज्ञापन और अनुच्छेदों, गत तीन वर्षों के वार्षिक लेखा या अन्य वैसी ही दस्तावेजों की एक प्रति, जैसा कि आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए;
- (छ) उपरोक्त विवरणों पर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा साथ में लगाए गए टिप्पण और प्रमाणन, यदि कोई हो;
- (ज) कार्यवाही करने की ऐसी फीस की प्राप्ति, जैसा कि आयोग द्वारा अपेक्षा की जाए;
- (झ) तकनीकी, पूंजी पर्याप्तता और विश्वसनीयता सहित आवेदक के ब्यौरे;
- (ञ) वह क्षेत्र दर्शाते हुए जिसमें प्रदाय किया जाना है, पारेषण/वितरण प्रणाली का विन्यास । नक्शों में स्पष्ट रूप से विद्युत का पारेषण/प्रदाय किए जाने के प्रयोजन के लिए विद्यमान प्रणाली और नई सुविधाओं, जो उपलब्ध कराई जा रही हैं या जिनका उपलब्ध किया जाना अपेक्षित है, के मध्य स्पष्ट रूप से विभेद किया जाएगा । नक्शे, उप-केंद्र, वितरण लाइन, पारेषण/वितरण तंत्र, ऐसी गलियां और सड़कें उपदर्शित की जाएंगी जिन पर विभिन्न उपभोक्ताओं को ऊर्जा का प्रदाय किया जाएगा तथा लोक और प्राइवेट उपभोक्ताओं के बीच विभेद होगा;
- (ट) स्थानीय प्राधिकरण से सहमति की ईप्सा करने वाले पत्र की प्रति या सहमति पत्र;

(ठ) अधिनियम की धारा 15 (2) (ii) के अनुसार केंद्रीय सरकार से सहमति की ईप्सा करने वाले पत्र की प्रति या सहमति पत्र ।

(v) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में कार्य करने की आशा करने वाला कोई भी व्यक्ति, आवेदन करने पर तुरंत ऐसे आवेदन-पत्र की एक प्रति राज्य पारेषण उपयोगिता को भेजेगा । राज्य पारेषण उपयोगिता आवेदनपत्र की अभिस्वीकृति जारी करेगी और उक्त आवेदन पत्र प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर अपनी सिफारिशें, यदि कोई हों, आयोग को भेजेगी ।

36. लोक निरीक्षण के लिए नक्शों और प्रारूप अनुज्ञप्ति की प्रतियां

आवेदक अपने कार्यालय में और अपने अभिकर्ताओं (यदि कोई हों) के कार्यालय में निम्नलिखित रखेगा और उन्हें ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय में जमा कराएगा जिसमें प्रदाय के प्रस्तावित क्षेत्र के किसी भाग का प्रशासन निहित हो:

- (i) लोक निरीक्षण के लिए उपरोक्त विनियम 36 (iv) (ख) में निर्दिष्ट नक्शों की प्रतियां; और
- (ii) प्रारूप अनुज्ञप्ति की प्रतियों की पर्याप्त संख्या आवेदन करने वाले सभी व्यक्तियों को सामान्य फोटो कापी के प्रभारों से अधिक कीमत पर उपलब्ध कराई जाएंगी ।

37. प्रारूप अनुज्ञप्ति की अंतर्वस्तु

प्रारूप अनुज्ञप्ति में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी:

- i. आवेदक के पते और वर्णन और यदि आवेदक कंपनी है तो कंपनी के सभी निदेशकों के नामों के साथ प्रस्तावित उपयोगिता वर्णित करने वाला संक्षिप्त नाम;
- ii. आवेदित अनुज्ञप्ति का प्रकार;
- iii. प्रस्तावित सेवा क्षेत्र की अवस्थिति;
- iv. प्रस्तावित क्षेत्र का वर्णन; और
- v. ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसा आयोग निदेश करें ।

38. अनुज्ञप्ति की शर्तें

क. साधारण शर्तें, जिनके अधीन अनुज्ञप्ति का प्रत्येक प्रवर्ग आयोग द्वारा अधिकथित किया जाएगा;

- ख. आयोग, ऐसी विशेष शर्तों पर विनिश्चय कर सकेगा जिनके अधीन आवेदक को अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी;
- ग. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति, आयोग द्वारा अधिकथित शर्तों और अपेक्षाओं का संभवतः अनुपालन करेगा ।

39. प्रारूप अनुज्ञप्ति का प्रारूप

आयोग, समय-समय पर, जारी की जाने वाली अनुज्ञप्तियों का प्रारूप विहित कर सकेगा और अनुज्ञप्तियों का इस प्रारूप का उपयोग ऐसे परिवर्तनों के साथ, जैसा कि प्रत्येक मामले में परिस्थितियों से अपेक्षित हो, इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा ।

40. आवेदन-पत्र की अभिस्वीकृति

आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्त करने वाला अधिकारी उस पर प्राप्त होने की तारीख लिखेगा और प्राप्ति की तारीख लिखकर उसकी अभिस्वीकृति आवेदक को भेजेगा ।

41. अतिरिक्त सूचना मांगा जाना

आयोग या सचिव या आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, आवेदन पत्र की समीक्षा करने के बाद आवेदक से ऐसी अवधि के भीतर, जिसका वह निदेश दे, ऐसी अतिरिक्त सूचना या विशिष्टियों या दस्तावेजों की अपेक्षा कर सकेगा जो आवेदन पत्र पर विचार करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों ।

42. आवेदन पत्र की सम्यक् फाइलिंग को अधिसूचित करना

यदि आयोग, आवेदन को अपेक्षित सूचना, विशिष्टियों और दस्तावेजों के साथ पूर्ण पाता है और यह पाता है कि आवेदक ने आवेदन की सभी अपेक्षाओं तथा सूचना, विशिष्टियों और दस्तावेजों को पूरा किया है तो आयोग या सचिव यह प्रमाणित करेगा कि आवेदन लागू विधियों के अनुसरण में अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए विचार किए जाने हेतु तैयार है ।

43. आवेदन और उसकी अंतर्वस्तु का ज्ञापन

- क. जब तक लागू विधियों/आयोग द्वारा छूट प्राप्त न हो, आवेदक आवेदन ग्रहण किए जाने के 7 दिनों के भीतर, सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा अपने आवेदन की एक

सूचना प्रकाशित करेगा और इस विज्ञापन में ऐसी विशिष्टियां होगी जैसा कि इन विनियमों में आयोग द्वारा निर्दिष्ट की गई हो;

- ख. विज्ञापन के शीर्ष पर प्रारूप अनुज्ञप्ति के शीर्ष पर दिए गए संक्षिप्त नाम के तत्समान संक्षिप्त नाम होगा और इसमें ऐसे कार्यालयों के पते दिए जाएंगे जहां पर इसमें निर्दिष्ट नक्शों की प्रतियों का निरीक्षण किया जा सकेगा और प्रारूप अनुज्ञप्ति का अवलोकन या क्रय किया जा सकेगा और इसमें यह कथन होगा कि प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, उपयोगिता या व्यक्ति, जो आयोग को आवेदन के संबंध में कोई अभ्यावेदन/आक्षेप करने के इच्छुक हों वह प्रथम विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे आयोग इस निमित्त अभिहित करें, संबोधित पत्र द्वारा ऐसा कर सकेगा।
- ग. आयोग यह निदेश दे सकेगा कि आवेदन की सूचना की तामील केंद्रीय सरकार, संबंधित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति या निकाय पर, जैसा कि आयोग निदेश दे ऐसी अन्य रीति में की जाए जो आयोग समुचित समझे। इसके अलावा, किसी ऐसे क्षेत्र के लिए अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन के मामले में जिसमें किसी छावनी, विमान क्षेत्र, किले, आयुधशाला, गोदीबाड़ा या कैम्प पूर्णतः या भागतः अथवा रक्षा प्रयोजन के लिए सरकार के अधिभोग में कोई भवन या स्थान सम्मिलित हैं, आयोग यह सुनिश्चित करने के बाद ही अनुज्ञप्ति जारी करेगा कि केंद्रीय सरकार को अनुज्ञप्ति जारी किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

44. प्रारूप अनुज्ञप्ति का संशोधन

ऐसा व्यक्ति जो प्रारूप अनुज्ञप्ति में कोई संशोधन करने का इच्छुक हो, वह समाचार पत्रों विज्ञापन के माध्यम से आवेदन की सूचना प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर संशोधन का एक विवरण आवेदक और सचिव या ऐसी अधिकारी को परिदत्त कर सकेगा जिसे आयोग इस निमित्त अभिहित करें।

45. आक्षेप

- क. अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने पर आक्षेप करने की आशा करने वाला कोई व्यक्ति समाचार पत्रों में आवेदन की सूचना प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आक्षेप फाइल करेगा। आक्षेप उत्तर के रूप में फाइल किए जाएंगे और ऐसे आक्षेप फाइल करने में उत्तर की बाबत अध्याय-2 के उपबंध लागू होंगे।
- ख. जब लागू हो, आवेदक, अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आयोग द्वारा सुनवाई हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने के पूर्व केंद्रीय सरकार से अपेक्षित अनापत्ति के लिए आवेदन करेगा और उसे प्राप्त करेगा।

46. स्थानीय जांच और सुनवाई

- क. यदि आवेदक ने आशयित आवेदन पत्र की सूचना के प्रकाशन के लिए सम्भवतः व्यवस्था की है और आक्षेप फाइल करने का समय समाप्त हो गया है तो आवेदक इस अनापत्ति, यदि वह केंद्रीय सरकार द्वारा अपेक्षित हो, आयोग में प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात्, आयोग नियमित सुनवाई के लिए आवेदन पर कार्यवाही करेगा।
- ख. आयोग, आवेदक, ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने आक्षेप फाइल किए हों, केंद्रीय सरकार, संबंधित सरकार और ऐसे अन्य प्राधिकारी, व्यक्ति या निकाय को जांच या सुनवाई की सूचना देगा, जैसा कि आयोग समुचित समझे।
- ग. आयोग, अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में राज्य पारेषण उपयोगिता से प्राप्त सिफारिशों पर, यदि कोई हों, विचार करेगा।
- घ. यदि आवेदक की गई अनुज्ञप्ति पर कोई व्यक्ति आक्षेप करता है तो आयोग, यदि आवेदक या आक्षेपकर्ता में से कोई ऐसी इच्छा करें, स्थानीय जांच करवाएगा जिसके लिए आवेदक और आक्षेपकर्ता दोनों को लिखित में सूचना दी जाएगी:

परंतु यह कि यदि आयोग की राय में आक्षेप तुच्छ या कष्टप्रद प्रकृति का है तो वह जांच से इंकार कर सकेगा।

- ड. ऐसी स्थानीय जांच के मामले में, की गई स्थानीय जांच के परिणामों का एक ज्ञापन तैयार किया जाएगा जिसे आवेदक, अधिकारी या इस प्रयोजन के लिए अभिहित व्यक्ति और ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जैसा आयोग निदेश करें।
- च. तत्पश्चात् अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन पर सुनवाई, जहां तक संभव हो, अध्याय-2 में दी गई रीति से की जाएगी।

47. प्रारूप अनुज्ञप्ति का अनुमोदन

- क. जांच, यदि कोई हो, और सुनवाई के पश्चात्, आयोग अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उससे इंकार करने का विनिश्चय कर सकेगा और यदि वह अनुज्ञप्ति प्रदान करने का विनिश्चय करता है तो वह ऐसा ऐसे उपांतरणों, परिवर्तनों या परिवर्धनों के साथ और ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों के अधीन, जैसा कि आयोग निदेश करें, प्रारूप अनुज्ञप्ति का अनुमोदन करके कर सकेगा।
- ख. जब कोई प्रारूप अनुज्ञप्ति आयोग द्वारा चाहे मूल रूप से या उपांतरित रूप में अनुमोदित की जाए तो सचिव या ऐसा अन्य अधिकारी, जो आयोग इस निमित्त पदाभिहित करे, आवेदक को ऐसे अनुमोदन और उस रूप की जिसमें अनुज्ञप्ति

- प्रदान किया जाना प्रस्तावित है तथा अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदक द्वारा संदत्त की जाने वाली फीस सहित ऐसी शर्तों की सूचना देगा जिनका समाधान आवेदक द्वारा किया जाना है ।
- ग. कोई भी अनुज्ञप्ति प्रदान करने, आयोग ऐसे दो दैनिक समाचार पत्रों में, जैसा आयोग आवश्यक, समझे, उस व्यक्ति का नाम और पता बताते हुए जिसे इसके द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है, एक सूचना प्रकाशित करेगा ।
- घ. आयोग, अनुज्ञप्ति जारी किए जाने के तुरंत पश्चात्, अनुज्ञप्ति की एक-एक प्रति संबंधित सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण और ऐसे अन्य व्यक्तियों को भेजेगा जैसा आयोग आवश्यक समझे ।

48. अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने की अधिसूचना

आवेदक से लिखित में ऐसी सूचना प्राप्त होने पर कि वह आयोग द्वारा अनुमोदित रूप में अनुज्ञप्ति स्वीकार करने का इच्छुक है तथा अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए अधिरोपित शर्तों का आवेदक द्वारा समाधान किए जाने के पश्चात् आयोग अनुज्ञप्ति या उसका ऐसा भाग या सार प्रकाशित करेगा जैसा आयोग समुचित समझे ।

49. अनुज्ञप्ति के प्रारंभ की तारीख और अवधि

अनुज्ञप्ति उस तारीख से प्रारम्भ होगी जैसा आयोग अनुज्ञप्ति के प्रारम्भ की तारीख का निदेश दे और यह 25 वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी यदि इसे पहले प्रतिसंहरित न की जाए ।

50. नक्शे जमा करना

जब अनुज्ञप्ति प्रदान कर दी जाए तो ऐसी अनुज्ञप्ति की बाबत उपरोक्त विनियम 25 (iv) (ख) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां दर्शाने वाले नक्शों के 3 सेट सचिव या आयोग द्वारा अभिहित किसी अन्य अधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने की अधिसूचना की तारीख के तत्स्थानी रूप में हस्ताक्षरित और दिनांकित किए जाएंगे । ऐसे नक्शों का एक सेट उक्त अधिकारी द्वारा जमा नक्शे के रूप में रखा जाएगा और अन्य दो सेट अनुज्ञप्तिधारी को दिए जाएंगे ।

51. मुद्रित प्रतियां जमा करना

प्रत्येक व्यक्ति, जिसे अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो, इसके प्रदान किए जाने के तीस दिनों के भीतर ----

- क.
 - i. अनुज्ञप्ति की पर्याप्त संख्या में प्रतियां मुद्रित करवाएगा;
 - ii. अनुज्ञप्ति में कथित प्रदाय क्षेत्र दर्शाते हुए नक्शों की पर्याप्त संख्या तैयार करवाएगा;
 - iii. अपने प्रधान कार्यालय, अपने स्थानीय कार्यालय (यदि कोई हो) और प्रदाय के क्षेत्र में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय पर सभी युक्तियुक्त समयों पर लोक निरीक्षण के लिए ऐसी अनुज्ञप्ति और नक्शों की एक-एक प्रति प्रदर्शित करने की व्यवस्था करेगा;
- ख. ऐसा प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, उपरोक्त तीस दिनों की अवधि के भीतर, अनुज्ञप्ति और सुसंगत नक्शों की एक-एक प्रति, प्रदाय के क्षेत्र में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को निःशुल्क प्रदान करेगा और अनुज्ञप्ति की मुद्रित प्रतियों के विक्रय के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा जिससे कि वह सामान्य फोटो कापी प्रभारों से अधिक कीमत पर आवेदन करने वाले व्यक्तियों को दी जा सके ।

52. लेखाओं की तैयारी और प्रस्तुत किया जाना

- क. प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी हर वर्ष 31 मार्च तक अपनी उपयोगिता के लेखा तैयार करवाएगा ।
- ख. ऐसा अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संपरीक्षित लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा और उपरोक्त तारीख से वह मास की अवधि के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि में, जो आयोग अपना यह समाधान होने पर प्राधिकृत करें कि अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण के बाहर कारणों से अनुज्ञात अवधि अपर्याप्त थी, आयोग में प्रस्तुत करेगा तथा विवरण की प्रतियों की ऐसी संख्या प्रस्तुत की जाएगी जैसा कि आयोग निदेश करें ।
- ग. लेखा ऐसी रीति में तैयार किए जाएंगे जैसा आयोग समय-समय पर निदेश दे । सभी फार्मों पर अनुज्ञप्तिधारी या उसका प्रत्यायित तथा सम्यक्तः प्राधिकृत अभिकर्ता या प्रबंधक हस्ताक्षर करेगा ।
- घ. आयोग, किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि उपरोक्त उपविनियम (iii) में निदेशित फार्मों में लेखाओं के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के अलावा अनुज्ञप्तिधारी आयोग या ऐसे अन्य प्राधिकारी के पास, जिसे वह इस निमित्त अभिहित करे, ऐसी अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करेगा जिसकी इस प्रयोग के लिए वह अपेक्षा करे ।

53. प्रदाय की मॉडल शर्तें

- क. आयोग, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपनाई जाने वाली और अनुपालन की जाने वाली प्रदाय की मॉडल शर्तें, ऐसे परिवर्तनों के साथ निर्दिष्ट करेगा जैसा कि आयोग समय-समय पर निदेश करे।
- ख. अनुज्ञप्तिधारी अपने कार्यालय में सदैव समय-समय पर यथा संशोधित इन विनियमों के अध्याय-9 के उपबंधों के अधीन तैयार की गई संहिताओं की मुद्रित प्रतियों की पर्याप्त संख्या रखेगा और मांग किए जाने पर इन प्रतियों का विक्रय किसी आवेदक को ऐसी कीमत पर करेगा जो सामान्य फोटोप्रति प्रभारों से अधिक न हों तथा दस्तावेजों के उपयुक्त प्रचार के लिए कदम उठाएगा।

54. अनुज्ञप्ति का उल्लंघन

- क. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, अनुज्ञप्ति के किसी निबंधन या शर्त, लागू विधि के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम उल्लंघन किए जाने या उल्लंघन की संभावना पर आयोग अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अनुसरण में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।
- ख. अधिनियम के उपबंधों के अधीन आयोग, जहां तक संभव हो, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए या संभावित उल्लंघन से उत्पन्न कार्यवाहियों पर विचार करते समय इन विनियमों के अध्याय-2 में निदेशित साधारण प्रक्रिया अपनाएगा।

55. वितरण अनुज्ञप्ति प्रदान समझा जाना

- क. जब तक आयोग द्वारा अन्यथा निदेशित न किया जाए, गोवा राज्य तथा अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्रों में विद्युत के प्रदाय में लगे हुए व्यक्तियों के निम्नलिखित वर्गों के बारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने वितरण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया है और जो उन्हें इसमें अंतर्विष्ट प्रयोजनों के लिए और नीचे उप विनियम (ख) में अंतर्विष्ट शर्तों के पूरा करने के अधीन रहते हुए, प्रदत्त समझा जाएगा:

- i. ऐसे व्यक्ति, जो स्वयं द्वारा उत्पादित और/या किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उन्हें प्रदाय की गई विद्युत दो मास से अधिक किसी धटना या समारोह के

प्रयोजनों के लिए करते हैं और जब विद्युत का वितरण उनके स्वामित्व वाली प्रणाली के माध्यम से किया जाए;

- ii. ऐसे व्यक्ति, जो अपने कर्मचारियों के उपयोग और अधिभोग के लिए अपनी क्रिया विधि के भाग के रूप में आवासीय कालोनियों के रखरखाव हेतु इन कालोनियों में विद्युत का प्रदाय करते हैं और/या कर्मचारियों को सुविधाएं तथा सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों के उपयोग और अधिभोग के लिए, जहां ऐसे व्यक्ति विद्युत का उपापन किसी अनुज्ञप्तिधारी या आयोग द्वारा अनुमोदित किसी अन्य स्रोत से करते हैं और आवासीय कॉलोनिनों में विद्युत का वितरण कोई लाभ उद्देश्य से नहीं करते हैं;
- iii. ऐसे अन्य व्यक्ति, जैसा आयोग समय-समय पर आदेश द्वारा अधिसूचित करे, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा आयोग निदेश दे ।

ख. उपरोक्त अधिनियम (i) में निर्दिष्ट व्यक्ति:

- i. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्युत में व्यापार नहीं करेंगे या अपने प्रचालन क्षेत्र के बाहर विद्युत का वितरण या प्रदाय नहीं करेंगे तथा विद्युत का वितरण या प्रदाय कड़ाई के साथ उपरोक्त उपविनियम (i) में उल्लिखित प्रयोजन तक सीमित रहेगा;
- ii. प्रचालन के क्षेत्र के भीतर ही विद्युत लाइन या संकर्मों की स्थापना करेंगे;
- iii. यदि ऐसा अपेक्षित हो, आयोग के कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित ऐसी सूचना आयोग में प्रस्तुत करेंगे जैसा कि आयोग समय-समय पर निदेश करे;
- iv. अधिनियम के उपबंधों, आयोग के विनियमों तकनीकी संहिताएं जैसे ग्रिड संहिता, वितरण सहित, निष्पादन के मानकों और आयोग द्वारा जारी निष्पादन संपूर्ण मानकों और मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करेंगे;
- v. प्रचालन की रक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करेंगे; और
- vi. ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे, जो आयोग, समय-समय पर, ऐसे प्रभारों की बाबत दे, जिन्हें ऐसे व्यक्ति किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त विद्युत के प्रदाय के निकटवर्ती क्षेत्र में प्रचलित प्रभारों पर विचार करके उपभोक्ताओं से उद्गृहीत करें ।

ग. आयोग, समय-समय पर, ऐसे समुचित निदेश जारी करने का हकदार होगा जिन्हें वह आवश्यक समझे और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध अधिनियम के उपबंधों और इन विनियमों के अनुसार, इनके किसी अतिलंघन या अननुपालन के लिए कार्रवाई करने का हकदार होगा ।

घ. आयोग, किसी भी प्रक्रम पर, यदि उसे आवश्यक प्रतीत हो, ऐसे व्यक्तियों को विनियम 35 के अनुसरण में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने का निदेश दे सकेगा और तदनुसार, अनुज्ञप्ति प्रदान करने या उससे इंकार करने पर विचार कर सकेगा तथा किसी अंतरिम या स्थायी आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को प्रचालन के किसी क्षेत्र या उसके भाग में विद्युत का वितरण या प्रदाय न करने का निदेश दे सकेगा।

ड. यदि कोई ऐसा मतभेद या विवाद उत्पन्न हो जाए कि क्या वह व्यक्ति अनुज्ञप्तिधारी के रूप में इस विनियम 55 के उपबंधों के अधीन विद्युत का प्रदाय करने का हकदार है या नहीं तो इस पर आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा।

56. अनुज्ञप्ति से छूट प्रदान करना

अनुज्ञप्ति से छूट ऐसी रीति में प्रदान की जाएगी जो लागू विधि और अधिनियम के उपबंधों के संगत हो।

57. अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण

- क. अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए कार्यवाहियां या अधिनियम की धारा 19 में यथा कथित किसी अन्य आदेश का पारित किया जाना, आयोग द्वारा पारित आदेश से प्रारम्भ होंगे जिसे आयोग स्वप्रेरणा से या अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर या किसी अन्य व्यक्ति से कोई शिकायत या सूचना प्राप्त होने पर शुरू कर सकेगा।
- ख. प्रतिसंहरण का प्रक्रिया और रीति, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम की धारा 19 उपबंधों के संगत होगी।
- ग. अधिनियम के उपबंधों और इनमें अंतर्विष्ट प्रक्रिया के अधीन रहते हुए, अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण पर आयोग द्वारा जांच, जहां तक लागू हो, उसी रीति से की जाएगी जैसा कि इन विनियमों के अध्याय-2 में उपबंधित है।
- घ. अनुज्ञप्तिधारी जो स्वयं अपनी अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण या भागतः प्रतिसंहरण के लिए आवेदन की इच्छा करता है या सहमति देता है, आयोग में आवेदन कर सकेगा। ऐसे आवेदनों पर आयोग अनुज्ञप्तिधारी और ऐसे अन्य व्यक्तियों को सुनने के पश्चात् जिन्हें वह उपयुक्त समझें, आदेश पारित करेगा। ऐसे आवेदन पर आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जहां तक संभव हो, वैसी होगी जो इन विनियमों के अध्याय-2 में उपबंधित है।

58. प्रदान की गई अनुज्ञप्ति का संशोधन

- क. अनुज्ञप्ति का संशोधन, अधिनियम की धारा 18 में अधिकृत रीति में किया जाएगा । जब तक आयोग द्वारा लिखित में अन्यथा निदेशित न किया जाए, अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया को, जहां तक इसे लागू किया जा सके, अनुज्ञप्ति के संशोधन या उसमें परिवर्तन के लिए आवेदन पर विचार करते समय अपनाया जाएगा ।
- ख. अनुज्ञप्ति के संशोधन के लिए आवेदन के साथ प्रस्तावित संशोधन का एक कथन होगा जो इन विनियमों के अध्याय-2 में यथा उपबंधित एक शपथपत्र द्वारा समर्थित होगा ।
- ग. जब तक आयोग द्वारा लिखित में अन्यथा निदेशित न किया जाए, अनुज्ञप्ति में संशोधन या परिवर्तन के लिए आवेदन के साथ ऐसी फीस की रसीद लगी होगी जैसा आयोग द्वारा अपेक्षित हो और आयोग द्वारा निदेशित रीति में सदत्त की गई हो ।
- घ. आवेदक, आवेदन ग्रहण और संस्थापित किए जाने की तारीख से सात दिनों के भीतर प्रस्तावित संशोधन का एक संक्षिप्त कथन, प्रस्तावित संशोधन के लिए कारण, प्रदान की गई अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के कृत्यों के निर्वहन पर प्रस्तावित संशोधन के प्रभाव, कृत्यों के ऐसे निर्वहन के लिए वैकल्पिक प्रस्तावित व्यवस्था और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो आयोग निदेशित करे, देते हुए, फाइल किए गए संशोधन आवेदनपत्र की सूचना प्रकाशित करेगा । प्रकाशन में कार्यालयों के ऐसे पते दिए जाएंगे जहां पर संशोधन के लिए आवेदन का निरीक्षण किया जा सके तथा दस्तावेजों की प्रतियां क्रय की जा सकें और इसमें यह कथन होगा कि आवेदन के संबंध में कोई आवेदन आयोग को करने का इच्छुक प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, उपयोगिता या व्यक्ति, ऐसे अधिकारी को, जैसा इस निमित्त आयोग द्वारा अभिहित किया जाए, संबोधित एक पत्र द्वारा प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऐसा कर सकेगा ।

59. वितरण अनुज्ञप्ति का निलंबन

यदि किसी समय, आयोग की यह राय हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो यह लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी की अनुज्ञप्ति अधिनियम की धारा 24 में दी गई परिस्थितियों, रीति और रूप में से निलंबित कर सकेगा ।

60. अनुज्ञप्तिधारी के विद्युत क्रय का विनियमन

- क. अनुज्ञप्तिधारी, उसके द्वारा पहले से किए गए सभी विद्युत क्रय करारों की प्रतियां पूर्ण रूप में आयोग के पास फाइल करेगा।
- ख. आयोग यह निदेश करने का हकदार होगा कि अनुज्ञप्तिधारी आयोग के समाधानप्रद रूप में यह स्थापित करे कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत का क्रय एक पारदर्शी विद्युत क्रय उपापन प्रक्रिया के अधीन है और किफायती है तथा अनुज्ञप्तिधारी के लिए सेवा बाध्यता पूरा करने हेतु विद्युत आवश्यक है।
- ग. अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे प्रारूप क्रय करार के अनुमोदन के लिए आयोग को आवेदन करेगा जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। आयोग निम्नलिखित आदेश पारित कर सकेगा:
- i. करार का अनुमोदन करेगा; या
 - ii. करार की शर्तों में प्रस्तावित उपांतरणों के साथ करार का अनुमोदन करेगा; या
 - iii. करार अस्वीकार करेगा।
- घ. इसमें अंतर्विष्ट कोई बात, विद्यमान संविदाओं और उत्पादन कंपनियों, विद्युत व्यापारियों और ऐसे अन्य व्यक्तियों से, जिनके साथ करारों के निबंधनों और शर्तों के अनुसरण में विद्युत क्रय या ऊर्जा उपापन के लिए अनुज्ञप्तिधारी ने करार या व्यवस्था की है, विद्युत के क्रय, आयात या अर्जन के लिए व्यवस्थाओं और आयोग द्वारा सहमत और अनुमोदित व्यवस्थाओं के अधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी की बाध्यताओं को प्रभावित नहीं करेगी।
- ड. उपरोक्त उपविनियम (ii) और (iii) के उपबंध या इसमें की गई कोई कार्रवाई, किसी भी रीति में, लागू विधि के अन्य उपबंधों, समय-समय पर जारी किए जाने वाले विनियमों और आदेश के अधीन आयोग के कृत्यों के निर्वहन और शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

61. कार्य-निष्पादन के मानक

आयोग, अनुज्ञप्तिधारियों और संभावित प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से परामर्श के पश्चात् किसी अनुज्ञप्तिधारी या अनुज्ञप्तिधारियों के वर्ग के लिए ऐसे कार्य-निष्पादन मानक निर्दिष्ट कर सकेगा जो उसकी राय में ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्राप्त हैं और प्राप्त किए जाने चाहिए तथा विभिन्न अनुज्ञप्तिधारियों के लिए विभिन्न मानक अवधारित किए जा

सकते हैं। आयोग, इस प्रकार अवधारित मानक ऐसे रूप और ऐसी रीति में प्रकाशित कर सकेगा जैसा आयोग समुचित समझे।

अध्याय 6 विनिधान अनुमोदन

62. आयोग द्वारा विनिधान अनुमोदन की अपेक्षा

- (i) जब तक आयोग द्वारा अन्यथा निदेश न किया जाए, प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्त कारबार में विनिधान के लिए यदि ऐसा विनिधान अनुज्ञप्ति शर्तों में अधिकथित सीमाओं के ऊपर है, आयोग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।
- (ii) अनुज्ञप्ति शर्तों में दी गई सीमा आयोग द्वारा समय-समय पर एक साधारण या विशेष आदेश द्वारा उपांतरित की जा सकेगी।
- (iii) विनिधान अनुमोदन के लिए आवेदनपत्र में, अनुज्ञप्तिधारी निम्नलिखित सूचना और विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा:-
 - (क) एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसमें किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा, विनिधान के लिए आवश्यकता प्रदर्शित करने वाली मुख्य विशेषताओं और विशिष्टियों के साथ आर्थिक तकनीकी प्रणाली की परीक्षा तथा विनिधान के पर्यावरणीय पहलू सम्मिलित हों;
 - (ख) लागत-फायदा विश्लेषण के साथ परियोजना लागत;
 - (ग) क्या विनिधान नई परियोजना में है अथवा विद्यमान प्रणाली के विस्तारण या उन्नयन के लिए है;
 - (घ) परियोजना के निष्पादन के लिए मंजूरियां और कानूनी समाशोधन और ऐसी मंजूरियों तथा समाशोधनों की प्रास्थिति;
 - (ङ.) वित्तीय वर्षों के दौरान विनिधान की चरणबद्धता और कमीशन अनुसूची;
 - (च) वह रीति, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी की राजस्व अपेक्षाओं में सम्मिलित किए जाने के प्रयोजनों के लिए विनिधान पूंजीबद्ध होंगे;
 - (छ) विनिधान करने या परियोजना क्रियान्वित करने में अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष आने वाले अवरोध, जिसमें उपलब्ध जानकारी पर अवरोध भी है;
 - (ज) विनिधान पूरा करने के लिए संसाधन गतिशीलता और वित्तीय योजना;
 - (झ) पारदर्शी निविदा प्रक्रिया, जो आयोग द्वारा अनुमोदित की जा सके, के अनुसरण में उपस्कर, सामग्री के उपापन और/या विनिधान के संबंध में

- सेवाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित करने और उन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया; और
- (अ) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जिनका आयोग समय-समय पर निदेश दे ।

63. आयोग द्वारा कार्यवाहियां

- (i) आयोग, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिधान के अनुमोदन के लिए आवेदन-पत्र पर विचार करते समय, अपने विवेकानुसार ऐसी जांच और परामर्श करेगा जैसा आयोग समुचित समझे ।
- (ii) आयोग, अपने विवेकानुसार, कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा या टैरिफ के अवधारण के लिए कार्यवाहियों के भाग रूप में या किसी अन्य ऐसी कार्यवाही के साथ विनिधान अनुमोदन के लिए आवेदन पर विचार कर सकेगा जैसा आयोग समुचित समझे ।
- (iii) आयोग, विनिधान अनुमोदन के लिए आवेदन पर, जिसके साथ ऐसी फीस होगी जिसका निदेश किया जाए, विचार करने के पूर्व, ऐसे परामर्शदाता, विशेषज्ञ और अन्य, जैसा आयोग समुचित समझे, नियुक्त करने और आयोग के कर्मचारिवृंद, परामर्शदाता और विशेषज्ञों को अनुज्ञप्तिधारी के साथ चर्चा करने एवं विचार करने के लिए प्राधिकृत करने का हकदार होगा ।

64. अतिरिक्त जानकारी

- (i) अनुज्ञप्तिधारी और विनिधान अनुमोदन की ईप्सा करने वाले अन्य आवेदक ऐसी जानकारी, विशिष्टियां, दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे जो आयोग के कर्मचारिवृंद, आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त परामर्शदाता और विशेषज्ञों द्वारा अपेक्षित हों और वे उनकी ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक पहुँच को अनुज्ञान करेंगे जो अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण, कब्जे या अभिरक्षा में है ।
- (ii) अनुज्ञप्तिधारी आयोग के स्टाफ, परामर्शदाताओं और विशेषज्ञों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने तथा उनके निष्कर्षों के परिणाम पर एक रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने के लिए उनके साथ सहयोग करेगा ।

अध्याय 7 विवादों का निपटारा

65. मध्यस्थता

- (i) अनुज्ञप्तिधारियों और उत्पादन कंपनियों के बीच कोई विवाद आयोग के समक्ष लाए जाने पर या अन्यथा आयोग की जानकारी में आने पर, आयोग उस पर न्यायनिर्णयन या मध्यस्थता के लिए कार्रवाई कर सकेगा।
- (ii) यदि आयोग किसी विवाद पर स्वयं न्यायनिर्णयन करने का विनिश्चय करें तो वह ऐसे सुविज्ञों, विशेषज्ञों से सहायता ले सकेगा जैसा वह आवश्यक समझे।
- (iii) यदि आयोग मामले को मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट करने का विनिश्चय करता है तो उस पर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

66. मध्यस्थों का नामनिर्देशन

क. यदि आयोग यह विनिश्चित करता है कि मामले को आयोग से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किया जाए तो निर्देश निम्नानुसार होगा:

- i. यदि विवाद के पक्षकार मध्यस्थ के नाम पर सहमत हैं तो एकल मध्यस्थ को; या
- ii. यदि पक्षकार एकल मध्यस्थ के नाम पर सहमत होने में असमर्थ हैं तो आयोग द्वारा अभिहित किसी एकल मध्यस्थ को या विवाद की प्रकृति और अन्तर्वलित मूल्य को ध्यान में रखते हुए, जैसा आयोग निदेश दे, तीन व्यक्तियों को। यदि तीन मध्यस्थों को निर्दिष्ट करने का विनिश्चय किया जाता है तो हर दो पक्षकारों द्वारा एक-एक तथा तीसरा आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा:

परंतु यह कि यदि कोई पक्षकार मध्यस्थ नाम निर्दिष्ट करने में असफल रहता है या पक्षकारों में से नामनिर्दिष्ट कोई मध्यस्थ कार्य करने या मध्यस्थ बने रहने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है तो आयोग उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करने का हकदार होगा।

- ख. आयोग ऐसे किसी व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं करेगा जिसके संबंध में मध्यस्थता के किसी पक्षकार को संभावित पक्षपात या वैसे ही अन्य कारणों के आधार पर आपत्ति हो और आयोग को आपत्ति विधिमान्य और न्यायोचित प्रतीत हो।
- ग. मध्यस्थता और आयोग के समक्ष कार्यवाहियों की फीस और खर्च ऐसे पक्षकारों द्वारा ऐसी राशियों के लिए वहन किए जाएंगे जैसा कि आयोग निदेश दे।

67. अधिनिर्णय, निपटारा और पंचाट पारित करने के लिए प्रक्रिया

ऐसे मामले में, जहां आयोग स्वयं विवाद पर अधिनिर्णय देने का विनिश्चय करें, वहां अधिनिर्णय और निपटारे के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जहां तक संभव हो, वैसी ही होगी जैसा अध्याय-2 में उपबंधित आयोग के समक्ष सुनवाई के मामले में होती है।

अध्याय - 8

फीसों और जुर्माने

68. आवेदनों या याचिकाओं पर फीस

- क. आयोग में कोई याचिका, आवेदन या शिकायत फाइल करने के लिए संदेय फीसों वे होंगी जो इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।
- ख. इन विनियमों के अधीन संदेय फीसों का संदाय सचिव, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के पक्ष में लिखे गए गुड़गांव, हरियाणा में संदेय बैंक ड्राफ्ट या पे-ऑर्डर के माध्यम से किया जाएगा।
- ग. आयोग के सचिव द्वारा इन विनियमों के अधीन प्राप्त फीसों आयोग द्वारा चलाए जा रहे ऐसे बैंक की शाखा के बैंक खाते में जैसा आयोग समय-समय पर निदेश दे या खाते के सुसंगत शीर्ष के अधीन सरकारी खाते में जमा की जाएंगी।

69. अनुज्ञप्ति फीस

- क. आयोग, किसी व्यक्ति को विद्युत के पारेषण या प्रदाय, जिसमें विद्युत का थोक प्रदाय है, का कारबार चलाने के लिए अनुज्ञप्ति या छूट प्रदान करते समय या कोई विशेषाधिकार प्रदान करने वाला आदेश करते समय, अधिनियम के उपबंधों

और आयोग द्वारा जारी इन या कोई अन्य विनियमों के अनुसरण में संदेय फीस अनुज्ञप्ति या विशेषाधिकार प्रदान करते समय और तत्पश्चात् वार्षिक या ऐसे आवधिक आधार पर जैसा आयोग अनुज्ञप्ति या विशेषाधिकार प्रदान करने वाले आदेश में या आयोग द्वारा पारित पृथक् आदेश विनिर्दिष्ट हो, उद्गृहीत और संगृहीत कर सकेगा ।

- ख. विद्यमान अनुज्ञप्तिधारी और छूट धारक वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए और आगे वार्षिक फीस का संदाय अनुसूची में विनिर्दिष्ट तौर पर करेंगे तथा 2009-10 के पूर्व की अवधि के लिए इसका उद्ग्रहण हर मामले के आधार पर आयोग द्वारा पारित पृथक् आदेशों द्वारा किया जाएगा ।
- ग. जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, अनुज्ञप्ति या छूट प्रदान करने के लिए संदेय फीस वे होंगी जो इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।
- घ. फीसों का संदाय और रकम का जमा किया जाना उसी रीति में किया जाएगा जो ऊपर विनियम 68 में विनिर्दिष्ट है ।

70. जुर्माने और प्रभारों का अधिरोपण

- क. आयोग, किसी प्रभावित व्यक्ति से शिकायत प्राप्त होने पर यह स्वयं ही यदि आयोग की यह राय हो कि उसकी जानकारी में आए तथ्यों से प्रथम दृष्टया उत्पादक कंपनी, अनुज्ञप्तिधारी या अन्य व्यक्ति द्वारा अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी उपबंध या अपेक्षा के अननुपालन या उल्लंघन का मामला बनता है, जुर्माने और प्रभार अधिरोपित करने और प्रतिकर प्रदान करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर सकेगा ।
- ख. यदि आयोग, प्राप्त जानकारी के आधार पर यह विनिश्चित करता है कि मामले में कार्यवाही करने के लिए प्रथमदृष्टया कारण है तो मामला रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और उस व्यक्ति को सूचना में यथा उपदर्शित युक्तियुक्त समय के भीतर कारण बताओ सूचना जारी की जाएगी जो उपरोक्त उपविनियम (i) के अधीन अननुपालन या उल्लंघन का उत्तरदायी है कि वह यह स्पष्टीकरण देने के लिए आयोग के समक्ष वैयक्तिक रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से हाजिर हो कि आयोग उस पर जुर्माना या प्रभार क्यों अधिरोपित न करें । सूचना में अभिकथित अननुपालन या उल्लंघन के विशिष्ट निर्देश के साथ ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उस अभिकथन का सारांश होगा ।
- ग. हाजिर होने के लिए सूचना में दी गई नियत तारीख पर, आयोग ऐसे व्यक्ति को, जो प्रथमदृष्टया अननुपालन या उल्लंघन के लिए उत्तरदायी है या उसके प्रतिनिधि को ऐसे व्यक्ति द्वारा पारित अभिकथन, अननुपालन या उल्लंघन स्पष्ट करेगा ।

- घ. जहां अननुपालन या उल्लंघन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति सूचना के जवाब में हाजिर हो जाए और लिखित में एक ज्ञापन द्वारा अभिकथन की सत्यता को स्वीकार कर ले, वहां आयोग जवाब अभिलिखित करेगा और अधिनियम के उपबंधों तथा आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए इसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार अपने विवेकानुसार जुर्माना और प्रभार अधिरोपित कर सकेगा तथा प्रभावित पक्षकर को प्रतिकर भी प्रदान कर सकेगा ।
- ड. जहां अननुपालन या उल्लंघन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति हाजिर होकर अभिकथित उल्लंघन या अननुपालन को स्वीकार नहीं करता है और सुनवाई की मांग करता है, वहां आयोग अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अनुसार मामले की सुनवाई की कार्यवाही करेगा ।
- च. यदि कोई व्यक्ति, जिसे सूचना जारी की गई थी, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के सुनवाई के लिए नियत तारीख को या किसी पश्चातवर्ती तारीख को जिसके लिए कार्यवाहियां स्थगित की गई हो, आयोग के समक्ष हाजिर होने में असफल रहता है तो आयोग ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में अपने विवेकानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर सकेगा ।
- छ. आयोग शिकायतकर्ता की सुनवाई करेगा और ऐसा साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी, या शपथपत्र के माध्यम से प्राप्त करेगा जो मामले के समर्थन में पेश किया जाए और ऐसा समस्त साक्ष्य प्राप्त करेगा जो अननुपालन या उल्लंघन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा अपनी प्रतिष्ठा में प्रस्तुत किया जाए । जहां कार्यवाहियां आयोग द्वारा प्राप्त जानकारी पर प्रारंभ की गई हों, वहां यह अपने किसी अधिकारी को मामले में शिकायतकर्ता के तौर पर कार्य करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगा ।
- ज. कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर आयोग को ऐसे किसी व्यक्ति को समन करने और उसकी हाजिरी को बाध्य करने की शक्ति होगी जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना प्रतीत हो ताकि वह साक्ष्य प्रस्तुत करें या ऐसे दस्तावेज पेश करें जो आयोग की राय में कार्यवाहियों की विषय-वस्तु में सारवान और सुसंगत प्रतीत हों ।

71. जुर्मानों और प्रभारों का उद्ग्रहण और वसूली के लिए प्रक्रिया

- क. यदि किसी कार्यवाही के समापन पर, आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति जुर्माने या प्रभारों का दायी है तो वह अधिनियम के उपबंधों और इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट विनियमों के अनुसार लिखित में आदेश प्राप्त करके जुर्माने या प्रभार अधिरोपित कर सकेगा और प्रतिकर भी दे सकेगा ।

- ख. जुर्मानों या प्रभारों का परिमाण अवधारित करते समय, आयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करेगा:-
- i. अननुपालन या उल्लंघन की प्रकृति और विस्तार;
 - ii. अननुपालन या उल्लंघन के परिणामस्वरूप अभिप्राप्त सदोष अभिलाभ या अनुचित फायदा;
 - iii. अननुपालन या उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को कारित हानि या उत्पीड़न का परिमाण; और
 - iv. अननुपालन या उल्लंघन दोहराए जाने की प्रकृति ।
- ग. इस विनियम के अधीन आदेश पारित करते समय, आयोग शिकायतकर्ता या प्रभावित पक्षकार को प्रतिकर प्रदान कर सकेगा जिसका संदाय वह व्यक्ति करेगा जो अननुपालन या उल्लंघन कारित करने वाला पाया गया ।
- घ. आयोग ऐसे समय का निदेश दे सकेगा जिसके भीतर संबंधित व्यक्ति द्वारा जुर्माने, प्रभार या प्रतिकर का संदाय किया जाना चाहिए ।
- ड. अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप जुर्मानों और प्रभारों का संग्रहण करने के लिए आयोग किसी अधिकारी को पदाभिहित कर सकेगा ।

72. शिकायत वापस लेना और निपटारा

- क. यदि कोई शिकायतकर्ता, कार्यवाहियों के अंतिम आदेश पारित होने के पूर्व किसी भी समय आयोग का यह समाधान करा देता है कि उसे अपनी शिकायत में नामित प्रत्यर्थी के विरुद्ध या यदि वहां एक से अधिक प्रत्यर्थी हैं तो सब के या उनमें से किसी एक के विरुद्ध शिकायत वापस लेने के लिए अनुज्ञात करने हेतु पर्याप्त आधार हैं तो शिकायतकर्ता को इसे वापस लेने की अनुमति दे सकेगा ।
- ख. यदि आयोग की यह राय हो कि शिकायत वापस लेने को अनुज्ञात करना समुचित नहीं होगा तो आयोग शिकायतकर्ता के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से शिकायत की कार्यवाही ऐसी रीति में जारी रखने के आदेश कर सकेगा जो आयोग को समुचित प्रतीत हो ।
- ग. जहां आयोग की यह राय हो कि इस विनियम के अधीन कार्यवाही जारी रखना अनावश्यक है या प्रक्रिया का दुरुपयोग है, वहां वह किसी भी प्रक्रम पर, कार्यवाही को लिखित में अभिलिखित कारणों के लिए समाप्त कर सकेगा ।

अध्याय - 9

कार्य-निष्पादन मानक, संहिताएं, प्रदाय विनियम आदि73. संहिताएं बनाना

- क. आयोग, समय-समय पर, यथास्थिति, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में प्रचलित अनुज्ञप्तिधारियों और उत्पादन कंपनियों को निदेश दे सकेगा कि ऐसी संहिताएं बनाएं और अपनाएं जैसा आयोग राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में विद्युत सेक्टर के दक्ष संचालन और विद्युत प्रणाली के प्रचालन में समुचित समझें।
- ख. आयोग ऐसे परामर्श और कार्यवाहियां कर सकेगा जैसा इस प्रकार बनाई गई संहिता पर विचार-विमर्श उसे समुचित लगे।
- ग. इस प्रकार बनाई गई संहिता पर आयोग को सलाह देने के लिए आयोग परामर्शदाताओं या विशेषज्ञों की नियुक्ति कर सकेगा।
- घ. आयोग, इस प्रकार बनाई गई संहिताओं में ऐसे उपांतरण करने का निदेश दे सकेगा जिन्हें वह समुचित समझे।
- ङ. अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन कंपनियां आयोग द्वारा अनुमोदित संहिताओं को समय-समय पर आयोग द्वारा दिए गए निदेशों और आदेशों की संगति क्रियान्वित करेंगे।
- च. विद्युत प्रणाली के प्रचालन में कार्य-निष्पादन के मानकों के प्रवर्तन के संबंध में आयोग की शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बनाई जाने वाली और क्रियान्वित की जाने वाली संहिताओं में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-
- i. ग्रिड संहिता;
 - ii. वितरण संहिता;
 - iii. विद्युत प्रदाय संहिता और प्रदाय की शर्तें;
 - iv. बिलों के संदाय पर व्यवहार की संहिता सहित उपभोक्ता संबंधी संहिताएं; असंदाय के लिए कनक्शन काटने पर संहिता; सेवा मानक और गुणवत्ता तथा असफलता के लिए जुर्माना और शास्तियां, उपभोक्ता अधिकार, निपटारा और उपभोक्ता शिकायत विचारण संबंधी प्रक्रिया;
 - v. रक्षा और सुरक्षा संहिता;
 - vi. पारेषण प्रणाली योजना और सुरक्षा मानक;
 - vii. वितरण प्रणाली योजना और सुरक्षा मानक;
 - viii. प्रचालन मानक; और
 - ix. विद्युत के उपयोग और मांग पक्षीय प्रबंध पर संहिता।

- छ. जब तक इस विनियम के अनुसरण में संहिताएं, मानक और प्रदाय की शर्तें बनाई और क्रियांवित नहीं की जाती, अनुज्ञप्तिधारी और उत्पादन कंपनियां विद्यमान मानकों, संहिताओं और प्रदाय की शर्तों का अनुसरण करेंगी ।

ध्याय - 10

प्रकीर्ण

74. विनिश्चयों, निदेशों और आदेशों का पुनर्विलोकन

- क. किसी भी समय, आयोग, स्वःप्रेरणा से या संबंधित व्यक्तियों अथवा पक्षकारों के आवेदन पर, कोई विनिश्चय, निदेश या आदेश किए जाने के 45 दिनों के भीतर ऐसे विनिश्चय, निदेश या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और ऐसे समुचित आदेश पारित करेगा जैसा आयोग ठीक समझें :

परंतु यह कि स्वःप्रेरणा पर आयोग द्वारा प्रयोग की जाने वाली पुनर्विलोकन की शक्ति लिपिकीय या टंकण त्रुटियों के संशोधन तक सीमित होगी ।

- ख. ऐसे पुनर्विलोकन के लिए कोई आवेदन उसी रीति में फाइल किया जाएगा जिसमें इन विनियमों के भाग-2 के अधीन याचिका फाइल होती है ।

75. मृत्यु आदि के पश्चात् कार्यवाहियों का जारी रहना

- क. जहां किसी कार्यवाही में, कार्यवाही के किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है या वह दिवालिया के रूप में अधिनिर्णीत हो जाता है या समापन/परिसमापन के अधीन कंपनी के मामले में, कार्यवाहियां हितबद्ध उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, रिसीवर, समापक या संबंधित पक्षकार के अन्य विधिक प्रतिनिधि के साथ जारी रहेंगी ।
- ख. आयोग, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए कार्यवाही को समाप्त मान सकेगा और आयोग के इस प्रकार निदेश देने पर वह हितबद्ध उत्तराधिकारी को मामले के अभिलेख पर लेने की आवश्यकता से छूट दे सकेगा ।
- ग. ऐसे मामले में जहां कोई व्यक्ति हितबद्ध उत्तराधिकारी को अभिलेख पर लाने की आशा करें, इस प्रयोजन के लिए आवेदन ऐसी घटना के 90 दिनों के भीतर फाइल किया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप हितबद्ध उत्तराधिकारी को अभिलेख पर लाना अपेक्षित हो जाए ।

76. कार्यवाहियों का जनता के लिए खुला रहना

आयोग के समस्त कार्यवाहियां जनता के लिए खुली रहेंगी:

परंतु यह कि आयोग, यदि वह ऐसा उचित समझें और लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए किसी विशिष्ट मामले में कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर आदेश कर सकेगा कि आम जनता या किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की कार्यवाहियों तक पहुँच सीमित होगी।

77. याचिका का प्रकाशन

- क. जहां किसी आवेदनपत्र, याचिका या अन्य मामले का अधिनियम या विनियमों के अधीन अथवा आयोग के निदेशों के अनुसार प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है, वहां उसे सुनवाई के लिए नियत तारीख से कम से कम 7 दिन पूर्व, जब तक कि आयोग अन्यथा आदेश न दे या अधिनियम अथवा विनियम अन्यथा उपबंधित न करें, प्रकाशित किया जाएगा।
- ख. अन्यथा उपबंधित के सिवाए, ऐसे प्रकाशन में संक्षिप्त रूप से विषय-वस्तु वर्णित करने वाला शीर्षक दिया जाएगा।
- ग. प्रकाशित किए जाने वाला ऐसा प्रकाशन, इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित आयोग के अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

78. प्रक्रियाओं पर आदेशों और निदेशों का जारी होना

अधिनियम के उपबंधों और विनियमों के अधीन रहते हुए, आयोग समय-समय पर विनियमों को क्रियान्वित करने और विभिन्न मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में आदेश और व्यवहार निदेश जारी कर सकेगा जिनको विनिर्दिष्ट करने या निदेश देने के लिए विनियमों द्वारा आयोग को सशक्त बनाया गया है।

79. आयोग की अंतर्निहित शक्ति की व्यावृत्ति

- क. इन विनियमों की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह ऐसे आदेश करने की आयोग की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करती है जो न्याय दिलाने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हैं।
- ख. इन विनियमों की कोई बात आयोग को अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाने से बाधित नहीं करेगी जो विनियमों के किसी उपबंध के असंगत हैं, यदि आयोग, किसी मामले या मामलों के वर्ग को विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और लिखित में अभिलिखित दिए जाने वाले कारणों के लिए ऐसे मामले या मामलों के वर्ग के संबंध में कार्यवाही के लिए इसे आवश्यक या समीचीन समझता है।

ग. इन विनियमों की कोई बात प्रकटतः या विवक्षित रूप से किसी ऐसे मामले में कार्यवाही करने या अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग करने से बाधित नहीं करेगी, जिसके लिए विनियम नहीं बनाए गए हैं और आयोग ऐसे मामलों में ऐसी रीति में ऐसी शक्तियों और कृत्यों के साथ कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

80. कार्यवाहियों/अभिवचनों में किसी दोष, त्रुटि आदि का संशोधन करने की शक्ति

आयोग, किसी भी समय, ऐसे निबधनों और लागत पर या अन्यथा, जैसा वह उपयुक्त समझे, अपने समक्ष कार्यवाहियों में किसी दोष या त्रुटि का संशोधन कर सकेगा और सभी आवश्यक संशोधन, कार्यवाहियों में उत्पन्न वास्तविक प्रश्न या मुद्दा अवधारित करने के प्रयोजन के लिए किए जाएंगे ।

81. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

यदि इन विनियमों के किसी भी उपबंध को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई आती है तो आयोग, साधारण या विशेष आदेश द्वारा कोई ऐसी बात कर सकेगा जो अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हों और जो कठिनाइयां दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत हों ।

82. विहित समय का विस्तार या संक्षेपण

आदेश द्वारा कोई कार्य करने के लिए विहित समय का विस्तार (चाहे वह पहले ही समाप्त हो चुका हो या नहीं) या संक्षेपण पर्याप्त कारणों के लिए आयोग के आदेश के माध्यम से किया जा सकेगा ।

83. अननुपालन का प्रभाव

इन विनियमों की अपेक्षा को पूरा करने में असफलता से कोई कार्यवाही मात्र ऐसी असफलता के कारण से अविधिमान्य नहीं होगी जब तक कि आयोग का यह मत हो कि ऐसी असफलता का परिणाम न्याय हुआ है ।

84. लागत

क. ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, जो आयोग द्वारा निदेशित की जाएं, सभी कार्यवाहियों की लागत और आनुषंगिक लागत आयोग के विवेक पर प्रदान की जाएगी तथा आयोग को यह अवधारित करने की पूर्ण शक्ति होगी कि किसके द्वारा और किस निधि में से और किस सीमा तक ऐसी लागत का संदाय किया जाए और वह उपरोक्त प्रयोजनों के लिए सभी आवश्यक निदेश देगा।

ख. लागत का संदाय आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर या ऐसे समय के भीतर जैसा आयोग आदेश द्वारा निदेशित करें, किया जाएगा। लागत प्रदान करने वाला आयोग के आदेश का निष्पादन उसी रीति से किया जाएगा जैसे सिविल न्यायालय की डिक्री/आदेश का होता है।

85. आयोग द्वारा पारित आदेशों का प्रवर्तन

सचिव, अधिनियम के उपबंधों और विनियमों के अनुसार में संबंधित व्यक्ति द्वारा, आयोग द्वारा पारित आदेशों के प्रवर्तन और अनुपालन को सुनिश्चित करेगा और यदि आवश्यक हो तो निदेशों के लिए आयोग के आदेशों की ईप्सा कर सकेगा।

86. संशोधन की साधारण शक्ति

आयोग किसी भी समय, इन विनियमों के किसी भी उपबंध में परिवर्धन, परिवर्तन, फेरफार, उपांतरण या संशोधन कर सकेगा।

अनुसूची
(संदर्भ: कारबार संचालन विनियम, 2009 का विनियम 68)

फीस तथा प्रभार

क्रम सं.	विवरण	फीस (रुपयों में)
1.	अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अधीन पारेषण सुविधा की उपालब्धता के बारे में विवाद का न्यायनिर्णयन, उस व्यक्ति द्वारा संदत्त की जानी है जिसने ऐसा विवाद आयोग को निर्दिष्ट किया है।	इच्छित पारेषण क्षमता के पहले 1 मेगावाट के लिए 10,000 रुपए तथा तत्पश्चात्, 1250 रुपए प्रति मेगावाट, अधिकतम 1,00,000/- रुपए के अधीन रहते हुए।
2.	अधिनियम की धारा 15 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने पर आरंभिक अनुज्ञप्ति फीस	संबंधित सरकार द्वारा फीस के अवधारण संबंधित होने तक "लेखे में" संदाय के रूप में 50,000/- रुपए
3.	<p>वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस</p> <p>(i) पारेषण अनुज्ञप्ति</p> <p>(ii) वितरण अनुज्ञप्ति</p> <p>(iii) व्यापार अनुज्ञप्ति:</p> <p>परंतु यह कि सभी अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर अग्रिम में संदेय होगी, जिसमें अधिनियम की धारा 14 के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे तथा पांचवें परंतुक में निर्दिष्ट अनुज्ञप्तिधारी भी सम्मिलित हैं :</p> <p>परंतु यह और कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की दशा में, वार्षिक फीस की संगणना आगामी वित्तीय वर्ष के लिए पारेषण क्षमता संविदाओं की अनुमोदित/प्राक्कलित कम मात्रा के आधार पर की जाएगी:</p> <p>परंतु यह भी कि वितरण अनुज्ञप्ति की दशा में, वार्षिक फीस की संगणना आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विद्युत के विक्रय से अनुमोदित/प्राक्कलित राजस्व के आधार पर की जाएगी:</p> <p>परंतु यह भी कि व्यापार अनुज्ञप्ति की दशा में, वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस की संगणना आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विद्युत के विक्रय से</p>	<p>(i) वर्ष या उसके भाग के दौरान प्रवृत्त पारेषण क्षमता संविदा का 1000 रुपए प्रति मेगावाट, न्यूनतम 1000000/- रुपए और अधिकतम 2000000/- रुपए के अधीन रहते हुए,</p> <p>(ii) विद्युत के विक्रय से राजस्व का 0.05 प्रतिशत (करोँ तथा शुल्कों को छोड़कर)</p> <p>(iii) विद्युत के विक्रय से राजस्व का 0.05 प्रतिशत (करोँ तथा शुल्कों को छोड़कर)</p>

	<p>अनुमोदित/प्राक्कलित राजस्व के आधार पर की जाएगी, जिसमें स्वयं संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के भीतर अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत के विक्रय से प्राप्त राजस्वों को छोड़कर:</p> <p>परंतु यह भी कि जहां, यथास्थिति व संविदागत वास्तविक पारेषण क्षमता या विद्युत के विक्रय से प्राप्त वास्तविक राजस्व में इस विनियम के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त अनुमोदित/प्राक्कलित स्तर से अंतर होता है वहां यथास्थिति, संविदागत वास्तविक क्षमता या वास्तविक राजस्व के आधार पर संगणित अधिक फीस कम अनुज्ञप्ति फीस को अगले वर्ष के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के मद्दे समायोजित किया जाएगा।</p>	
4.	अधिनियम की धारा 17 के अधीन पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन	उस संव्यवहार, जिसके लिए अनुमोदन मांगा गया है, के मूल्य का 0.01 प्रतिशत, न्यूनतम 5,00,000/- और अधिकतम 20,00,000/- के अधीन रहते हुए।
5.	अधिनियम की धारा 18 के अधीन अनुज्ञप्ति के संशोधन के लिए आवेदन (i) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा (ii) अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा	(i) 10,00,000/- रुपए (ii) 1,00,000/- रुपए
6.	अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन (i) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा (ii) अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा	(i) 10,00,000/- रुपए (ii) 1,00,000/- रुपए
7.	मध्यवर्ती पारेषण प्रसुविधाओं के उपयोग के लिए अधिनियम की धारा 35 के अधीन आवेदन	50,000/- रुपए
8.	अधिनियम की धारा 35 के परंतुक के अधीन अधिशेष पारेषण के विस्तार के बारे में विवाद का न्यायनिर्णयन	5,00,000/- रुपए
9.	अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन दरों, प्रभारों, निबंधनों तथा शर्तों के अवधारण के लिए आवेदन	2,50,000/- रुपए
10.	अधिनियम की धारा 40 के साथ पठित धारा 2 की उपधारा (47) के अधीन और इसके अधीन विनिर्दिष्ट विनियम, जो उपरोक्त में सम्मिलित	

	<p>नहीं है, गैर-विभेदकारी निर्बाध पहुंच के उपबंध के बारे में विवादों का न्यायनिर्णयन</p> <p>(i) अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा निर्दिष्ट</p> <p>(ii) उस व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट जिसने कैप्टिव उत्पादन संयंत्र संनिर्मित, रखरखाव तथा प्रचालित किया है।</p> <p>(iii) उपभोक्ता/उपभोक्ता प्रतिनिधि द्वारा निर्दिष्ट</p>	<p>5,00,000/- रुपए</p> <p>25,000/-रुपए</p> <p>5,000/- रुपए</p>
11.	<p>अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2), (3) तथा (4) के साथ पठित धारा 2 की उपधारा (47) के तथा इसके अधीन विनिर्दिष्ट विनियमों के अधीन गैर-विभेदकारी निर्बाध पहुंच के उपबंध के बारे में विवादों का न्यायनिर्णयन</p> <p>(i) नीचे (ii) में निर्दिष्ट उत्पादन कंपनी से भिन्न अनुज्ञप्तिधारी या उत्पादन कंपनी द्वारा निर्दिष्ट</p> <p>(ii) वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से सीधे जुड़ी उत्पादन कंपनी या ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्दिष्ट जिसने कैप्टिव उत्पादन संयंत्र संनिर्मित, रखरखाव तथा प्रचालित किया है।</p> <p>(iii) उपभोक्ता/उपभोक्ता प्रतिनिधि द्वारा निर्दिष्ट</p>	<p>5,00,000/- रुपए</p> <p>25,000/-रुपए</p> <p>5,000/- रुपए</p>
12.	<p>धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंधों के अधीन आवेदक द्वारा संदत्त किए जाने वाले टैरिफ का अवधारण:</p> <p>(क) पारम्परिक ईंधन आधारित (कोयला, तेल आदि) संयंत्र</p> <p>(ख) गैर-पारम्परिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जिसमें को-उत्पादन भी है</p> <p>(ग) परियोजनाओं के वर्ग के लिए टैरिफ का जेनेरिक अवधारण</p>	<p>100 मेगावाट तक की क्षमता के लिए 10,00,000/-रुपए प्रत्येक अतिरिक्त मेगावाट या उसकी क्षमता के भाग के लिए 10,000/- रुपए</p> <p>मेगावाट की संस्थापित क्षमता का 1,00,000/- रुपए या 10 मेगावाट से ऊपर की क्षमता के लिए 5,00,000 रुपए।</p> <p>यथास्थिति, उपरोक्त (क) तथा (ख) पर संदेय फीस/प्रभारों का न्यूनतम।</p>
13.	धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (ख) के	15,00,000/- रुपए

	उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संदत्त किए जाने वाले विद्युत के पारेषण के लिए टैरिफ का वार्षिक/आधार वर्ष अवधारण: परंतु यह कि ऐसी फीस संदेय है चाहे अवधारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए आवेदन पर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या आयोग द्वारा स्व-प्रेरणा से अवधारण किया जाता है।	
14.	धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संदत्त किया जाने वाले विद्युत के चक्रण के लिए टैरिफ का वार्षिक/आधार वर्ष अवधारण: परंतु यह कि ऐसी फीस संदेय होती है चाहे अवधारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए आवेदन पर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या आयोग द्वारा स्व-प्रेरणा अवधारण से किया जाता है।	5,00,000/- रुपए
15.	धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संदत्त किए जाने वाले विद्युत के खुदरा विक्रय के लिए टैरिफ का वार्षिक/आधार वर्ष अवधारण: परंतु यह कि ऐसी फीस संदेय होती है चाहे अवधारण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए आवेदन पर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या आयोग द्वारा स्व-प्रेरणा अवधारण से किया जाता है।	15,00,000/- रुपए प्लस व्यस्ततम भाग के 500/- रुपए प्रति एमवीए, अधिकतम 20,00,000/- रुपए तक
16.	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संदत्त किए जाने वाले टैरिफों का वार्षिक पुनर्विलोकन तथा बहु-वर्षीय टैरिफ संरचना के अंतर्गत नियंत्रण अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी का कार्य-निष्पादन	5,00,000/- रुपए
17.	टैरिफ आदेश या ऊर्जा क्रय करार या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऊर्जा उपाप्ति दर के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन	टैरिफ की अवधारण के लिए मूल आवेदन के समय संदत्त फीस का 10 प्रतिशत
18.	टैरिफ आदेश या ऊर्जा क्रय करार या ऊर्जा उपाप्ति दर के पुनर्विलोकन के लिए उपभोक्ता या उपभोक्ता प्रतिनिधि द्वारा आवेदन	25,000/- रुपए
19.	टैरिफ आदेश या ऊर्जा क्रय करार या ऊर्जा उपाप्ति दर के पुनर्विलोकन के लिए अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता/उपभोक्ता प्रतिनिधि से भिन्न व्यक्ति द्वारा आवेदन	1,00,000/- रुपए
20.	अधिनियम की धारा 45 तथा 46 के अधीन	1,00,000/- रुपए

	वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रभारों की अनुसूची के अनुमोदन के लिए आवेदन	
21.	धारा 86 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी तथा उत्पादन कंपनियों और स्वयं अनुज्ञप्तिधारियों, जो इन विनियमों में कहीं भी सम्मिलित नहीं है, के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन	5,00,000/- रुपए
22.	अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन पारित आदेशों के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन	मूल आदेश के लिए संदत्त फीस का 10 प्रतिशत
23.	आयोग के आदेशों/अभिलेखों के निरीक्षण के लिए आवेदन	100/- रुपए प्रतिदिन या उसके भाग
24.	आयोग के दस्तावेजों/आदेश की प्रतियों का प्रदाय	3 रुपए प्रति पृष्ठ
25.	आयोग के आदेशों, जो इन विनियमों में कहीं भी सम्मिलित नहीं है, के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन	10,000/- रुपए
26.	प्रकीर्ण आवेदन, अर्थात् वह आवेदन जो इन विनियमों में कहीं भी सम्मिलित नहीं है: (क) अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आवेदन (ख) इकाईयों द्वारा आवेदन (ग) व्यक्तियों द्वारा आवेदन	10,000/- रुपए 1,000/- रुपए 500/- रुपए

जे. एस. सहरावत, सचिव

[विज्ञापन III/4/218 I/09-असा.]

उपाबंध-1

प्ररूप जेईआरसी - 1

(कारबार संचालन विनियम का विनियम 12 देखिए)

गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त
विद्युत विनियामक आयोग

फीस रजिस्टर

क्रम सं.	याचिका/ आवेदन सं०	डीडी/पे- आर्डर संदत्त करने वाले पक्षकार का नाम	डीडी/पे- आर्डर संदत्त करने का प्रयोजन	डीडी/पे- आर्डर की संख्या तथा तारीख	आई पी ओ/डी डी रकम की विशिष्टताएं	बैंक का नाम	लिपिक का नाम तथा हस्ताक्षर	उन पदाधिकारियों के नाम तथा हस्ताक्षर जिन्होंने पे-आर्डर पारित किया	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

उपाबंध - 2

प्ररूप जेईआरसी - 2
(कारबार संचालन विनियम का विनियम 13 देखिए)

कार्यवाहियों के लिए साधारण शीर्षक

गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त
विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष

फाइल करने की सं.
मामला सं.
(कार्यालय द्वारा भरा जाना है)

निम्नलिखित के मामले में
याचिकाकर्ताओं/आवेदकों के नाम

..... विवरण तथा पता

प्रत्यर्थियों का नाम

..... विवरण तथा पता

तथा

निम्नलिखित मामले में

(याचिका या आवेदन के प्रयोजन का आधार)

उपाबंध-3

प्ररूप जेईआरसी - 3

शपथ-पत्र

(कारबार संचालन विनियम का विनियम 14 देखिए)

गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त
विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष

फाइल सं.

मामला सं.

(कार्यालय द्वारा भरा जाना है)

निम्नलिखित के मामले में

(याचिकाकर्ताओं/आवेदक का नाम तथा पूरा पता तथा

प्रत्यर्थियों का नाम तथा पूरा पता)

शपथ-पत्र

मैं श्री/श्रीमती (पुत्र, पत्नी/पुत्री) श्री (आयु..... वर्ष),
(व्यवसाय) निवासी) सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ तथा
निम्नलिखित रूप से कथन करता हूँ :-

1. कि अभिसाक्षी प्रबंध निदेशक/निदेशक है, जिसे तारीख..... को कंपनी के संकल्प के अनुसार प्राधिकृत किया है (यदि याचिकाकर्ता एक कंपनी है) तथा नीचे वर्णित तथ्यों से परिचित है।
2. मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी यह सत्यापित करता हूँ कि शपथ-पत्र के पैरा सं. 1 तथा संलग्न याचिका के पैरा सं. की अंतर्वस्तु मेरी निजी ज्ञान से सही है तथा संलग्न याचिका के पैरा सं. अभिलेखों के आधार पर है तथा संलग्न याचिका के पैरा सं. विधिक सलाह पर आधारित है जो कि मेरे विश्वास के अनुसार सही है तथा सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ-पत्र का कोई भी भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कोई सारवान् वस्तु छिपाई नहीं गई है।

(अभिसाक्षी)

मैं, अधिवक्ता यह घोषणा करता हूँ कि इस शपथ-पत्र को करने वाला व्यक्ति अभिलेखों के माध्यम से मुझे जानता है और मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि वह अभिसाक्षी स्वयं अभिकथित किए जाने वाला व्यक्ति है।

(अधिवक्ता)

आज तारीख को बजे अभिसाक्षी द्वारा मेरे समक्ष प्रतिज्ञान किया गया जिसकी उपरोक्त अधिवक्ता द्वारा पहचान कर ली गई है। मैं अभिसाक्षी की जांच करके यह संतुष्ट हूँ कि उसने शपथ-पत्र की अंतर्वस्तु को समझ लिया है जिसे उसे पढ़ा दिया गया है तथा स्पष्ट कर दिया गया है। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के बारे में भी यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो आयोग की किंहीं भी कार्यवाहियों में जान-बूझकर मिथ्या साक्ष्य देता है या किंहीं भी कार्यवाहियों में उपयुक्त किए जा रहे प्रयोजन के लिए साक्ष्य गढ़ता है।

उपाबंध-4

प्रारूप जेईआरसी - 4

(कारबार संचालन विनियम का विनियम 15 देखिए)

गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष

निम्नलिखित मामले में

याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता

बनाम

..... प्रत्यर्थी

उपसंज्ञाति ज्ञापन

मैं, के रूप में व्यवसायरत/कार्यरत, की ओर से उपस्थित होने के लिए (द्वारा) प्राधिकृत (प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति के विशिष्टियों को प्रस्तुत करें) किया जा रहा हूँ तथा पूर्वोक्त मामले में उनके/उसके लिए अभिवचन तथा कार्य करने का वचनबंध करता हूँ।

स्थान

तारीख

हस्ताक्षर तथा

पदनाम

पत्राचार के लिए पता

उपाबंध-5

प्ररूप जेईआरसी - 5
(कारबार संचालन विनियम का विनियम 15 देखिए)

गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त
विद्युत विनियामक आयोग

याचिका/आवेदन रजिस्टर

क्रम सं.	आयसी सं.	फाइल करने की तारीख	याचिका/आवेदन सं.	याचिकाकर्ता (ओं) का नाम तथा पता	प्रत्यर्था (यों) का नाम तथा पता	याचिका/आवेदन की विषय-वस्तु	स्वीकार करने का आवेदन	पास्ति अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, की विशिष्टियां	अंतिम आदेश की तारीख तथा विशिष्टियां	अपील के ब्यारे, यदि फाइल की गई हो	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

उपाबंध-6

प्ररूप जेईआरसी - 6
(कारबार संचालन विनियम का विनियम 15 देखिए)

गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त
विद्युत विनियामक आयोग

संख्या

विषय मामले में विद्युत अधिनियम की धारा के अधीन याचिका

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर तारीख को फाइल किए गए तारीख को आपकी याचिका/आवेदन के संदर्भ में आपको सूचित करने का निदेश हुआ है कि संवीक्षा करने पर, निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैं :

1. याचिका, जेईआरसी, कारबार संचालन विनियम के अध्याय 2 में विनिर्दिष्ट प्ररूप (जेईआरसी-2) में नहीं है।
2. पक्षकारों के नाम, विवरण तथा पता वाद शीर्षक (टाइटिल) में नहीं दिया गया है।

3. निम्नलिखित आवश्यक पक्षकार अभियोजित नहीं किए गए हैं
क.
ख.
ग.
4. याचिका सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित नहीं है।
5. याचिका शपथ-पत्र द्वारा समर्थित नहीं है।
6. शपथ-पत्र जेईआरसी व्यापक कारबार संचालन विनियम के अध्याय-2 में विहित प्ररूप में नहीं है।
7. शपथ-पत्र हस्ताक्षरित तथा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सशपथ नहीं है।
8. याचिका की छह प्रतियां फाइल नहीं की गई हैं।
9. याचिकाओं की प्रतियां सभी प्रकार से पूरी नहीं हैं।
10. दस्तावेजों की प्रतियां पढ़े जाने योग्य तथा सम्यक् रूप से प्रमाणित नहीं हैं।
11. अंग्रेजी/हिंदी/आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य भाषा से भिन्न, भारत में अंतर्विष्ट दस्तावेजों तथा अन्य सामग्री का अंग्रेजी/हिंदी/आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य भाषा में अनुवाद नहीं है।
12. अंग्रेजी/हिंदी/आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य भाषा में दस्तावेजों का प्रमाणिक अनुवाद प्रस्तुत नहीं किया गया है।
13. वकालतनामा/प्राधिकार-पत्र फाइल नहीं किया गया है।
14. वकालतनामा पर्याप्त रूप से निष्पादित नहीं किया गया है तथा आवश्यक न्यायालय फीस संदत्त नहीं की गई है।
15. याचिका/आवेदन के लिए विहित फीस संदत्त नहीं की गई है।
16. दस्तावेजों की अनुक्रमणिका फाइल नहीं की गई है।
17. दस्तावेजों पर पृष्ठ संख्या उचित रूप से नहीं डाली गई है।

आपसे, इस पत्र के जारी होने के तीन सप्ताह के भीतर त्रुटियों को दूर करने का अनुरोध किया जाता है, ऐसा करने में असंदत्त रहने पर, याचिका रद्द समझी जाएगी।

भवदीय,

(न्यायपीठ अधिकारी)

उपाबंध-7

प्ररूप जेईआरसी - 7
(कारबार संचालन विनियम का विनियम 24 देखिए)

गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त
विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष

निम्नलिखित मामले में

याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता (ओं)

बनाम

..... प्रत्यर्थी (यों)

दस्तावेजों/अभिलेखों के निरीक्षण के लिए आवेदन

1. अनुज्ञा चाहने वाले व्यक्ति का नाम तथा पता
2. क्या वह मामले का पक्षकार है या वह किसी पक्षकार का प्राधिकृत प्रतिनिधि है (आवश्यक विशिष्टियां दें)
3. निरीक्षण किए जाने वाले कागज-पत्रों/दस्तावेजों के ब्यौरे
4. निरीक्षण करने का प्रयोजन
5. किए जाने वाले निरीक्षण की तारीख तथा अवधि
6. संदेय फीस तथा संदाय की पद्धति

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

कार्यालय उपयोग के लिए

..... को निरीक्षण मंजूर/रद्द किया गया ।

सचिव

उपाबंध-8

प्ररूप जेईआरसी - 8
(कारबार संचालन विनियम का विनियम 24 देखिए)

गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त
विद्युत विनियामक आयोग

अभिलेखों के निरीक्षण के लिए रजिस्टर

क्रम सं.	आवेदक का नाम	आवेदन की तारीख	निरीक्षण किए जाने वाले अभिलेख	निरीक्षण का प्रयोजन	बीडी/पे-आर्बर सं. तारीख बैंक की विशिष्टियों के साथ संवत् रकम	निरीक्षण करने की तारीख	उस पक्षवादी जिसकी उपस्थिति में अभिलेख का निरीक्षण किया गया	अभिलेख/ निरीक्षण करने वाले सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

उपाबंध-9

प्ररूप जेईआरसी - 9
(कारबार संचालन विनियम का विनियम 25 देखिए)

गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त
विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष

निम्नलिखित मामले में

याचिका संख्या

..... याचिकाकर्ता (ओं)

बनाम

..... प्रत्यर्थी (यों)

प्रमाणित प्रति देने के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम तथा पता
2. क्या आवेदक मामले का पक्षकार है

3. क्या मामला लंबित है या निपटा दिया गया है
4. जिस दस्तावेज की प्रति के लिए आवेदन किया गया है, तारीख सहित विवरण
5. अपेक्षित प्रतियों की संख्या
6. प्रेषित फीस की रकम तथा संदाय की पद्धति

कार्यालय उपयोग के लिए

हस्ताक्षर

मंजूर की गई/रद्द की गई
संदेय/संदत्त अतिरिक्त प्रतियों की फीस
तथा उसके ब्यौरे

सचिव

उपाबंध-10

प्ररूप जेईआरसी - 10
(कारबार संचालन विनियम का विनियम 25 देखिए)

गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त
विद्युत विनियामक आयोग

आवेदित प्रति का रजिस्टर

क्रम सं.	आवेदन की तारीख	आवेदक का नाम	याचिका सं.	उस दस्तावेज की विशिष्टियां जिसकी प्रति अपेक्षित है	प्राप्त रकम	डी डी/पे-आर्डर की सं. तारीख तथा बैंक की विशिष्टियां	पृष्ठों की संख्या	अतिरिक्त रकम तथा डी.डी./पे-आर्डर की विशिष्टियां	तैयार करने की तारीख	परिधान की तारीख	प्राप्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

सचिव

**JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION FOR
THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES**

NOTIFICATION

Gurgaon, the 30th July, 2009

No. JERC-01/2009.—In exercise of the powers conferred on it by Section 181 of The Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, and after previous publication, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories hereby makes the following Regulations, namely :—

Chapter I

General

1. Short title, commencement, and extent

- (i) These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2009.
- (ii) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- (iii) These Regulations extend to the whole of the State of Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry.

2. Definitions

- (i) In these Regulations, unless the context otherwise requires:
 - (a) 'Act' means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
 - (b) 'Chairperson' means the Chairperson of the Commission;
 - (c) 'Commission' means the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa &

Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry;

- (d) 'Meeting' means hearings, meetings, discussions, deliberations, inquiries, investigations, consultations as held by the Commission from time to time in the discharge of its functions under the Act.
 - (e) 'Officer' means an officer of the Commission;
 - (f) 'Petition' means and includes all petitions, applications, complaints, appeals replies, rejoinders, supplemental pleadings, other papers and documents;
 - (g) 'Receiving Officer' means the officer designated by the Commission for receiving the petition;
 - (h) 'Proceedings' means and includes proceedings of all nature that the Commission may hold in the discharge of its function under the Act;
 - (i) 'Regulations' means these Regulations;
 - (j) 'Secretary' means the Secretary of the Commission; and
 - (k) 'UT' means Union Territory.
- (ii) Words and expressions occurring in these Regulations and not defined herein but defined in the Act shall bear the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

3. Commission's office, office hours and sittings

- (i) The headquarter of the Commission shall be located at other place as may be decided by the Central Government from time to time, the headquarter presently being located at Gurgaon, Haryana.
- (ii) Unless otherwise directed, the headquarter and other offices of the Commission shall be open daily except on Saturdays, Sundays and holidays notified by the Commission.
- (iii) The headquarters and other offices of the Commission shall be open at such hours as the Commission may direct from time to time. At present the working hours of the Commission shall be from 09.30 AM to 06.00 PM, with a lunch-break from 01.30 PM to 02.00 PM.
- (iv) Where the last day for doing of any act falls on a day on which the office of the Commission is closed and by reasons thereof the act cannot be done on that day, it may be done on the next day on which the office is open.
- (v) The Commission may hold sittings for hearing matters at its headquarter or at any other place on days and time to as directed by the Chairperson.

4. Language of the Commission

- (i) Unless otherwise permitted by an order of the Commission, the proceedings of the Commission shall be conducted in English/Hindi or any other language notified by Government of India for respective UTs and by Government of Goa for the State of Goa for conduct of their official business.
- (ii) No Petition, document or other material contained in any language other than those specified in sub-regulation (i) above may be accepted by the Commission, unless the same is accompanied by a translation thereof in one of such languages.
- (iii) Any translation which is agreed to by the parties to the proceedings, or which any of the parties may furnish with an authenticity certificate of the person who had translated the same in a language recognized by the Commission, may be accepted by the Commission as a true translation.
- (iv) The Commission may in appropriate cases direct translation of the petitions, pleadings, documents and other material into English by an officer or person designated by the Commission for the purpose.

5. Seal of the Commission

- (i) There shall be a separate seal indicating that it is the seal of the Commission.
- (ii) The design of the seal shall be as given below:



- (iii) Every order or communication made, notice issued or certified copy granted by the Commission shall be stamped with the seal of the Commission and shall be certified by Secretary or any other officer designated for the purpose.

6. Officers of the Commission

- (i) Appointments
 - (a) The Commission shall have the power to appoint Secretary, officers and other employees

for discharging various duties. It may also prescribe the qualifications, experience and other terms and conditions for the appointment of such officers and other employees in conformity with the procedure laid down in the Act.

- (b) The Commission may appoint Consultants to assist the Commission in the discharge of its functions.

(ii) **The Secretary**

- (a) The Secretary shall exercise his powers and perform his duties under the control of the Chairperson.

- (b) The Commission in discharge of its functions under the Act, may take such assistance from the Secretary as it may deem fit.

(iii) In particular and without prejudice to the generality of the above provisions, the Secretary shall have the following powers and perform the following duties, viz.:

- (a) He shall have custody of the records and the seal of the Commission;
- (b) He shall receive or cause to receive all petitions, applications or references pertaining to the Commission;
- (c) He shall prepare or cause to prepare briefs and summaries of all pleadings presented by various parties in each case before the Commission in the discharge of its functions in this regard;
- (d) He shall assist the Commission in the proceedings relating to the powers exercisable by the Commission;
- (e) He shall authenticate the orders passed by the Commission;
- (f) He shall ensure compliance of the orders passed by the Commission; and
- (g) He shall have the right to collect from the Central Government or State Government/Administration of Goa/UTs or other offices, companies and firms or any other party as may be directed by the Commission, such information as may be considered useful for the purpose of efficient discharge of the functions of the Commission under the Act and place the information before the Commission.

7. Delegation of Powers

- (i) The Commission may delegate to its officers such functions including functions that may be required by these regulations to be exercised by the Secretary on terms and conditions the Commission may specify for the purpose.
- (ii) In the absence of the Secretary, such other Officer of the Commission, as may be designated by the Commission, may exercise all the functions of the Secretary.

- (iii) The Commission shall, at all times have the authority, either on an application made by any interested or affected party or *suo motu*, to review, revoke, revise, modify, amend, alter or otherwise change any order made or action taken by the Secretary or the Officers of the Commission, if the Commission considers the same to be appropriate.

8. Participation of Consumer Associations and others

- (i) It shall be open to the Commission to permit any association/forum or other bodies corporate or any group of consumers to participate in any proceedings before the Commission on such terms and conditions, in regard to the nature and extent of participation that the Commission may consider appropriate.
- (ii) It shall be open to the Commission for the sake of timely completion of proceedings, to direct grouping of associations/groups/forums referred to above for submission of respective Petitions/Affidavits collectively.
- (iii) The Commission may as and when considered appropriate notify a procedure for recognition of associations, groups, forums or bodies corporate as registered consumer association for purposes of representation before the Commission.
- (iv) The Commission may appoint any officer or any other person to represent consumers' interests, if considered necessary.
- (v) The Commission may direct payment to the officer or person appointed to represent the consumers' interest such fees, costs and expense by such of the parties in the proceedings as the Commission may consider appropriate.

Chapter II

General Rules Concerning the Proceedings before the Commission

9. Proceedings etc. before the Commission

- (i) The Commission may from time to time hold meetings, as it may consider appropriate in the discharge of its functions under the Act.
- (ii) The quorum for conduct of meetings as mentioned in sub regulation (i) above, for transaction of business of the Commission shall be two:

Provided that when the Chairperson or the Member has been prevented from attending the hearing, meeting etc. of which he has been given due notice, for

sufficient reason, the Member or the Chairperson, as the case may be, attending the meeting shall validly constitute the quorum:

Provided further that for a meeting of the Commission to review any previous decision, the quorum shall be that all members shall be present.

10. Authority to represent

A person may authorize an advocate or a member of any statutory professional body holding a Certificate of Practice, as the Commission may from time to time specify, to represent him and to act and plead on his behalf before the Commission. The person may also appear himself or may authorize any of his employees to appear before the Commission and to act and plead on his behalf. The Commission may from time to time specify the terms and conditions subject to which a person may authorize any other person to represent him and act and plead on his behalf.

11. Initiation of Proceedings

- (i) The Commission may initiate any Proceedings *suo motu* or on a Petition filed by any affected or interested person.
- (ii) The notice of the initiation of the proceedings may be issued by the Commission, and the Commission may give such orders and directions as may be deemed necessary, for service of notices to the affected parties, the filing of replies and rejoinders in opposition or in support of the Petition in such form as it may direct. The Commission may, if it considers appropriate, issue orders for publication of the petition inviting comments on the issues involved in the proceedings in such form as the Commission may direct.
- (iii) While issuing the notice of inquiry, the Commission may, in appropriate cases, designate an Officer of the Commission or any other person whom the Commission considers appropriate to present the matter in the capacity of a petitioner in the case.

Regulation 12 - Petitions and Pleadings before the Commission and Fees payable

- (i) All Petitions to be filed before the Commission shall be typewritten, cyclostyled or printed neatly and legibly on one side of white paper and every page shall be consecutively numbered. The Commission will accept petitions filed with a Computer Disk or through electronic media on such terms and conditions as the Commission may specify. The contents of the Petition should be divided appropriately into separate paragraphs, which shall be numbered serially. The Petition shall be accompanied by such documents, supporting data and statements as the Commission may specify. All such documents, supporting data and statements accompanying the Petition shall be attested by the person who files the affidavit.

- (ii) Every petition/application filed before the Commission shall be accompanied by fee in accordance with the provisions of Chapter VIII.
- (iii) The fees shall be payable by way of demand draft/pay order issued in favour of Secretary, Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories.
- (iv) The fee received shall be entered in the register prescribed for the purpose in Form JERC-1 (Annexure I).

13. General Headings

The general headings in all Petitions before the Commission and in all publications and notices shall be in Form JERC-2 (Annexure II).

14. Affidavit in support

- (i) Each petition shall be signed, verified and supported by affidavit and every such affidavit shall be in Form JERC-3 (Annexure III).
- (ii) Every affidavit shall be drawn up in the first person and shall state the full name, age, occupation and address of the deponent and the capacity in which he is signing and shall be signed and sworn before a person lawfully authorized to take and receive affidavits.
- (iii) Every affidavit shall clearly and separately indicate the statements, which are true to the:
 - (a) Knowledge of the Deponent;
 - (b) Information received by the Deponent; and
 - (c) Belief of the Deponent.
- (iv) Where any statement in the affidavit is stated to be true to the information received by the deponent, the affidavit shall also disclose the source of the information and a statement that the deponent believes that information to be true.

15. Presentation and Scrutiny of the Petitions

- (i) All Petitions shall be filed with six copies and each set of the Petition shall be complete in all respects. The fees as may be prescribed by the Commission shall be payable along with the petition.
- (ii) All Petitions shall be presented in person or by any duly authorized agent or representative at the headquarters of the Commission or such other filing centre or centres as may be notified by the Commission from time to time and during the time

notified. The Petitions may also be sent, by registered post acknowledgment due, to the Commission at the places mentioned above. The vakalatnama in favour of the advocate and, in the event the Petition is presented by an authorized representative, the document authorizing the representative shall be filed along with the Petition, if not already filed on the record of the case. Any person other than a legal practitioner representing a party before the Commission shall file a Memorandum of Appearance, in Form JERC-4 (Annexure IV), duly signed by him.

- (iii) Upon the receipt of the Petition, the Receiving Officer designated by the Commission for the purpose of receiving the petition, shall acknowledge the receipt by stamping and endorsing the date on which the Petition has been presented and shall issue a duly stamped and dated acknowledgment to the person filing the Petition. In case the Petition is received by registered post, the date on which the Petition is actually received at the office of the Commission shall be taken as the date of the presentation of the Petition.
- (iv) The presentation and receipt of the Petition shall be duly entered in the register maintained for the purpose by the office of the Commission. The said register shall be as per the format given in Form JERC-5 (Annexure V).
- (v) The Receiving Officer may decline to accept any Petition which does not conform to the provisions of the Act or the Regulations or directions given by the Commission or is otherwise defective or which is presented otherwise than in accordance with the Regulations or directions of the Commission:
Provided, however, that no petition shall be refused for defects in the pleadings or in the presentation, without giving an opportunity to the person filing the petition to rectify the defects within the time which may be given for the purpose. The Receiving Officer shall advise in writing the person filing the petition, of the defects in the petition filed, in format as per Form JERC-6 (Annexure VI).
- (vi) A person aggrieved by any order of the Receiving Officer in regard to the presentation of the Petition may request the matter to be placed before the Secretary of the Commission for appropriate orders.
- (vii) The Chairperson shall be entitled to call for the Petition presented by any party and give such directions regarding the presentation and acceptance of the Petition as he considers appropriate.
- (viii) If on scrutiny, the Petition is not refused or any order of refusal is rectified by the Secretary or by the Chairperson of the Commission, the Petition shall be duly

registered and assigned a number in the manner to be specified by the Commission.

- (ix) As soon as the Petition and all necessary documents are lodged and the defects and objections, if any, are removed, and the Petition has been scrutinized and numbered, the Petition shall be put up before the Commission for preliminary hearing and admission.
- (x) The Commission may admit the Petition for hearing without requiring the attendance of the party. The Commission shall not pass an order refusing admission without giving the party concerned an opportunity of being heard. The Commission may, if it considers appropriate, issue notice to such person or persons, as it may deem fit, to hear the petition for admission.
- (xi) If the Commission admits the Petition, it may give such orders and directions, as may be deemed necessary, for service of notices to the respondent(s) and other affected or interested parties for the filing of replies and rejoinders in opposition or in support of the Petition in such form as the Commission may direct and for the petition to be placed for hearing before the Commission.

16. Service of notices and processes issued by the Commission

- (i) Any notice, process or summons to be issued by the Commission may be served by any one or more of the following modes as may be directed by the Commission:
 - (a) Service by any of the parties to the proceedings as may be directed by the Commission;
 - (b) By hand delivery through a messenger;
 - (c) By registered post with acknowledgement due;
 - (d) By publication in newspaper in cases where the Commission is satisfied that it is not reasonably practicable to serve the notices, processes, etc. on any person in the manner mentioned above.
 - (e) In any other manner as considered appropriate by the Commission.
- (ii) The Commission shall be entitled to decide in each case the persons who shall bear the cost of such service/publication.
- (iii) Every notice or process required to be served on or delivered to any person may be sent to the person or his agent empowered to accept service at the address furnished by him for service or at the place where the person or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain. The notice shall be accompanied by

- a copy of the petition along with the copies of the documents filed with the petition.
- (iv) In the event any matter is pending before the Commission and the person to be served has authorized an agent or representative to appear for or represent him or her in the matter, such agent or representative shall be deemed to be duly empowered to take service of the notices and processes on behalf of the party concerned in all matters and the service on such agent or representative shall be taken as due service on the person to be served.
 - (v) Where a notice is served by the party to the proceedings either in person or through registered post, an affidavit of services shall be filed by such party with the Commission giving details of the date and manner of service of notices and processes.
 - (vi) Where any petition is required to be published, it shall be published in the newspapers in such form to be specified, for such duration and within such times as the Commission may direct.
 - (vii) In default of compliance with the requirements of the Regulations or directions of the Commission as regards the service of notices, summons or processes or the publication thereof, the Commission may either dismiss the Petition or give such other or further directions as it thinks fit.
 - (viii) No service or publication required to be done shall be deemed invalid by reason of any defect in the name or description of a person provided that the Commission is satisfied that such service is in other respects sufficient, and no proceeding shall be invalidated by reason of any defect or irregularity unless the Commission, on an objection taken, is of the opinion that substantial injustice has been caused by such defect or irregularity or there are otherwise sufficient reasons for doing so.

17. Filing of Reply, Opposition, Objections, etc.

- (i) Each person to whom the notice of inquiry or the Petition is issued (hereinafter called the 'respondent') who intends to oppose or support the Petition shall file the reply and the documents relied upon (with six (6) copies) within such period as may be fixed by the Commission. In the reply filed, the respondent shall specifically admit, deny or explain the facts stated in the notice of inquiry or the Petition and may also state such additional facts as he considers necessary for just decision of the case. The reply shall be signed and verified and supported by affidavit in the same manner as in the case of the Petition.
- (ii) The respondent shall serve a copy of the reply along with the documents duly attested

to be true copies on the petitioner or his authorized representative and file proof of such service with the office of the Commission.

(iii) Where the respondent states that additional facts may be necessary for the just decision of the case, the Commission may allow the petitioner to file a rejoinder to the reply filed by the respondents. The procedure mentioned above for filing of the reply shall apply mutatis mutandis to the filing of the rejoinder.

(iv) Filing of objections or comments

(a) Every person (other than the persons to whom notices, processes, etc. have been issued calling for reply) who intends to file objections or comments in regard to a matter pending before the Commission, pursuant to the publication made for the purpose shall deliver to an Officer designated by the Commission for the purpose, the statement of the objections or comments with six (6) copies of the documents and evidences in support thereof within the time fixed for the purpose.

(b) The Commission may permit such person or persons including associations, forums and bodies corporate as it may consider appropriate to participate in the proceedings before the Commission if, on the report received from the Officer, the Commission considers that the participation of such person or persons will facilitate the proceedings and the decision in the matter.

(c) Unless permitted by the Commission, the person filing objections or comments shall not necessarily be entitled to participate in the proceedings to make oral submissions. However, the Commission shall be entitled to take into account the objections and comments filed after giving such opportunity to the parties to the proceedings as the Commission considers appropriate to deal with the objections or comments.

18. Hearing of the matter

(i) The Commission may determine the stages, manner, the place, the date and the time of the hearing of a matter, as it may consider appropriate and proceed further in any one or more of the following manners:

(a) The Commission may decide the matter on the pleadings of the parties or may call for the parties to produce evidence by way of affidavit or lead oral evidence in the matter.

(b) If the Commission directs evidence of a party to be led by way of oral

submissions, the Commission may, if considered necessary or expedient, grant an opportunity to the other party to cross-examine the persons giving evidence.

- (c) The Commission may, if considered necessary or expedient, direct that the evidence of any of the parties be recorded by an Officer or person designated for the purpose by the Commission.
- (d) The Commission may direct the parties to file written note(s) of arguments or submissions in the matter.

19. Procedure to be followed where any party does not appear

- (i) Where, on the date fixed for hearing or any other date to which such hearing may be adjourned, any of the parties or its authorized agent or representative does not appear when the matter is called for hearing, the Commission may, in its discretion, either dismiss the Petition for default when the petitioner or the person who moves the Commission for hearing is in default or process *ex-parte*.
- (ii) Where a Petition is dismissed in default or decided *ex-parte*, the person aggrieved may file an application within 30 days from the date of such dismissal or being proceeded *ex-parte*, as the case may be, for recall of the order passed, and the Commission may recall the order on such terms as it thinks fit, if the Commission is satisfied that there was sufficient cause for the non-appearance when the Petition was called for hearing.

20. Powers of the Commission to call for further information, evidence, etc.

- (i) The Commission may, at any time before passing orders on any matter, require the parties or any one or more of them or any other person whom the Commission considers appropriate, to produce such documentary or other evidence as the Commission may consider necessary for the purpose of enabling it to pass orders.
- (ii) The Commission may direct the summoning of the witnesses, discovery and production of any document or other material objects producible in evidence, requisition of any public record from any office, examination by an Officer of the Commission, the books, accounts or other documents or information in the custody or control of any person which the Commission considers relevant to the matter.

21. Reference of issues to others

- (i) At any stage of the Proceedings, the Commission shall be entitled to refer such issue or issues in the matter as it considers appropriate to persons including, but not limited

to, the Officers and consultants of the Commission whom the Commission considers as qualified to give expert advice or opinion.

- (ii) The Commission may nominate from time to time any person including, but not limited to, the Officers and consultants to visit any place or places for inspection and report on the existence or status of the place or any facilities therein.
- (iii) The Commission, if it thinks fit, may direct the parties concerned and/or any other person considered by it as qualified to provide expert or informed advice or opinion to appear before the persons designated in sub-section (i) or (ii) above to present their respective views on the issues or matters referred to.
- (iv) The report or the opinion received from such person shall form a part of the record of the case and the parties shall be given the copies of the report or opinion given by the person(s) designated by the Commission. The parties shall be entitled to file their version either in support or in opposition to the report or the opinion.
- (v) The Commission shall duly take into account the report or the opinion given by the person, the reply filed by the parties while deciding the matter and if considered necessary, may examine the person giving the report or the opinion.

22. Orders of the Commission

- I. The Commission shall pass orders on the Petition and the Members of the Commission who hear the matter and vote on the decision shall sign the orders.
- II. The reasons given by the Commission in support of the orders shall form a part of the order and shall be available for inspection and supply of copies in accordance with the Regulations.
- III. All orders and decisions issued or communicated by the Commission shall be certified by the signature of the Secretary or any other officer of the Commission duly authorized by the Chairperson in this behalf and bear the official seal of the Commission.
- IV. All final orders of the Commission shall be communicated to the parties to the Proceedings under the signature of the Secretary or an Officer empowered in this behalf by the Chairperson
- V. Without prejudice to any other remedies an aggrieved person may have, an appeal against an order of the Commission shall lie with the Appellate Tribunal for Electricity established under Section 110 of the Act.

23. Interim Orders

The Commission may pass such interim orders, as it may consider appropriate at any stage of the proceedings.

24. Inspection of records of Proceedings

- (i) Records of every Proceeding, except those parts which for reasons recorded by the Commission are confidential or privileged or otherwise not to be disclosed to any person, shall be open to inspection either during the proceeding or after the orders have been passed, subject to such person complying with such terms as the Commission may direct from time to time including in regard to time, place, and manner of inspection and payment of fees.
- (ii) An application for inspection of documents shall be in the Form JERC-7(Annexure-VII) and shall be accompanied by a fee of Rs. 100/- for each inspection for one day in the form of Demand Draft/Pay Order in favour of the Secretary, Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories.
- (iii) The inspection of record shall be allowed on any working day ordinarily during 1430 hours to 1630 hours in the presence of an officer authorized for that purpose.
- (iv) The person inspecting the records shall not in any manner cause dislocation, mutilation, tampering or damage to records in the course of inspection.
- (v) The officer supervising the inspection may at any time prohibit further inspection if in his opinion any of the records are likely to be damaged in the process of inspection and shall immediately make a report about the matter to the Secretary and seek orders on the matter.
- (vi) A register for inspection of records in the format as per Form JERC-8(Annexure VIII) shall be maintained.

25. Supply of Certified Copies of Documents

- (i) Any person shall be entitled to obtain certified copies of the orders, decisions, direction and reasons in support thereof given by the Commission as well as the pleading ,papers and other parts of the records of the Commission to which he is entitled, on payment of fees and complying with such other terms which the Commission may direct.
- (ii) Every order granting, refusing or modifying interim relief and final order shall be communicated to the parties to the petition free of cost:
Provided that unless ordered otherwise by the commission, a copy of the final order may not be sent to any party who has not entered appearance.
- (iii) Any person desirous of obtaining a certified copy of any order of the Commission or

any document forming part of the record of proceeding before the Commission may submit an application in the prescribed Form JERC-9 (Annexure-IX).

(iv) The application for certified copy shall be accompanied by the fee prescribed in the Schedule to these Regulations in the form of Demand Draft / Pay Order in favour of the Secretary, Joint Electricity Regulatory Commission for the state of Goa and Union Territories.

(v) A Register of Copy Applications shall be maintained in the form as prescribed in Form JERC-10 (Annexure -X).

(vi) As far as practicable, the certified copies shall be prepared in the order in which the applications are entered in the Register of Copy Applications.

(vii) The certified copies shall be prepared by photocopying process or by typing and when a copy is so made, it shall be compared by the person preparing the copy to satisfy himself that the copy prepared faithfully and legibly reproduces the document desired.

(viii) An endorsement as under shall be affixed on the reverse of the last page of the document.

(a) Sl. No. of the application.

(b) Name of the applicant.

(c) Date of presentation of the application.

(d) No. of pages.

(e) Copying fee charged,

(f) Date on which copy is ready.

(g) Date of delivery.

(ix) The endorsement shall be made with the help of rubber stamp got prepared for the purpose. The entries shall be made in ink.

(x) The copying fee payable for obtaining a certified copy shall be Rs. 3/- per page irrespective of the number of words / lines in each page.

26. Proceedings before the Commission to be deemed as Judicial Proceedings

(i) According to Section 95 of the Electricity Act, 2003, all proceedings before the Commission shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860) and the Commission shall be deemed to be a Civil Court for the purposes of sections 345 and 346 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

(ii) The relevant provisions of the Indian Penal Code and Criminal Procedure Code are as under:

(a) Section 193 of Indian Penal Code, 1860.

Punishment for false evidence:-

Whoever intentionally gives false evidence in any stage of a judicial proceeding, or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of judicial proceeding, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine;

and whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any other case, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.

Explanation 1. A trial before a Court-martial a [* * *] is a judicial proceeding.

Explanation 2. An investigation directed by law preliminary to a proceeding before a Court of Justice, is a stage of a judicial proceeding, though that investigation may not take place before a Court of Justice.

(b) Section 228 of Indian Penal Code, 1860.

Intentional insult or interruption to public servant sitting in judicial proceeding:-

Whoever intentionally offers any insult, or causes any interruption to any public servant, while such public servant is sitting in any stage of a judicial proceeding, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(c) Section 345 of Code of Criminal Procedure, 1973.

Procedure in certain cases of contempt:-

- (1) When any such offence as is described in Section 175, Section 178, Section 179, Section 180 or Section 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860) is committed in the view or presence of any Civil, Criminal or Revenue Court, the Court may cause the offender to be detained in custody and may, at any time before the rising of the Court on the same day, take cognizance of the offence and, after giving the offender a reasonable opportunity of showing cause why he should not be punished under this section, sentence the offender to fine not exceeding two hundred rupees, and, in default of payment of fine, to simple imprisonment for a term which may extend to one month, unless such fine be sooner paid.
- (2) In every such case the Commission shall record the facts constituting the offence, with the statement (if any) made by the offender, as well as the finding and sentence.
- (3) If the offence is under Section 228 of the Indian Penal Code (45 of 1860), the

record shall show the nature and stage of the judicial proceeding in which the Court interrupted or insulted was sitting, and the nature of the interruption or insult.

(d) Section 346 of Code of Criminal Procedure, 1973.

Procedure where Court considers that case should not be dealt with under Section 345:-

- (1) If the Court in any case considers that a person accused of any of the offences referred to in Section 345 and committed in its view of presence should be imprisoned otherwise than in default of payment of fine, or that a fine exceeding two hundred rupees should be imposed upon him, or such Court is for any other reason of opinion that the case should not be disposed of under Section 345, such Court, after recording the facts constituting the offence and the statement of the accused as hereinbefore provided, may forward the case to a Magistrate having jurisdiction to try the same, and may require security to be given for the appearance of such person before such Magistrate, of if sufficient security is not given shall forward such person in custody to such Magistrate.
- (2) The Magistrate to whom any case is forwarded under this section shall proceed to deal with, as far as may be, as if it were instituted on a police report.

Chapter III

Investigation, Inquiry, Collection of Information, etc.

27. Orders/Directions by the Commission

- (i) The Commission may make such order or orders as it deems fit in terms of the applicable provisions of the Act for collection of information, inquiry, investigation, entry, search, and seizure and without prejudice to the generality of its powers in regard to the following:
 - (a) The Commission may specially authorize any officer, on behalf of the Commission, to enter any building or place where the Commission has reason to believe that any document relating to the subject matter of the inquiry or adjudication under the Act, may be found and may seize any such document or take extracts or copies therefrom;
 - (b) In the exercise of powers conferred on it by Section 128 of the Act, the Commission may, on being satisfied that a licensee or a generating company has failed to comply with any of the conditions of the licence or the provisions of the Act or the rules or regulations made thereunder, at any time, by order in writing, direct any person specified in the order to investigate the affairs of the licensee or generating company and report to the Commission. For this, the

Commission may direct the minimum information to be maintained by the licensees and generating companies in their books and also direct the manner in which such information shall be maintained and the checks and verifications to be adopted.

- (c) The Commission may, at any time, direct the Secretary or any one or more Officers or consultants or any other person as the Commission considers appropriate to study, investigate or furnish information with respect to any matter within the purview of the Commission.
 - (d) The Commission may for the above purpose give such other directions as it may deem fit and specify the time within which the report is to be submitted or information furnished.
 - (e) The Commission may issue or authorize the Secretary or an Officer to issue directions to any person to produce before it and allow to be examined and kept by an Officer of the Commission, designated in this behalf the books, accounts, etc. or to furnish to an Officer information, etc. as provided in the Act.
 - (f) The Commission may, for the purpose of collecting any information, particulars or documents which the Commission consider necessary in connection with the discharge of its functions, issue such directions and follow any one or more of the methods provided for in the Act.
 - (g) If any such report or information obtained appears to the Commission to be insufficient or inadequate, the Commission or the Secretary or an Officer authorized for the purpose may give directions for further inquiry report and furnishing of information.
 - (h) The Commission may direct such incidental, consequential and supplemental matters to be attended to as may be considered relevant in connection with the above.
- (ii) In connection with the discharge of its functions under the Act and the Regulations, the Commission may, if it thinks fit, direct a notice of inquiry to be issued and proceed with the matter in a manner provided under Chapter II of these Regulations.
- (iii) The Commission may, at any time, take the assistance of any institution, consultants, experts, engineers, chartered accountants, advocates, surveyors and such other technical and professional persons, as it may consider necessary, and ask them to study, investigate, inquire into any matter or issue and submit report or reports or furnish any information. The Commission may determine the terms and conditions for engagement of such professionals.

Chapter IV

Tariff Regulations

28. Filing by the Licensees & Generating Companies

- (i) The Commission shall specify the terms and conditions for the determination of the revenues and tariffs of the licensees/generating companies in accordance with the applicable provisions of the Act.
- (ii) The methodologies and procedures for computing the expected revenue from charges, and for determining the tariffs may be provided by the Commission from time to time. The Commission may at any time add, amend, alter, revise, substitute or otherwise change the methodologies and procedures, as the Commission considers appropriate.
- (iii) Unless otherwise directed by the Commission, the terms and conditions for the determination of revenues and tariff of the licensees/generating companies shall include that the tariff allowed and the revenue permitted to a licensee/generating company in any financial year in terms of Section 62 of the Act shall be subject to adjustments in any tariff(s) to be fixed for the subsequent period if the Commission is satisfied for reasons to be recorded in writing that such adjustments for the excess amount or shortfall in the amount, actually realized is necessary, and the Commission is further satisfied that the same is not on account of any reason attributable to the licensee/generating company.
- (iv) Subject to the provisions of the applicable provisions of the Act, each year, a licensee or the generating company shall file with the Commission on or before 30th November, or otherwise as and if so directed by the Commission, in the format and in accordance with the guidelines and procedures issued by the Commission for this purpose, an application for determination of tariff, along with statements containing calculations for the ensuing financial year of the expected aggregate revenue from charges under its currently approved tariff, the expected cost of providing services, and the tariff proposals.
- (v) The statement referred to in sub-regulation (iv) above shall be furnished separately for each separate business of the licensee/generating company and in such manner in respect of each such business as the Commission may direct.
- (vi) Notwithstanding the above, the licensee/generating company shall forthwith furnish to the Commission such additional information, particulars and documents as the Commission may require from time to time prior to, with or after, such filing of

revenue calculations and tariff proposals, in the format that may be directed by the Commission.

- (vii) The Commission may, issue guidelines for filing statement of revenue calculations and tariff proposals and unless waived by the Commission, the licensee/generating company shall follow such guidelines issued by the Commission.

29. Publication of Tariff Proposals & Hearing on Objections

- (i) The licensee or the generating company shall publish within 3 (three) days of submission of its tariff proposals, a notice in at least two (2) newspapers, widely circulated in the area of generation or supply, outlining the proposed tariff and calling for objections from the interested persons and the State Government/Union Territory concerned:

Provided that the notice published in the newspaper shall be in the same language as of the newspaper.

- (ii) Unless otherwise directed by the Commission, the Commission shall hold a proceeding on the revenue calculations and tariff proposals given by the licensee/generating company and may hear such persons as the Commission may consider appropriate for making a decision on such revenue calculations and tariff proposals.
- (iii) The hearing on the revenue calculations and tariff proposals of the licensee/generating company shall, as far as possible, be done in the same manner as provided in Chapter II of these regulations.

30. Order of the Commission

- (i) Subsequent to the licensee or the generating company furnishing the complete information required by the Commission, and upon hearing the applicant and other interested parties and upon making such inquiry as the Commission may consider it to be appropriate, the Commission shall make an order and notify the applicant of its decision on the revenue calculations and tariff proposals.
- (ii) While making an order under sub-regulation (i) above or at any time thereafter the Commission may notify the tariff which the licensee or generating company shall charge.

- (iii) The Commission shall, within seven days of the order forward a copy of the order to the Concerned Government, the Central Electricity Authority and the concerned licensees/generating companies and to the persons concerned.

31. Publication of Tariff

The licensee or the generating company shall publish the tariff or tariffs approved by the Commission in the newspapers having circulation in the State of Goa or the UT(s) concerned as the case may be and if necessary the Commission may also publicize the same for information of all the stakeholders. The publication shall, besides other things as the Commission may require, include a general description of the tariff approved and its impact.

32. Revision of Tariff

- (i) The tariff determined shall not generally be amended or modified more than once in a financial year except in respect of any change expressly permissible under the terms of any fuel surcharge formula as may be provided by the Commission.
- (ii) All applications for amendment of tariff in terms of Section 62(4) of the Act shall be made in such form as the Commission may direct from time to time, and the provisions of Chapter II in so far as they are applicable shall apply to the proceeding for determination/amendment/modification of tariffs.

33. Differential Tariffs and Cross-subsidization

While determining the retail tariff under these Regulations, the Commission may set different tariffs to different persons according to the consumer's load factor, power factor, voltage, consumer's total consumption of energy during any period, or time during which the supply is required or geographical position of any area, the nature of supply and the purpose for which supply is required.

34. Subsidy from Government

- (i) The concerned Government may, at any time as it considers to be appropriate, propose grant of any subsidy to any consumer or class of consumers in the tariff determined by the Commission and upon receiving such proposal, the Commission shall determine the amount to be paid as subsidy and the terms and conditions of such payment

- including the manner of payment of subsidy amounts by the concerned Government to the person affected by the decision of the subsidy.
- (ii) While determining the tariff, the Commission shall take into account any subsidies, which the concerned Government had agreed to give to any class or classes of consumers.
- (iii) Notwithstanding anything mentioned above, no direction of the concerned Government shall be operative if the advance payment of the subsidy amount is not made by the concerned Government in accordance with the provisions of Section 65 of the Act and the tariff fixed by the Commission shall be applicable from the date of issue of orders by the Commission in this regard.
- (iv) The Distribution Licensee shall be required to furnish documents to the satisfaction of the Commission that the subsidy amount received by the Distribution Licensee from the concerned Government is duly accounted for and utilized for the purpose for which the subsidy is given.

Chapter V

Licence

35. Application for Licence

- (i) The regulations contained herein shall apply to all persons desirous of engaging in the business of transmission, distribution or trading of electricity within the State of Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar Island, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry.
- (ii) An application for any licence shall be made in accordance with the provision of the Act and these regulations.
- (iii) The Commission may, if considered appropriate, advertise in newspapers or otherwise notify in such other appropriate manner as the Commission may decide inviting applications for grant of licence for Transmission, Distribution or Trading of Electricity.
- (iv) Every application for a licence shall be signed by the applicant and addressed to the Secretary or such officer as the Commission may designate in this behalf and it shall be accompanied by:
- (a) Six copies in print, and one soft copy of the draft licence as proposed by the applicant with the name and address of the applicant and of his agent (if any) printed on the outside of the draft;

- (b) Three copies, each signed by the applicant, of maps of the proposed service area and, in the case of supply of the streets or roads in which the supply of electricity is to be made, which shall be so marked or coloured as to define any portions of such area and streets or roads which are under the administrative control of any local authority and shall be on a scale:
 - (i) of not less than that of the largest scale ordinance maps available, or
 - (ii) such other scales as may be approved by the Commission.
 - (c) A list of any local authorities invested with the administration of any portion of the area of transmission or supply;
 - (d) An approximate statement describing any lands which the applicant proposes to acquire for the purpose of the licence and the means of such acquisition;
 - (e) An approximate statement of the capital proposed to be expended in connection with the utility and such other particulars as the Commission may require;
 - (f) A copy of the Memorandum and Articles of Association, Annual Accounts for the last three years or other similar documents as may be required;
 - (g) Accompanying notes and certifications, if any, on the above statements, from a chartered accountant;
 - (h) A receipt for such processing fee, as the Commission may require;
 - (i) Applicant's details including technical, capital adequacy and credit-worthiness;
 - (j) Detailed map(s) of the proposed area for transmission/supply, showing the area to be supplied and the configuration of the Transmission/Distribution system. The map(s) shall clearly distinguish between the existing system and any new facilities that are or will be required for the purpose of providing transmission/supply of electricity. The map(s) shall indicate the sub-station, distribution mains, transmission/distribution network, streets and roads on which energy is supplied to various consumers and distinguish between public and private consumers;
 - (k) Copy of letter seeking consent from local authority or consent letter;
 - (l) Copy of letter seeking consent from the Central Government as per Section 15(2) (ii) of the Act or the consent letter.
- (v) Any person intending to act as the Transmission Licensee shall, immediately on making the application, forward a copy of such application to the State Transmission Utility. The State Transmission Utility shall acknowledge the receipt of the application and within thirty days of the receipt of the said application send its recommendations, if any, to the Commission.

36. Copies of maps and draft licence for public inspection

The applicant shall keep at his own office and of his agents (if any) and shall deposit at the office of every local authority invested with the administration of any portion of the proposed area of supply:

- i. Copies of the maps referred to in Regulation 36(iv)(b) above for public inspection; and
- ii. A sufficient number of copies of the draft licence shall be furnished to all persons applying for them at a price not exceeding the normal photocopying charges.

37. Contents of draft licence

The draft licence shall contain the following particulars:

- i. A short title descriptive of the proposed utility together with the address and description of the applicant and if the applicant is a company, the names of all the directors of the company;
- ii. Type of licence applied for;
- iii. Locations of the proposed service area;
- iv. A description of the proposed area; and
- v. Such other particulars as the Commission may direct.

38. Conditions of Licence

- a. The General Conditions subject to which each of the categories of licence shall be laid down by the Commission.
- b. The Commission may decide on the special conditions subject to which licence shall be issued to the applicant.
- c. Any person intending to apply for licence shall duly comply with the conditions and requirements laid down by the Commission.

39. Form of Draft Licence

The Commission may, from time to time, prescribe the form of licences to be issued and this form of licences may, with such variation as the circumstances of each case require, be used for the purposes of these Regulations.

40. Acknowledgement of Application

On receipt of the application, the Receiving Officer shall note thereon the date of its receipt and shall send to the applicant an acknowledgement stating the date of receipt.

41. Calling for additional information

The Commission or the Secretary or any other officer so authorized by the Commission for this purpose, may upon security of the application, require the applicant to furnish within a period to be directed by it such additional information or particulars or documents as considered necessary for the purpose of dealing with the application.

42. Notifying the due filing of the application

If the Commission finds the application to be complete, accompanied by the requisite information, particulars and documents, and finds that the applicant has complied with all the requirements for making the application and furnishing of information, particulars and documents, the Commission or the Secretary shall certify that the application is ready for being considered for grant of licence in accordance with the applicable laws.

43. Advertisement of application and contents thereof

- a. Unless exempted by the applicable laws/Commission, the applicant shall, within seven (7) days from the date of admission of the application, publish notice of his application by public advertisement, and such advertisement shall contain such particulars as have been directed by the Commission in these Regulations.
- b. The advertisement shall be headed by a short title corresponding to that given at the head of the draft licence and shall give the addresses of the offices at which copies of maps therein referred to may be inspected and the copies of draft licence perused or purchased and shall state that every local authority, utility or person, desirous of making any representation/objection with reference to the application to the Commission, may do so by letter addressed to Secretary or such Officer as the Commission may designate in this behalf, within thirty (30) days from the date of publication of the first advertisement.

- c. The Commission may direct that notice of the application be served on the Central Government, the concerned Government, the local authority or any other authority or person or body as the Commission may direct in such other manner, as the Commission may consider appropriate. Further, in the case of an application for a licence for an area including the whole or any part of any cantonment, aerodrome, fortress, arsenal, dockyard or camp or of any building or place in the occupation of the Government for defense purposes, the Commission shall issue a licence only after ascertaining that the Central Government has no objection to the grant of the licence.

44. Amendment of draft licence

Any person who desires to have any amendment made in the draft licence shall deliver a statement of the amendment to the applicant and to Secretary or such Officer as the Commission may designate in this behalf within a period thirty (30) days from the date of publication of notice of the application by way of advertisement in newspapers.

45. Objections

- a. Any person intending to object to the grant of the licence shall file objection within a period of thirty days from the date of publication of notice of application in newspapers. The objection shall be filed in the form of a reply and the provisions of Chapter II dealing with a reply shall apply to the filing of such objections.
- b. When applicable, the applicant shall apply for and obtain the no objection required from the Central Government before the application can be placed for hearing by the Commission for grant of the licence.

46. Local Inquiries and Hearings

- a. If the applicant has duly arranged for the publication of the notice of the intended application and the time for filing of the objections is over and after the applicant has furnished to the Commission the no objection, if required from the Central Government, the Commission may proceed to place the application for regular hearing.

- b. The Commission shall give the notice of inquiry or hearing to the applicant, the persons who had filed objections, the Central Government, the concerned Government and such other authority, person or body as the Commission considers appropriate.
- c. The Commission shall consider the recommendations, if any, from the State Transmission Utility in regard to the grant of licence.
- d. If any person objects to the grant of licence applied for, the Commission shall, if either the applicant or the objector so desires, cause a local inquiry to be held of which the notice in writing shall be given to both the applicant and the objector:

Provided that the Commission may refuse such an inquiry if in its opinion the objection is of a trifling or vexatious nature.

- e. In case of such local inquiry, a memorandum of results of the local inquiry made shall be prepared and shall be signed by the applicant, the Officer or person designated for the purpose and such other person as the Commission may direct.
- f. The hearing on the application for grant of licence shall thereafter proceed as far as possible in the same manner as provided in Chapter II.

47. Approval of draft licence

- a. After inquiry, if any, and the hearing, the Commission may decide to grant or refuse the licence and if it decides to grant the licence, it may do so by approving the draft licence with such modifications changes or additions and subject to such other terms and conditions as the Commission may direct.
- b. When the Commission has approved a draft licence either in its original form or in a modified form, the Secretary or such other officer as the Commission may designate in this behalf, shall inform the applicant of such approval and of the form in which it is proposed to grant the licence and the conditions to be satisfied by the applicant including the fees to be paid by the applicant for the grant of the licence.
- c. Before granting any licence, the Commission shall publish a notice in two such daily newspapers, as the Commission may consider necessary, stating name and address of the person to whom it proposes to issue the licence.
- d. The Commission shall immediately after issue of a licence forward a copy of the licence to the concerned Government, Central Electricity Authority, local authority, and to such other persons as the Commission considers necessary.

48. Notification of grant of licence

On receiving intimation in writing from the applicant that he is willing to accept the licence in the form approved by the Commission and after the applicant satisfies the conditions imposed for the grant of the licence, the Commission shall publish the licence or such part or gist thereof as the Commission considers appropriate.

49. Date of commencement and duration of licence

The licence shall commence from the date the Commission may direct as the date of commencement of licence and shall be valid for a period of twenty-five years, unless revoked earlier.

50. Deposit of maps

When a licence has been granted, three sets of maps showing, as regards such licence, the particulars specified in Regulation 35(iv)(b) above shall be signed and dated to correspond with the date of the notification of the grant of the licence by Secretary or any other officer designated by the Commission. One set of such maps shall be retained as the deposited maps by the said Officer and the other two sets given to the licensee.

51. Deposit of printed copies

- a. Every person who is granted a licence shall within thirty days of the grant thereof:
 - i. Have adequate number of copies of the licence printed;
 - ii. Have adequate number of maps prepared showing the area of supply stated in the licence;
 - iii. Arrange to exhibit a copy of such licence and maps for public inspection at all reasonable times at his head office, at his local offices (if any) and at the office of every local authority within the area of supply.
- b. Every such licensee shall, within the aforesaid period of thirty days, supply free of charge one copy of the licence and the relevant maps to every local authority within the area of supply and shall also make necessary arrangements for the sale of printed copies of the licence to all persons applying for the same, at a price not exceeding the normal photocopying charges.

52. Preparation and submission of accounts

- a. Every licensee shall cause the accounts of his utility to be made up the thirty-first day of March each year.

- b. Such licensee shall prepare and render to the Commission an annual statement of his audited accounts in accordance with the provisions of the Act, within a period of six months from the aforesaid date, or such extended period as the Commission may authorize after it is satisfied that the time allowed is insufficient owing to any cause beyond the control of the licensee and the statement shall be rendered in such numbers of copies as the Commission directs.
- c. The accounts shall be made up in such forms as the Commission may direct from time to time. All the forms shall be signed by the licensee or his accredited and duly authorized agent or manager.
- d. The Commission may by special or general order direct that, in addition to the submission of the annual statements of accounts in the forms directed in sub-regulation (iii) above, a licensee shall submit to the Commission or such other authority as it may designate in this behalf such additional information as it may require for the purpose.

53. Model Conditions of Supply

- a. The Commission shall specify the model conditions of supply to be adopted and complied by the licensee, with such variations as the Commission may direct from time to time.
- b. The licensee shall always keep in his office an adequate number of printed copies of the Codes formulated under the provisions of Chapter IX of these Regulations, as amended from time to time and shall, on demand, sell such copies to any applicant at a price not exceeding normal photocopying charges and shall take steps to give suitable publicity to the documents.

54. Contravention of Licence

- a. The Commission may pass such orders, as it thinks fit, in accordance with the relevant provisions of the Act, for the contravention or the likely contravention, by a licensee, of the terms or conditions of the licence, any provisions of the applicable law or the rules or regulations made there under.
- b. Subject to the provisions of the Act, the Commission may follow as far as possible the general procedure directed in Chapter II of these Regulations in dealing with a proceeding arising out of a contravention or likely contravention by a licensee.

55. Deemed grant of the Distribution Licence

- a. Until otherwise directed by the Commission, the following classes of persons engaged in the supply of electricity in the State of Goa and Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshdweep and Puducherry

shall be deemed to have applied for and been granted the Distribution Licence for the purposes contained herein and subject to the fulfillment of the conditions contained in sub-regulation (b) below.

- i. Persons who supply electricity generated by themselves and/or supplied to them by an authorized person, for the purposes of an event or function not exceeding two months, and when the electricity is distributed through a system owned by them;
 - ii. Persons who supply electricity to the residential colonies as a part of their activity of maintaining such colonies for use and occupation of their employees and/or for use and occupation of persons providing facilities and services to the employees, where such person procures electricity from any Licensee or from any other source approved by the Commission and distributes the electricity within the residential colonies on no-profit motive basis;
 - iii. Such other persons as the Commission may from time to time by order notify, subject to such terms and conditions as the Commission may direct.
- b. The persons referred to in sub-regulation (i) above shall:
- i. Not directly or indirectly undertake trading in electricity or distribution or supply of electricity outside its area of operation and the distribution or supply of electricity shall be strictly restricted to the purpose mentioned in sub-regulation (i) above;
 - ii. Establish the electric line or works only within the area of operation;
 - iii. If so required, furnish to the Commission such information required for the purposes of the discharge of the functions of the Commission as the Commission may from time to time direct;
 - iv. Comply with the provisions of the Act, the Regulations of the Commission, technical codes such as Grid Code, Distribution Code, Standards of Performance and Overall Standards of Performance or any other guidelines issued by the Commission;
 - v. Comply with all applicable rules and regulations concerning the safety and security of the operation; and
 - vi. Comply with any directions which the Commission may issue from time to time in regard to the charges which such persons may levy on the consumers taking into account the charges prevailing in the nearby area of supply of electricity supplied by a licensee.
- c. The Commission shall be entitled to issue appropriate directions from time to time as it may consider necessary and take appropriate actions against such persons in accordance with the provisions of the Act and these Regulations for any breach or non-compliance thereof.
- d. The Commission, at any stage, if it considers to be necessary, direct any such, persons to apply for a licence in accordance with Regulation 35 above and consider accordingly the

grant or refusal of licence and may by an interim or final order directs such a person to cease to distribute or supply electricity in the area of operation or any part thereof.

- e. If any difference or dispute arises as to whether the person is entitled to undertake supply of electricity as a Licensee under the provisions of this regulation 55, the decision of the Commission, thereon shall be final.

56. Grant of exemption from licence

An exemption from licence shall be granted in a manner that is consistent with the provisions of the applicable law and provision of the Act.

57. Revocation of the licence

- a. The proceedings for revocation of the licence or for passing of any other orders stated in Section 19 of the Act, shall be initiated by an order passed by the Commission, which the Commission may initiate *suo motu* or on application of the licensee or on receiving any complaint or information from any person.
- b. The procedure and the manner of revocation shall be consistent with the provisions inter-alia of Section 19 of the Act.
- c. Subject to the provisions of the Act and the procedure contained therein, the inquiry by the Commission on the revocation of the licence, in so far it is applicable, shall be in the same manner as provided in Chapter II of these Regulations.
- d. A licensee himself wishing to apply for or give consent to the revocation or part revocation of his licence may make an application to the Commission. The Commission shall pass orders on such applications, after hearing the licensee and such other persons as it thinks fit. The procedure to be followed by the Commission on such application shall be as far as possible as provided in Chapter II of these Regulations.

58. Amendment of the licence granted

- a. Amendment of the licence shall take place in the manner laid down in Section 18 of the Act. Unless otherwise directed by the Commission in writing, the procedure specified in these Regulations for grant of licence, in so far it can be applied, shall be followed while dealing with an application for amendment or alternation of the licence.
- b. The application for amendment of the licence shall be accompanied by a statement of the proposed amendment and shall be supported by affidavit as provided in Chapter H. of these Regulations.
- c. Unless otherwise directed by the Commission in writing, each application for an

amendment or alteration in the licence shall be accompanied by a receipt for such fee as the Commission may require and paid in the manner directed by the Commission.

- d. The applicant shall, within seven days from the date of admission and numbering of the application for amendment, publish a notice of the amendment application filed giving a brief statement of the amendment proposed, the reason for the proposed amendment, the effect of the amendment proposed on the discharge of the functions of the Licensee under the licence granted, the alternate arrangement proposed for such discharge of the functions and such other particulars as the Commission may direct. The publication shall give the addresses of the offices at which the application for amendment may be inspected and the copies of documents be purchased and shall state that every local authority, utility or person, desirous of making any representation with reference to application to the Commission, may do so by letter addressed to such Officer as the Commission may designate in this behalf, within thirty days from the date of publication.

59. Suspension of Distribution Licence

If at any time, it is of the opinion that it is necessary in public interest, the Commission may, for reasons to be recorded in writing, suspend the licence of the distribution licensee in the circumstances, manner and form given in Section 24 of the Act.

60. Regulation of licensee's purchase of power

- a. The licensee shall file with the Commission in complete form copies of all Power Purchase Agreements already entered into by the licensee.
- b. The Commission shall be entitled to direct that the licensee shall establish to the satisfaction of the Commission that the purchase of power by the licensee is under a transparent power purchase procurement process and is economical and the power is necessary for the licensee to meet its service obligation
- c. The licensee shall apply to the Commission to approve the draft Power Purchase Agreement that the Licensee proposes to enter into. The Commission may pass orders:
 - i. Approving the agreement; or
 - ii. Approving the agreement with modifications proposed to the terms of the agreement; or
 - iii. Rejecting the agreement.
- d. Nothing contained herein shall affect the obligations of distribution licensee under the existing contracts and arrangements for purchase, import or acquisition of electricity from generating companies, electricity traders and from other persons with whom the licensee

has agreements or arrangements of power purchase or procurement of energy in accordance with the terms and conditions of such agreements and arrangements consented to or approved by the Commission.

- e. The provisions of sub-regulation (ii) and (iii) above or any action taken therein shall not, in any manner, prejudice the exercise of functions and powers of the Commission under any of the other provisions of the applicable law, the Regulations and orders to be issued from time to time.

61. Standards of Performance

The Commission may, after consultation with the licensees and persons likely to be affected, specify standards of performance of a licensee or a class of licensees which in its opinion, are attainable and ought to be achieved by such licensees, and different standards may be determined for different licensees. The Commission may publish the standards so determined in such form and in such manner as the Commission may consider appropriate.

Chapter VI

Investment Approvals

62. Requirement for Investment Approval by the Commission

- (i) Unless otherwise directed by the Commission, every licensee shall obtain prior approval of the Commission for making investment in the licensed business if such investment is above the limits laid down by the Commission in the licence conditions.

- (ii) The limits in the licence conditions may be modified by the Commission from time to time by a general or special order.

- (iii) In the application for investment approval, the licensee shall furnish the following information or particulars:

- (a) A detailed project report containing examination of an economic technical system and environmental aspects of the investment together with the outline of the working to be undertaken, the salient features and particulars demonstrating the need for investment;
- (b) The project cost together with the cost-benefit analysis;
- (c) Whether the investment is in a new project or for expansion or upgradation of an existing system;
- (d) Sanctions and statutory clearances required for execution of the project and status of

- such sanctions and statutory clearances;
- (e) Phasing of investment over the financial years and commissioning schedule;
 - (f) The manner in which investments will be capitalized for the purposes of inclusion in the revenue requirements of the Licensee;
 - (g) Constraints which the Licensee may face in making the investments or in implementing the project including constraints on information available;
 - (h) Resource mobilization and financial plans for meeting the investment;
 - (i) Process for inviting and finalizing tenders for procurement of equipment, material and /or services relating to investment, in accordance with a transparent tendering procedure as may be approved by the Commission; and
 - (j) Such other particulars as the Commission may from time to time direct.

63. Proceedings by the Commission

- (i) The Commission may at its discretion hold such inquiries and consultations as the Commission may consider appropriate while dealing with the application for approval for the investment to be made by the licensee.
- (ii) The Commission may at its discretion initiate a proceeding or consider the application for investment approval as a part of the proceedings for determination of tariff or along with any other proceedings as the Commission may consider appropriate.
- (iii) The Commission shall be entitled to appoint consultants, experts and others as the Commission may consider appropriate and authorise the Commission's staff, consultants and experts to hold discussions and deliberations with the licensees before the Commission considers the application for investment approval which shall be accompanied by such fee as may be directed.

64. Additional Information

- (i) The licensee and other applicants seeking investment approval shall furnish information, particulars, documents as may be required by the Commission staff, consultants and experts appointed by the Commission for the purpose and allow them access to the records and documents in the power, possession or custody of the licensee.
- (ii) The licensee shall cooperate with the Commission's staff, consultants and experts to enable them to discharge their functions and to submit a report to the Commission on the outcome of their findings.

Chapter VII

Settlement of Disputes

65. Arbitration

- (i) On disputes, between the licensees and the generating companies being brought before the Commission or coming to Commission's notice otherwise, the Commission may take up the same for adjudication or arbitration.
- (ii) If the Commission decides to adjudicate on a dispute itself, it may take such help from experts, specialists as it considers necessary.
- (iii) If the Commission decides to refer the matter for arbitration, the same will be done in accordance with the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

66. Nomination of Arbitrators

- a. If the Commission decides to refer the matter to arbitration by a person or persons other than the Commission itself, the reference shall be:
 - i. To a sole arbitrator if the parties to the dispute agree on the name of the arbitrator; or
 - ii. If the parties are unable to agree on the name of a sole arbitrator, to a sole arbitrator to be designated by the Commission or to three persons as the Commission may direct taking into account the nature of the dispute and the value involved. If the decision is to refer to three arbitrators, one shall be nominated by each of the parties to the dispute and the third by the Commission:

Provided that if any of the parties fails to nominate the arbitrator or if any of the arbitrators nominated by the parties or the Commission fails or neglects to act or continue as arbitrator, the Commission shall be entitled to nominate any other person in his place.
- b. The Commission shall not nominate a person as arbitrator to whom any party to the arbitration has a reasonable objection on grounds of possible bias or similar such reasons, if the Commission considers the objection to be valid and justified.
- c. The fees and expenses of the arbitration and proceedings before the Commission shall be borne by such parties and in such sums as the Commission may direct.

67. Procedure for adjudication, settlement and passing of award

In case the Commission decides to adjudicate upon a dispute itself, the procedure for adjudication and settlement to be followed shall be as far as possible the same as in the case of hearing before the Commission provided in Chapter II.

Chapter VIII**Fees & Fines****68. Fees on applications or petitions**

- a. The fees payable for filing of any petition, application or complaint with the Commission shall be as specified in the Schedule to these regulations.
- b. The fees payable under these regulations shall be paid by means of bank draft or pay order, drawn in favour of the Secretary, Joint Electricity Regulatory Commission, payable at Gurgaon, Haryana.
- c. The fees received by the Secretary of the Commission under these regulations shall be deposited in a bank account to be maintained by the Commission at such bank and in such Branches as the Commission may direct from time to time or in Government Account under relevant head of account.

69. Licence Fees

- a. The Commission may while granting a licence or an Exemption to undertake the business of transmission or supply of electricity including bulk supply of electricity or any other order granting any privilege to any person may levy and collect the fee payable in accordance with provisions of the Act and these or any other regulations issued by the Commission, at the time of the grant of licence or privilege and thereafter on an annual or such periodic basis as the Commission may specify in the order granting licence or privilege or in a separate order that may be passed by the Commission.
- b. The existing licensees or exemption holders shall pay the annual fee for the financial year 2009-10 onwards as specified in the Schedule and for the period prior to 2009-10 the same shall be levied on case to case basis through separate orders as may be passed by the Commission.
- c. Until otherwise specified, the fees payable for grant of licence or exemption, shall be as specified in the Schedule to these Regulations.
- d. The fees shall be payable and the amount shall be deposited in the same manner as specified in Regulation 68 above.

70. Imposition of Fines and Charges

- a. The Commission may initiate a proceeding for imposition of fines and charges and award of compensation upon receiving from the person affected a complaint or on its own if the Commission is of the view that the facts made known *prima-facie*

constitute non-compliance or violation by a generating company, a licensee or other person of any provision or requirement of the Act or of any of the rules or regulations framed there under or of directions or orders of the Commission.

- b. If the Commission decides on the basis of the information received that there is a *prima-facie* cause to proceed in the matter, a case shall be registered and notice shall be issued to the person who is responsible for non-compliance or violation under sub-regulation (i) above to show cause within a reasonable time, as indicated in the notice, to appear before the Commission in person or through his authorized representative to explain as to why the Commission should not impose the fines or charges on him. The notice shall state the substance of the allegation against such person with specific reference to the alleged non-compliance or violation.
- c. On the date fixed in the notice for appearance, the Commission shall explain to the person who is *prima-facie* responsible for non-compliance or violation or his authorized representative, the non-compliance or violation alleged to have been committed by such person.
- d. Where the person who is responsible for non-compliance or violation appears in response to the notice and admits the truth of the allegation by a memorandum in writing, the Commission shall record the response and may impose fines and charges at its discretion in accordance with the provisions of the Act and the Regulations framed by the Commission for the purpose and may also award compensation to the affected person(s).
- e. Where the person who is responsible for non-compliance or violation on appearance does not admit the alleged violation or non-compliance and demands a hearing, the Commission shall proceed to hear the case in accordance with the provisions of the Act and the Regulations.
- f. If any person to whom a notice has been issued fails without reasonable cause to appear before the Commission on the date fixed for hearing or any subsequent date to which the proceeding may have been adjourned, the Commission may at its discretion proceed with the case *ex parte* in the absence of such person.
- g. The Commission shall proceed to hear the complainant and take all such evidence, oral or documentary, or by way of affidavit, as may be produced in support of the case and take all such evidence as may be produced by the person who is responsible for non-compliance or violation in his defence. Where the proceeding has been initiated upon information received by the Commission, it may direct any of its officers to act as complainant in the matter and present the evidence in the case.
- h. The Commission, at any stage of the proceeding, shall have the power to summon and enforce the attendance of any person who appears to be acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the Commission appears to be material or relevant to the subject matter of the proceeding.

71. Process for Levy and Recovery of Fines and Charges

- a. If on the conclusion of any proceeding, the Commission is satisfied that any person is liable to fines or charges, it may by order in writing impose such fines or charges in accordance with the provisions of the Act and the Regulations specified for the purpose and may also award compensation.
- b. While determining the quantum of fines or charges, the Commission shall, inter-alia, consider the following factors:
 - i. The nature and extent of non-compliance or violation;
 - ii. Wrongful gain or unfair advantage derived as a result of the non-compliance or violation;
 - iii. Loss or degree of harassment caused to any person(s) as a result of the non-compliance or violation; and
 - iv. The repetitive nature of the non-compliance or violation.
- c. While passing an order under this regulation, the Commission may award compensation to the complainant or affected party to be paid by the person found to have committed the non-compliance or violation.
- d. The Commission may direct the time within which the fines, charges or compensation should be paid by the concerned person.
- e. The Commission may designate an Officer to collect the fines and charges pursuant to the provisions of the Act.

72. Withdrawal and Disposal of Complaint

- a. If a complainant, at any time before a final order is passed in any proceeding satisfies the Commission that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint against the respondent named in the complaint, or if there be more than one respondent, against all or any of them, the Commission may permit the complainant to withdraw the same.
- b. If the Commission is of the opinion that it will not be appropriate to allow the withdrawal of the complaint, the Commission may make orders for the complaint being continued by such other person in the place of the complainant and in such manner as the Commission may consider appropriate.
- c. Where the Commission is of the opinion that the continuance of the proceeding under this regulation is unnecessary or is an abuse of the process, it may at any stage, terminate the proceeding for reasons to be recorded in writing.

Chapter IX**Performance Standards, Codes, Supply Regulations, etc.****73. Formulation of Codes**

- a. The Commission may from time to time direct the licensees and generating companies operating in the State/UT, as the case may be, to formulate or adopt such codes as the Commission considers appropriate for the proper and efficient conduct of the electricity sector and operation of the power systems in the State/UT.
- b. The Commission may hold such consultations and proceedings as it considers appropriate to deliberate on the codes so formulated.
- c. The Commission may appoint consultants or experts to advise the Commission on the codes so formulated.
- d. The Commission may direct such modifications as it considers appropriate to the codes so formulated.
- e. The licensees and generating companies shall implement the codes approved by the Commission consistent with the directions and orders made by the Commission from time to time.
- f. Without prejudice to the generality of the powers of the Commission in regard to the enforcement of standards of performance in operation of the power system, the codes to be formulated and implemented may include:
 - i. Grid Code;
 - ii. Distribution Code;
 - iii. Electricity Supply Code and Conditions of Supply;
 - iv. Consumer related codes including code of practice on payment of bills; code on disconnection for non-payment, standards and quality of service and fines and penalties for failure, consumer rights, settlement and consumer complaint handling procedures;
 - v. Safety and security codes;
 - vi. Transmission system planning and Security Standards;
 - vii. Distribution system planning and Security Standards;
 - viii. Operating standards; and
 - ix. Codes on utilization of electricity and demand side management.
- g. The Licensees and generating companies shall follow the existing standards, codes and conditions of supply till the codes, standards and conditions of supply are formulated and implemented in accordance with this regulation.

Chapter X**Miscellaneous****74. Review of the decisions, directions and orders**

- (a) The Commission may at any time on its own motion or on the application of any of the persons or parties concerned, within 45 days of the making of any decision, direction or order, review such decisions, directions or orders and pass such appropriate orders as the Commission thinks fit:

Provided that power of review by the Commission on its own motion shall be exercised limited to correction of clerical or typographical errors.

- (b) An application for such review shall be filed in the same manner as a Petition under Chapter II of these regulations.

75. Continuance of Proceeding after death, etc.

- a). Where in any proceeding any of the parties to the proceeding dies or is adjudicated as insolvent or is in the case of a Company under liquidation/winding up, the proceedings shall continue with the successor-in-interest, the executor, administrator, receiver, liquidator or other legal representative of the party concerned.
- b). The Commission may, for reasons to be recorded, treat the proceeding as abated, and in case the Commission so directs, dispense with the need to bring the successors-in-interest, etc. on the record of the case.
- c). In case any person wishes to bring on record the successors-in-interest, etc. the application for the purpose shall be filed within 90 days from the event requiring the successors-in-interest to come on record.

76. Proceedings to be open to public

The proceedings before the Commission shall be open to the public:

Provided that the Commission may, if it thinks fit, and for reason to be recorded in writing, order at any stage of the proceedings of in any particular case that the public generally or any particular person or group of persons shall have restricted access to proceedings.

77. Publication of Petition

- (j) Where any application, petition, or other matter is required to be published under the Act or the Regulations or as per the directions of the Commission, it shall, unless the Commission otherwise orders or the Act or Regulations otherwise provide, be published not less than 7 days before the date fixed for hearing.
- b. Except as otherwise provided, such publication shall give a heading describing the subject matter in brief.
- c. Such publication to be published shall be approved by the Officer of the Commission designated for the purpose.

78. Issue of orders and directions on procedures

Subject to the provisions of the Act and the Regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions in regard to the implementation of the Regulations and procedure to be followed and various matters, which the Commission has been empowered by the Regulations to specify or direct.

79. Saving of inherent power of the Commission

- a. Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent the abuse of the process of the Commission.
- b. Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting, in conformity with the provisions of the Act, a procedure, which is at variance with any of the provisions of the Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.
- c. Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, bar the Commission to deal with any matter or exercise any power under the Act for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

80. Power to amend any defect, error, etc. in proceedings/pleadings

The Commission may, at any time and on such terms as to costs or otherwise, as it may think fit, amend any defect or error in any proceedings before it, and all necessary amendments shall be made for the purpose of determining the real question or issue arising in the proceedings.

81. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or special order, do anything not being inconsistent with the provisions of the Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

82. Extension or abridgement of time prescribed

Subject to the provisions of the Act, the time prescribed by the Regulations or by order of the Commission for doing any act may be extended (whether it has already expired or not) or abridged for sufficient reason by means of an order of the Commission

83. Effect of non-compliance

Failure to comply with any requirement of these Regulations shall not invalidate any proceeding merely by reason of such failure unless the Commission is of the view that such failure has resulted in miscarriage of justice.

84. Costs

- a. Subject to such conditions and limitation as may be directed by the Commission, the cost of and incidental to, all proceedings shall be awarded at the discretion of the Commission and the Commission shall have full power to determine by whom or out of what funds and to what extent such costs are to be paid and give all necessary directions for the aforesaid purposes.
- b. The costs shall be paid within 30 days from the date of the order or within such time as the Commission may, by order, direct. The order of the Commission awarding costs shall be executed in the same manner as the decree/order of a Civil Court.

85. Enforcement of orders passed by the Commission

The Secretary shall ensure enforcement and compliance of the orders passed by the Commission, by the persons concerned in accordance with the provisions of the Act and Regulations and if necessary, may seek the orders of the Commission for directions.

86. General power to amend

The Commission may, at any time, add, vary, alter, modify or amend any of the provisions of these Regulations.

SCHEDULE

(Reference: Regulation 68 of Conduct of Business Regulations, 2009)

FEES & CHARGES

S. No.	Description	Fees (in Rupees)
1.	Adjudication of dispute regarding availability of transmission facility under the second proviso to sub-section (2) of Section 9 under the Act, to be paid by the person who has referred such dispute to the Commission.	Rs. 10,000 for the first 1 MW of transmission capacity sought and Rs. 1,250 per MW thereafter, subject to a maximum of Rs. 1,00,000.
2.	Initial licence fee upon grant of licence under Section 15 of the Act	Rs. 50,000 as "on account" payment pending determination of fees by the concerned Government.
3.	<p>Annual Licence Fees:</p> <p>(i) Transmission Licence</p> <p>(ii) Distribution Licence</p> <p>(iii) Trading Licence:</p> <p>Provided that the annual licence fee shall be payable in advance, at the commencement of the financial year, by all Licensees, including licensees referred to in the first, second, third, fourth and fifth provisos to Section 14 of the Act:</p> <p>Provided further that in the case of a Transmission Licence, the annual licence fee shall be calculated based on the approved/estimated aggregate quantum of transmission capacity contracts for the ensuing financial year:</p> <p>Provided also that in the case of a Distribution Licence, the annual licence fee shall be calculated based on the approved/estimated revenue from the sale of electricity for the ensuing financial year:</p> <p>Provided also that in the case of a Trading Licence, the annual licence fee shall be calculated based on the approved/estimated revenue from the sale of electricity for the ensuing financial year, excluding revenues from sales of electricity to a Licensee within the State/UT concerned itself:</p> <p>Provided also that where the actual transmission capacity contracted or actual revenue from the sale of electricity, as the case may be, differs from the approved/estimated level used for the purpose of this Regulation, the excess or shortfall in licence fee, calculated based on the actual transmission capacity contracted or actual revenue, as the case may be, shall be adjusted against the annual licence</p>	<p>(i) Rs. 1,000 per MW of transmission capacity contracts in force during the year or part thereof, subject to a minimum of Rs. 1,00,000 and maximum of Rs. 20,00,000.</p> <p>(ii) 0.05 percent of revenue (excluding taxes and duties) from the sale of electricity.</p> <p>(iii) 0.05 percent of revenue (excluding taxes and duties) from the sale of electricity.</p>

	fee for the following year.	
4.	Application seeking prior approval under Section 17 of the Act.	0.01 percent of the value of the transaction for which approval is sought, subject to a minimum of Rs. 5,00,000 and maximum of Rs. 20,00,000.
5.	Application for amendment of licence under Section 18 of the Act (i) by Licensee (ii) by any person other than a Licensee	(i) Rs. 1,00,000 (ii) Rs. 10,000
6.	Application for revocation of licence under sub-section (2) of Section 19 of the Act (i) by Licensee (ii) by any person other than a Licensee	(i) Rs. 10,00,000 (ii) Rs. 1,00,000
7.	Application under Section 35 of the Act for seeking the use of intervening transmission facilities	Rs. 50,000
8.	Adjudication of dispute regarding extent of surplus capacity under the proviso to Section 35 of the Act	Rs. 5,00,000
9.	Application for determination of rates, charges, terms and conditions under proviso to sub-section (1) of Section 36	Rs. 2,50,000
10.	Adjudication of disputes regarding provision of non-discriminatory open access under sub-section (47) of Section 2 read with Section 40 of the Act and regulations specified thereunder, not covered above: (i) referred by a Licensee or by a Generating Company. (ii) referred by person who has constructed and maintains and operates a Captive Generating Plant (iii) referred by Consumer/Consumer Representative	(i) Rs. 5,00,000 (ii) Rs. 25,000 (iii) Rs. 5,000
11.	Adjudication of disputes regarding provision of non-discriminatory open access under sub-section (47) of Section 2 read with sub-section (2), (3) and (4) of Section 42 of the Act and regulations specified thereunder: (i) Referred by a Licensee or by a Generating Company, other than a Generating Company referred to in (ii) Below (ii) Referred by a Generating Company directly connected to the distribution system of a Distribution Licensee or by Person who has constructed, maintains and operates a Captive Generating Plant (iii) Referred by consumer/Consumer Representative	(i) Rs. 5,00,000 (ii) Rs. 25,000 (iii) Rs. 5,000
12.	Determination of tariff under the provisions of clause (a) of sub-section (1) of Section 62, to be paid by the applicant: (a) Conventional fuel based (coal, oil etc) Plant	Rs. 10,00,000 for capacity up to 100 MW. Rs. 10,000 for each additional MW

	<p>(b) Non-conventional & Renewable Sources of Energy, including co-generation</p> <p>(c) Generic Determination of tariff for a class of projects.</p>	<p>or part thereof capacity</p> <p>Rs. 1,00,000 installed capacity of MW or Rs. 5,00,000 for capacity above 10 MW.</p> <p>Lowest of fees/charges payable as at (a) and (b) above, as may be applicable.</p>
13.	<p>Annual/base year determination of tariff for transmission of electricity under the provisions of clause (b) of sub-section (1) of Section 62, to be paid by Licensee:</p> <p>Provided that such fees are payable whether such determination is upon application by the Licensee or by any other Person or suo motu determination by the Commission.</p>	Rs. 15,00,000
14.	<p>Annual/base year determination of tariff for wheeling of electricity under the provisions of clause (c) of sub-section (1) of Section 62, to be paid by Licensee:</p> <p>Provided that such fees are payable whether such determination is upon application by the Licensee or by any other Person or suo motu determination by the Commission.</p>	Rs. 5,00,000
15.	<p>Annual/base year determination of tariff for retail sale of electricity under the provisions of clause (d) of sub-section (1) of the Section 62, to be paid by the Licensee:</p> <p>Provided that such fees are payable whether such determination is upon application by the Licensee or by any other person or suo motu determination by the Commission.</p>	Rs. 5,00,000 plus Rs. 500 per MVA of peak demand up to a maximum of Rs. 20,00,000
16.	Annual review of tariffs and performance of the Licensee during the control period under a multi-year tariff framework, to be paid by the Licensee	Rs. 5,00,000
17.	Application for review of Tariff Order or power purchase agreement or power procurement rate by Licensee	10 percent of the fees paid at the time of the original application for determination of tariff
18.	Application by a consumer or a Consumer Representative for review of Tariff Order or power purchase agreement or power procurement rate	Rs. 25,000
19.	Application by a person other than the Licensee or a consumer/Consumer Representative for review of Tariff Order or power purchase agreement or power procurement rate	Rs. 1,00,000
20.	Application for approval of the schedule of charges of a Distribution Licensee under Section 45 and Section 46 of the Act	Rs. 1,00,000
21.	Adjudication under clause (f) of sub-section (1) of section 86 of disputes Between licensees and generating	Rs. 5,00,000

	companies and between licensees themselves, not covered elsewhere in these Regulations.	
22.	Application for review of Order passed under clause (f) of sub-section (1) of Section 86 of the Act.	10 percent of the fee paid for the original order.
23.	Application for inspection of Orders/Records of the Commission	Rs. 100 per day or part thereof
24.	Supply of copies of documents/order of the Commission	Rs. 3 per page
25.	Application for review of Orders of Commission not covered elsewhere in these Regulations	Rs. 10,000
26.	Miscellaneous applications, i.e. application not covered elsewhere in these Regulations:	
	(a) Applications by Licensees	Rs. 10,000
	(b) Applications by entities	Rs. 1,000
	(c) Applications by Individuals	Rs. 500

J. S. SEHRAWAT, Secy.
[ADVT III/4/218 I/09-Exty.]

Annexure I

Form JERC-1

(See Regulation 12 of Conduct of Business Regulations)

Joint Electricity Regulatory Commission for the State of
Goa and Union Territories

Fee Register

Sl. No.	Petition/ Application No.	Name of party remitting DD/Pay Order	Purpose of remittance of DD/Pay Order	No. & Date of DD/Pay Order	Particulars of IPO/DD Amount	Name of the Bank	Name & initials of clerk	Name & initial of Officials to whom pay order has been passed	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Form JERC-2

(See Regulation 13 of Conduct of Business Regulations)

**General Heading for Proceedings
BEFORE THE JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES**

FILING NO.:

CASE NO.:

(To be filled by the Office)

IN THE MATTER OF:

Names of the Petitioners/Applicants

..... **Add Description and Address(es)**

V/s

Name of the Respondents

..... **Add Description and Residence/Address(es)**

AND

IN THE MATTER OF:

(Gist of the purpose of the Petition or application)

Annexure-III**Form JERC-3***Affidavit*

(See Regulation 14 of Conduct of Business Regulations)

**BEFORE THE JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES**

FILE NO.

CASE NO. (To be filled by the Office)

In the matter of

(Gist of purpose of petition and legal provision)

And In the matter of:

(Name and full address of the Petitioners/ applicant and names and full address of the respondents)

Affidavit

I, Sh./Smt. _____, (S/o, W/o, D/o) Sh. _____ (aged _____ years), (occupation) _____, residing at _____, the deponent named above do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That the deponent is the Managing Director / Director who is authorized as per the resolution of the company dated ____ (In case the Petitioner is a Company) and is acquainted with the facts deposed to below.

2. I, the deponent named above do hereby verify that the contents of the

paragraph Nos. 1 of the affidavit and those of the paragraph No.

..... of the accompanying petition are true to my personal knowledge and those of the paragraph Nos. of the accompanying petition are based on the perusal of records and those of the paragraph Nos. of the accompanying petition are based on information received and those of the paragraph Nos. of the accompanying petition are based on the legal advice which I believe to be true and verify that no part of this affidavit is false and nothing material has been concealed.

(Deponent)

I, _____ Advocate, _____, do hereby declare that the person making this affidavit is known to me through the perusal of records and I am satisfied that he is the same person alleging to be deponent himself.

Advocate

Solemnly affirmed before me on this day of 200 at a.m. / p.m. by the deponent who has been identified by the aforesaid Advocate.

I have satisfied myself by examining the deponent that he understood the

contents of the affidavit which has been read over and explained to him. He has also been explained about section 193 of Indian Penal Code that whoever intentionally gives false evidence in any of the proceedings of the Commission or fabricates evidence for purpose of being used in any of the proceedings shall be liable for punishment as per law.

Form JERC-4

Annexure IV

(See Regulation 15 of Conduct of Business Regulations)

BEFORE THE JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES

IN THE MATTER OF

Petition No.

..... Petitioner(s)

V/s

..... Respondent(s)

Memorandum of Appearance

I,, practicing/working as having been authorized by (furnish the particulars of the person authorizing), hereby enter appearance on behalf of and undertake to plead and act for him/it in all matters in the aforesaid case.

Place:

Date:

Signature & Designation

Address for CorrespondenceAnnexure V

Form JERC-5

(See Regulation 15 of Conduct of Business Regulations)

Joint Electricity Regulatory Commission for the State of

Goa and Union Territories

Petitions/Applications Register

Sl. No.	Day No.	Date of Filing	Petition/ Application No.	Name & address of the Petitioner(s)	Name & address of the Respondent (s)	Subject matter of the petition/ application	Date of admission	Particulars of interim orders passed, if any	Date and particulars of final order	Details of appeal, if any filed	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Annexure 18

Form JERC-6

(See Regulation 15 of Conduct of Business Regulations)

Joint Electricity Regulatory Commission
for the State of Goa and Union Territories

No.

Subject: Petition under Section ____ of Electricity Act of 2003 in the matter of.....

Dear Sir,

I am directed to refer to your petition/application dated..... Filed on..... on the above subject and to inform you that on scrutiny, the following defects have been pointed out:

1. The petition is not in the form (JERC-2) prescribed in Chapter II of the JERC, Conduct of Business Regulations.
2. The names, descriptions and addresses of the parties have not been furnished in the cause title.
3. The following necessary parties have not been impleaded:
 - a.
 - b.
 - c.
4. The petition has not been duly signed.
5. The petition has not been supported by an affidavit.
6. The affidavit is not on the form prescribed in Chapter II of the JERC comprehensive conduct of Business Regulations.
7. The affidavit has not been signed and sworn before the competent authority.
8. Six copies of the petition have not been filed.
9. The copies of the petitions are not complete in all respects.
10. The copies of the documents are not legible and duly attested.
11. Translation, in English/Hindi/any other language recognized by the Commission, of the documents and other material, contained in a language other than English/Hindi/any other language recognized by the Commission, has not been filed.
12. Authenticity of the translation of the documents, in English/Hindi/any other language recognized by the Commission, has not been furnished.
13. The Vakalatnama/letter of authorization has not been filed.
14. The Vakalatnama is not properly executed and necessary court fee has not been paid.
15. The prescribed fee for the petition/application has not been paid.
16. The index of documents has not been filed.
17. The pagination of the documents has not been done properly.
- 18.
19.

You are requested to rectify the defects within three weeks of issue of this letter, failing which the petition shall be deemed to have been rejected.

Yours faithfully,

(Deputy Officer)

Annexure VII**Form JERC-7**

(Regulation 24 of the Conduct of Business Regulations)

**BEFORE THE JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES**

IN THE MATTER OF

Petition No.

..... Petitioner(s)

V/s

..... Respondent(s)

Application for Inspection of Documents/Records

I hereby apply for grant of permission to inspect the documents/records in the above case. The details are as follows:

1. Name & address of the person
seeking permission
2. Whether he is party to the case or
he is the authorized representative
of any Party. Furnish necessary particulars
3. Details of papers/documents

sought to be inspected

4. Purpose for seeking inspection
5. Date and duration of the inspection
sought
6. The amount of fee payable and the
mode of payment

Place: _____

Date: _____

Signature

Office use

Granted inspection on _____ / Rejected

**Secretary,
Joint Electricity Regulatory Commission
For Goa & Union Territories**

Annexure VIII**Form JERC-8***(See Regulation 24 of Conduct of Business Regulations)***Joint Electricity Regulatory Commission for the State of
Goa and Union Territories****Register for Inspection of Records**

Sl. No.	Name of the applicant	Date of application	Records to be inspected	Purpose of inspection	Amount paid with particulars of DD/Pay Order No. Date Bank	Date on which inspected	Official in whose presence the record inspected	Signature of all person inspecting the records	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Form JERC-8

(See Regulation 25 of Conduct of Business Regulations)

**BEFORE THE JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES**

IN THE MATTER OF

Petition No.

..... Petitioner(s)

V/s

..... Respondent(s)

Application for grant of certified copy

1. **Name & address of applicant**
2. **Whether the applicant is party
to the case**
3. **Whether the case is pending or
disposed of**
4. **Description with date of the documents
of which copy is applied for**
5. **No. of copies required**

6. Amount of fee remitted and

mode of payment

Signature

Office use

Granted/Rejected

Additional Copying fee

Payable/Paid and details thereof

Secretary,
Joint Electricity Regulatory Commission
For Goa & Union Territories

Annexure X

Form JERC-10

(See Regulation 25 of Conduct of Business Regulations)

Joint Electricity Regulatory Commission for the State of
Goa and Union Territories

Register of Copy Applications

Sl. No	Date of application	Name of the applicant	Petition No.	Particulars of the document whose copy is required	Amount received	Particulars of DD/Pay Order No., Date & Bank	No. of pages	Addl. Amount & particulars of DD/Pay Order	Date of preparation	Date of delivery	Signature of the person receiving	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Secretary,
Joint Electricity Regulatory Commission
For Goa & Union Territories